राष्ट्रीय संस्करण



तीसरे दौर में पहुंचे शरत कमल
>> 12

वर्ष 5 अंक 47

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 27 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

जागरण विशेष

बिहार का एक गांव जो 43 बार बाढ़ में बहा और बसा



शिवहर: यह कहानी नरकटिया के ग्रामीणों की जिजीविषा और सबकुछ खोकर फिर से खड़ा होने की जीवटता की है। बागमती की बाढ़ से उजड़ना उनकी नियति है तो पुरुषार्थ से फिर गांव को आबाद करना कर्म है। बीते 87 साल में 43 बार यह गांव उजड़ कर बस चुका है। (पेज-10)

मीरा की जय-जय

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: टोक्यो ओलिंपिक में भारत के लिए अब तक एकमात्र पदक जीतने वाली महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू सोमवार को जैसे ही राजधानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरीं वैसे ही भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। हालांकि, इस दौरान हवाई अड्डे में अफरा-तफरी भी मच गई और कोविड-19 से बचाव के लिए लागू किए शारीरिक दूरी के नियमों की पूरी तरह अनदेखी हुई।

चानू को सुरक्षाकर्मियों ने घेर रखा था। वहां मौजूद सभी लोग भारत माता की जय, मीराबाई चानू जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। इसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। चानू पिछले पांच वर्षों से अपने खेल पर ध्यान देने के लिए परिवार से दूर रहीं हैं। मणिपुर की इस खिलाड़ी ने ओलिंपिक की भारोत्तोलन स्पर्धा के 49 किग्रा वर्ग में कुल 202 किग्रा (87 किग्रा+115 किग्रा) भार उठाकर शनिवार को रजत पदक हासिल किया था। संबंधित खबरें >> पेज 12

TOKYO 2020

देश लौटने पर भारत माता की जय के नारों से हुआ ओलिंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई का भव्य स्वागत

" इतने प्यार और समर्थन के बीच यहां वापस आकर खुशी हो रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद।
-मीराबाई चानू, रजत पदक विजेता भारोत्तोलक



नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (बाएं से चौथे), किरण रिजिजू (बाएं से दूसरे) और निशीथ प्रमाणिक (दाएं) ने टोक्यो ओलिंपिक में रजत पदक विजेता साइखोम मीराबाई चानू का अभिनंदन किया। इस मौके पर चानू के कोच विजय शर्मा भी मौजूद रहे। प्रेट्र

21 साल बाद देश को भारोत्तोलन में दिलाया है ओलिंपिक पदक

मणिपुर सरकार एक करोड़ देने के साथ बनाएगी एसीपी

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने सोमवार को घोषणा कि मीराबाई चानू को राज्य पुलिस में अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। साथ ही उन्हें एक करोड़ रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। हालांकि, चानू अभी रेलवे में टिकट कलेक्टर हैं। रेलवे ने उनका काफी लंबे से साथ दिया है। अब यह देखना होगा कि वह रेलवे छोड़कर अपने राज्य के मुख्यमंत्री का प्रस्ताव स्वीकार करती हैं या नहीं।

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

मनमाने तरीके से 95 फीसद से अधिक अंक नहीं दे सकेंगे स्कूल

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबंधित स्कूल 10वीं-12वीं के छात्रों को 95 फीसद से ज्यादा अंक नहीं दे सकेंगे। बोर्ड ने कहा है कि रेफरेंस ईयर में जितने छात्रों को 95 फीसद से ज्यादा अंक मिले थे, इस वर्ष भी उतने ही छात्रों को इतने अंक मिल सकते हैं। सीबीएसई ने नए निर्देश जारी किए हैं, ताकि स्कूल प्रबंधन मनमाने तरीके से अपने छात्रों को फायदा न पहुंचा सकें।

राजनीति ▸ पृष्ठ 4

गहलोत मंत्रिमंडल से बाहर होंगे आधा दर्जन मंत्री

जयपुर : कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान में सत्ता और संगठन में फेरबदल की कार्ययोजना लगभग तैयार कर ली है। इसके तहत मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ ही मानसून सत्र से पहले विधानसभा उपाध्यक्ष और संसदीय सचिव बनाए जाएंगे। पांच से छह मंत्रियों को संसदीय सचिव बनाए जाने की संभावना है तो आधा दर्जन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है।

राष्ट्रीय फलक ▸ पृष्ठ 7

अलीगढ़ में बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश, 16 गिरफ्तार

अलीगढ़ : पुलिस ने अंतरजनपदीय बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है। गिरोह के 16 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें नौ महिलाएं भी शामिल हैं। इनके पास से पांच बच्चे भी बरामद किए गए हैं। इनमें तीन बच्चे अलीगढ़ व दो बच्चे गाजियाबाद से चोरी किए गए थे। ये झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को निशाना बनाते थे। दो से पांच लाख रुपये में बच्चे का सौदा करते थे।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 11

गुलाम कश्मीर के चुनाव में धांधली, विपक्ष ने कहा, लेंगे भारत की मदद

मुजफ्फराबाद: गुलाम कश्मीर में इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने हिंसा, धांधली और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर भले ही चुनाव जीत लिया है, लेकिन विपक्षी इस जीत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन के नेता चौधरी मुहम्मद इस्माइल गुज्जर ने तो यहां तक कहा है कि धांधली की जांच नहीं हुई तो वह भारत की मदद लेने से भी गुरेज नहीं करेंगे।

जासूसी को लेकर संसद में सियासत चरम पर

- लगातार पांचवें दिन जबर्दस्त हंगामा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच और तत्काल बहस की मांग पर अड़ा विपक्ष
- लोकसभा में शोर-शराबे के बीच सरकार ने पारित कराए दो विधेयक, गतिरोध का हल निकालने को विपक्षी नेताओं से शुरू की चर्चा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेगासस फोन जासूसी विवाद को लेकर संसद में चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार पांचवें दिन जबरदस्त हंगामा किया। जासूसी कांड की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच के साथ ही विपक्ष इस मामले पर तत्काल बहस की मांग पर अड़ा है। जबकि जासूसी के आरोपों से इन्कार कर रही सरकार विपक्ष के हंगामे के बावजूद इस मुद्दे पर दबाव में आने को तैयार नहीं है। हालांकि संसद का कामकाज बाधित होने के मद्देनजर सरकार ने सोमवार को विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क साधकर गतिरोध का हल निकालने की कोशिश शुरू की।

पेगासस जासूसी विवाद पर सरकार को घेरने में विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में सोमवार को एकजुटता और आक्रामकता दिखाई। इसके लिए विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर इस मामले को उठाया और हंगामा कर बार-बार सदन को स्थगित कराया। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक आदि के नेताओं के कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्पीकर ओम बिरला ने खारिज कर दिया। साथ ही विपक्षी हंगामे के बीच करीब 20 मिनट तक प्रश्नकाल भी चलाया, लेकिन हंगामा थमता नहीं देख सदन को दो बजे तक स्थगित कर दिया। इस बीच, स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे और नारेबाजी को लेकर एतराज जताते हुए कहा कि सरकार चर्चा कराने को तैयार है तो फिर हंगामे का कोई औचित्य नहीं है। दो बजे के बाद भी सदन दो बार हंगामे की वजह से ठप हुआ और तीन बजे जब चौथी बार सदन शुरू हुआ तो भारी शोर-शराबे के बीच ही सरकार ने दो विधेयक पारित करा लिए और फिर सदन पूरे दिन के लिए स्थगित हो गया।

राज्यसभा में भी जासूसी प्रकरण पर विपक्ष की आक्रामकता इसी तरह जारी रही। सभापति वेंकैया नायडू ने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय और द्रमुक के त्रिची शिवा समेत 12 सदस्यों के पेगासस जासूसी विवाद पर तत्काल चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया। इसको लेकर विपक्षी सांसद वेल में जाकर हंगामा करने लगे और खड़गे व कुछ अन्य विपक्षी सदस्य सरकार पर राजनेताओं और प्रमुख लोगों के फोन की जासूसी करने का आरोप लगाने लगे। हंगामे और नारेबाजी के बीच सभापति ने सदन को पहले 12 बजे तक स्थगित किया। जब 12 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ तब भी विपक्षी सदस्यों का शोर-शराबा नहीं रुका और चार बार के स्थगन के बाद आखिरकार चार बजे राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई।

इसके बाद गतिरोध का रास्ता निकालने के लिए सरकार की ओर से बातचीत की पहल की गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लोकसभा में कांग्रेस के रणनीतिकारों में शामिल मनीष तिवारी और राकांपा नेता सुप्रिया सुले समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से हल निकालने के विकल्पों पर बात की। 'प्रेट्र' के मुताबिक, इससे पहले राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि सदन के कामकाज को लेकर उन्होंने नेता विपक्ष और प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं से संपर्क किया था, लेकिन उनमें सहमति नहीं है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही इस मामले में बयान दे चुके हैं।
(संबंधित खबरें पेज-3 पर)



पेगासस जासूसी कांड समेत विभिन्न मुद्दों पर सोमवार को रास में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। प्रेट्र

पेगासस जासूसी विवाद की पड़ताल के लिए ममता सरकार ने गठित किया जांच आयोग

कोलकाता : कथित पेगासस जासूसी मामले में जारी सियासत के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाया है। तृणमूल प्रमुख ने इजराइली स्पाइवेयर के जरिये नेताओं, अफसरों और पत्रकारों की जासूसी कराए जाने आरोपों की पड़ताल के लिए दो सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की विशेष बैठक में जांच आयोग (पैनल) गठित करने का फैसला लिया गया, जिसके सदस्य सुप्रीम कोर्ट एवं कलकत्ता हाई कोर्ट के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। (पेज-3)

ट्रैक्टर चलाकर संसद जा रहे राहुल को थाने ले गई पुलिस

नई दिल्ली: कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन की ओर निकले। पुलिस रास्ते में ही रोककर थाने ले गई। वहां से राहुल को जाने दिया गया, लेकिन रणदीप सुरजेवाला व अन्य नेता हिरासत में रहे। (पेज-6)



कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सोमवार को ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन जाते समय रास्ते में रोक लिए गए। प्रेट्र

झूठ के सहारे राजनीतिक वजूद बचाने की कोशिश में राहुल: तोमर

नई दिल्ली : कृषि सुधार कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर पर संसद भवन आने और इन कानूनों को किसान विरोधी बताने पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। तोमर ने कहा कि राहुल गांधी पर झूठ के सहारे राजनीतिक वजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। (पेज-6)

मिजोरम और असम सीमा विवाद भड़का, छह पुलिसवालों की मौत

- गृह मंत्री शाह ने दोनों राज्यों से किया शांति व सहमतिपूर्ण समाधान तलाशने का अनुरोध
- दोनों मुख्यमंत्रियों ने हिंसा के लिए एक-दूसरे की पुलिस को ठहराया जिम्मेदार
- हिंसा में असम पुलिस के एसपी और 50 पुलिस कर्मी घायल भी हुए

गुवाहाटी, प्रेट्र: असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया है। इसमें सोमवार को असम के छह पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए। इस दौरान दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों में भी वाकयुद्ध छिड़ गया। दोनों ने एक-दूसरे की पुलिस को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की। इसके बाद शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा व मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा से अलग-अलग बात की और उनसे विवादित सीमा पर शांति सुनिश्चित करने और सहमतिपूर्ण समाधान तलाशने का अनुरोध किया।

असम में बराक घाटी के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिले मिजोरम के आइजल, कोलासिब और ममित जिलों के साथ 164 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। एक क्षेत्रीय विवाद के बाद पिछले साल अगस्त और इस साल फरवरी में भी अंतरराज्यीय सीमा पर झड़पें हुई थीं।

असम के मुख्यमंत्री सरमा ने सोमवार को ट्विटर पर घोषणा की कि कछार जिले में अंतरराज्यीय सीमा पर मिजोरम से उपद्रवियों द्वारा की गई फायरिंग में असम पुलिस के छह कर्मी राज्य की संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जबकि, असम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फायरिंग और पत्थरबाजी में 50 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं जिनमें कछार के पुलिस अधीक्षक निंबाल्कर वैभव भी शामिल हैं। उनकी टांग में गोली लगी है। उन्होंने कहा कि दोनों ओर के अधिकारी जब मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे थे, तभी दोनों ओर से उपद्रवियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी।

दूसरी ओर, मिजोरम के गृह मंत्री लालचामलियाना ने एक बयान में कहा कि असम पुलिस के 200 कर्मियों द्वारा सीआरपीएफ कर्मियों के ड्यूटी पोस्ट को जबरन पार करने और आगजनी, निहत्थे लोगों पर हमले और फायरिंग करने में शामिल होने पर मिजोरम पुलिस ने फायरिंग कर इसका जवाब दिया। इससे पहले जोरमथांगा ने असम पुलिस पर लाठीचार्ज करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने का आरोप लगाया था। वहीं, असम पुलिस का दावा था कि बड़ी संख्या में मिजोरम के उपद्रवी पथराव में शामिल थे और उन्होंने असम सरकार के अधिकारियों पर हमला किया था। मिजोरम के आइजी (उत्तरी रेंज) लालबियकथांगा खिआंगते का कहना था कि रविवार रात करीब 11.30 बजे समस्या ग्रस्त इलाके में ऐतलांग स्ट्रीम के पास खेत में खाली पड़ीं कम से कम आठ झोपड़ियों को आग लगा दी गई थी। ये झोपड़ियां असम सीमा से लगते वैरेंगते गांव के किसानों की थीं।

बहरहाल, मामले को तूल पकड़ता देख शाम को शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अलग-अलग बात की और उनसे अंतरराज्यीय सीमा पर शांति बनाए रखने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों को सीमा विवाद का आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए कहा। दोनों मुख्यमंत्रियों ने शाह को आश्वस्त किया कि शांति सुनिश्चित करने और सहमति से सीमा मसले का समाधान करने के जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसके तुरंत बाद मिजोरम के गृह मंत्री लालचामलियाना ने एक बयान जारी कर कहा कि शाह के हस्तक्षेप के बाद असम पुलिस को वापस बुला लिया गया है और ड्यूटी पोस्ट सीआरपीएफ कर्मियों को सौंप दी गई है।



असम-मिजोरम सीमा पर असम पुलिस और मिजोरम के उपद्रवियों के बीच हिंसक झड़प हुई। एएनआइ

पुराना है असम-मिजोरम सीमा विवाद पेज>>10

अब दुनिया भर में विजय माल्या की संपत्तियां होंगी जब्त



लंदन: ब्रिटिश हाई कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय बैंकों के लिए दुनियाभर में फैली उसकी संपत्तियों को जब्त करने का रास्ता आसान हो गया है। माल्या ने अब बंद हो चुकी अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए भारतीय बैंकों से नौ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज लिया था और जब कंपनी डूबी तो कर्ज चुकाए बिना ही वह लंदन भाग गया। माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ ने ब्रिटिश कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। (पेज-11)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से येदियुरप्पा ने दिया इस्तीफा

नेतृत्व परिवर्तन
- अपने दो साल के कार्यकाल को बताया अग्निपरीक्षा
- पार्टी की ओर से तय नए मुख्यमंत्री को पूरी मदद का दिया भरोसा



बेंगलुरु में सोमवार को विधानसभा में अपनी सरकार के दो साल पूरे होने पर कार्यक्रम के दौरान बीएस येदियुरप्पा रो पड़े। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे को लेकर संशय आखिरकार खत्म हो गया। अपनी सरकार के दो साल पूरे होने के दिन सोमवार को ही येदियुरप्पा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को इस्तीफा सौंप दिया। बहुत जल्द वहां नए मुख्यमंत्री का एलान हो जाएगा। नया मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के लिंगायत समुदाय से होगा या कोई और इसे लेकर संशय है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि प्रशासनिक क्षमता और साफ छवि को महत्व मिलेगा।

रविवार शाम तक येदियुरप्पा ने कहा था कि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व की ओर से इस्तीफे का आदेश नहीं आया है। बताया जा रहा है कि देर रात उन्हें संदेश मिला कि वह कार्ययोजना के अनुसार बढ़ें। लिहाजा सोमवार दोपहर येदियुरप्पा भावुक भी हुए। अपने कार्यकाल को अग्निपरीक्षा बताते हुए कहा, इस दौरान उन्हें लंबे समय तक बिना कैबिनेट सहयोगियों के काम करना पड़ा। फिर बाढ़ की स्थिति बनी। इस दौरान पूरी ताकत से जनता के लिए काम किया। उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। यह भी याद दिलाया कि प्रदेश में पार्टी को यहां तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने भावी सीएम के बारे में बात नहीं की और कहा, पार्टी जिसे भी जनता की सेवा का मौका देगी, वह उसका सहयोग करेंगे।

नए सीएम के लिए ये नाम चर्चा में

अगर लिंगायत समुदाय से मुख्यमंत्री चुना गया तो गृह मंत्री बासवराज बोम्मई समेत अरविंद हेगड़े और मुरगेश निरानी दौड़ में आगे हैं। ब्राह्मणों में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के नाम प्रमुख हैं।

एक-दो दिन में फैसले की उम्मीद

पिछले दिनों भाजपा की ओर से दूसरी अहम जाति वोक्कालिगा को भी साधने की कोशिश होती रही, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा करने से बचने की सलाह देता है। दरअसल लिंगायत और वोक्कालिगा के बीच बहुत मधुर सामंजस्य नहीं रहा है। माना जा रहा है कि मंगलवार- बुधवार तक नए मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, येदियुरप्पा को नेतृत्व ने भरोसा दिया है कि उनके पुत्र को उचित स्थान मिलेगा। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, लिंगायत समुदाय से उम्मीदवार चुने जाने की प्राथमिकता होगी, क्योंकि 17 फीसद आबादी वाले लिंगायतों का विस की 30 फीसद सीटों पर प्रभाव है। भाजपा इसमें सेंध नहीं चाहेगी। ऐसे नाम को भी खारिज किया जा रहा है, जिससे येदियुरप्पा का टकराव रहा हो। भाजपा प्रयोग करने में विश्वास रखती है। इस नाते अलग जाति के सीएम को भी खारिज नहीं किया जा रहा है।

कोरोना से बचाव

किशोर व बीमार बच्चों को पहले लग सकती है वैक्सीन

एम्स के डाक्टर वयस्कों की तरह बच्चों के लिए वरीयता तय करने का दे रहे सुझाव, बच्चों के टीकाकरण अभियान की तैयारियां जोरों पर, सितंबर में शुरू होने की उम्मीद

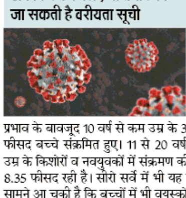
रणविजय सिंह, नई दिल्ली

कोरोना वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर बच्चों के टीकाकरण की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। दो से 18 वर्ष के बच्चों पर कोवैक्सीन टीके के परीक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सितंबर में बच्चों के टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डाक्टर वयस्कों की तरह बच्चों की भी बीमारियों व उम्र के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर टीकाकरण की सलाह दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो 12 से 18 वर्ष के बच्चों के साथ मोटापे व अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित बच्चों को वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता दी जा सकती है।

एम्स के डाक्टरों का तर्क है कि देश में बच्चों में कोविड का संक्रमण करीब 12 फीसद है। इसमें भी छोटे बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। दूसरी लहर में डेल्टा वायरस के घातक प्रभाव के बावजूद 10 वर्ष से कम उम्र के 3.33 फीसद बच्चे संक्रमित हुए। 11 से 20 वर्ष की उम्र के किशोरों व नवयुवकों में संक्रमण की दर 8.35 फीसद रही है। सीरो सर्वे में भी यह बात सामने आ चुकी है कि बच्चों में भी वयस्कों की तरह ही कोविड एंटीबाडी पाई गई है। लिहाजा, छोटे बच्चे भी संक्रमित तो हुए, लेकिन वे बीमार नहीं हुए। इसलिए छोटे बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं है।

कोवैक्सीन के ट्रायल में भी पहले 12 से 18 वर्ष के बच्चों को और फिर छह से 12 वर्ष के बच्चों को टीका लगाया गया था। इसके बाद दो से छह साल की उम्र के बच्चों की बारी आई। एम्स के पीडियाट्रिक विभाग के प्रोफेसर डा. एसके काबरा ने कहा कि वयस्कों की तरह बच्चों को भी वरीयता सूची के आधार पर टीका लगेगा। 12 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों पर टीके के ट्रायल का डाटा भी पहले आने की उम्मीद है, जिससे पता चल सकेगा कि टीका कितना सुरक्षित और प्रभावी है। इसलिए पहले 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को टीका लगेगा।

वयस्कों की तरह बच्चों के टीकाकरण के लिए भी तैयार की जा सकती है वरीयता सूची



12 साल से अधिक उम्र के बच्चे मोटापे से ज्यादा पीड़ित

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की निदेशक प्रोफेसर डा. सुनीला गर्ग ने कहा कि 12 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों में मोटापा अधिक होता है। खास तौर पर शहरी क्षेत्र के बच्चे मोटापे से अधिक पीड़ित हैं। इसलिए पहले इस आयु वर्ग को टीका लगना चाहिए। विदेश में भी यही फार्मूला अपनाया जा रहा है।

उम्र के अनुसार कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या

उम्र	संक्रमण दर (फीसद में)
0-10	3.13
11-20	8.67
21-30	21.47
31-40	21.80
41-50	17.18
51-60	14.14
61-70	8.79
71 साल से ज्यादा	4.68

पहली व दूसरी लहर में कोरोना से संक्रमित हुए बच्चे (फीसद में)

उम्र	पहली लहर	दूसरी लहर
0-10	3.88	3.33
11-20	7.87	8.35
कुल	11.75	11.68

39 नए मामले सोमवार को राजधानी में कोरोना संक्रमण के सामने आए। वहीं 80 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण एक मरीज की मौत हुई।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 27 जुलाई, 2021

छूट के पहले ही दिन मेट्रो में टूटे कोरोना के नियम

कार्रवाई ▶ 432 यात्री ट्रेन से उतारे गए, 159 लोगों पर लगाया गया जुर्माना

स्टेशनों के बाहर यात्रियों की दिखी लंबी कतारें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

इस साल महामारी फैलने के बाद पहली बार सोमवार से बैठने की पूरी क्षमता के साथ मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया। हालांकि, पहले दिन व्यस्त समय में स्टेशनों के बाहर से लेकर मेट्रो ट्रेनों के अंदर तक अव्यवस्था दिखी। स्टेशन के बाहर यात्रियों को 30 मिनट से लेकर एक घंटे तक लाइन में खड़े होना पड़ा। वहीं, सुबह मेट्रो के अंदर भी काफी भीड़ रही और यात्रियों ने खड़े होकर सफर किया। इससे शारीरिक दूरी के नियम धरे रहे गए। ऐसे में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) का कहना है कि परिचालन के नए दिशा-निर्देश से सभी यात्री पूरी तरह अवगत नहीं थे। इसलिए यात्रियों ने खड़े होकर सफर किए। नए दिशा निर्देश के मुताबिक एक सीट छोड़कर बैठने की बाध्यता खत्म कर दी गई है और सभी सीटों पर यात्री बैठकर सफर कर सकते हैं। फिर भी 20 फीसद क्षमता के साथ ही मेट्रो का परिचालन होना है, क्योंकि मेट्रो में अभी खड़े होकर सफर करने का प्रविधान नहीं है। मेट्रो के एक कोच में करीब 300 यात्रियों के सफर करने की क्षमता होती है, लेकिन करीब 50 यात्रियों के ही बैठने की सुविधा होती है।

खड़े होकर सफर करने पर फ्लाइंग स्क्वाड करेगी कार्रवाई : डीएमआरसी ने यात्रियों से खड़े होकर सफर नहीं करने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा कि फ्लाइंग स्क्वाड की टीम औचक जांच करेगी ताकि मेट्रो में भीड़ न होने पाए। इसके अलावा खड़े होकर सफर करने वाले यात्रियों के खिलाफ फ्लाइंग स्क्वाड टीम जुर्माना करेगी। सोमवार को खड़े होकर सफर करने पर नौ फ्लाइंग स्क्वाड टीमों ने 432 यात्रियों को ट्रेन से उतार दिए। वहीं 159 यात्रियों पर 200-200 रुपये जुर्माना लगाया गया।

बहरहाल एक दिन पहले तक मेट्रो में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था थी। इसके लिए सभी मेट्रो ट्रेनों में हर एक सीट के बाद स्टिकर चिपकाया गया है। स्टिकर लगे सीट पर यात्रियों को नहीं बैठने का निर्देश लिखा हुआ है। बैठने की पूरी क्षमता के साथ मेट्रो का परिचालन तो शुरू हो गया, लेकिन अभी ये स्टिकर हटाए नहीं जा सके हैं। इससे कई मेट्रो में यात्री एक सीट छोड़कर बैठे भी नजर आए, लेकिन उसी ट्रेन में कई यात्रियों ने खड़े होकर सफर किया। डीएमआरसी का कहना है कि मेट्रो की सीटों पर लगे स्टिकर हटा दिए जाएंगे।



राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में प्रवेश के लिए कनाट प्लेस में लगी यात्रियों की लंबी कतार। जागरण

स्टेशनों के बाहर लगी यात्रियों की लंबी कतार

मेट्रो में भीड़ नियंत्रित करने के लिए ज्यादातर स्टेशनों पर सिर्फ एक गेट ही खोला जा रहा है। कुछ इंटरचेंज स्टेशनों के अलावा 16 स्टेशनों पर दो-दो गेट खुले रहे। इस तरह 253 स्टेशनों पर सिर्फ 276 गेट ही खुले रहे। इससे सुबह व्यस्त समय में ज्यादातर स्टेशनों के बाहर यात्रियों की लंबी लाइनें लग गईं। यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर फोटो पोस्ट कर एक किलोमीटर तक लाइन लगने की डीएमआरसी से शिकायतें कीं। यात्रियों ने स्टेशनों पर अतिरिक्त गेट खोलने व मेट्रो में शारीरिक दूरी के नियम के साथ यात्रियों के खड़े होकर सफर करने का प्रविधान करने की भी मांग की।



नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खड़े होकर यात्रा करते लोग। सौ.यात्री

भूकंप के हल्के झटके से मेट्रो का परिचालन थोड़ी देर प्रभावित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भूकंप के हल्के झटके के कारण सोमवार सुबह दिल्ली मेट्रो का परिचालन थोड़ी देर के लिए प्रभावित हुआ। इस दौरान कई स्टेशनों पर मेट्रो ट्रेनें रोक दी गईं और सुरक्षा कारणों से यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। हालांकि, थोड़ी देर बाद ही दोबारा मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया, लेकिन परिचालन सामान्य होने में आधा घंटा से अधिक समय लगा।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने ट्वीट कर कहा कि सुबह 6.42 बजे मेट्रो में हल्का कंपन महसूस किया गया। ऐसी स्थिति में तय मानकों के अनुसार तुरंत ट्रेनों की गति कम कर दी गई और अगले स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंचने पर ट्रेनों को रोक दिया गया। इससे कुछ देर के लिए मेट्रो का परिचालन रुक गया।

प्रीतम सिंह नामक यात्री ने ट्वीट कर कहा कि ग्रेटर कैलाश स्टेशन पर 12 मिनट मेट्रो रुकी रही। सभी यात्रियों को ट्रेन से बाहर उतारने के बाद मेट्रो खाली ही रवाना हो गई। आदित्य नाम के एक अन्य यात्री ने भी ट्वीट कर कहा कि ब्लू लाइन पर भी मेट्रो ठीक से नहीं चल रही थी। इससे यात्रा में विलंब हुआ। डीएमआरसी का कहना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कारिडोर पर मेट्रो की गति कम कर दी गई थी। बाद में परिचालन सामान्य हो गया।

इधर, दिल्ली में भूकंप के झटके आम लोगों ने महसूस नहीं किए। इसे लेकर डीएमआरसी का कहना है कि भूकंप आने पर कंपन मापने के लिए मेट्रो कारिडोर के कई स्टेशनों पर सिस्मोग्राफ लगे हुए हैं। इसलिए हल्का झटका महसूस होने पर भी तुरंत अलर्ट जारी हो जाता है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेट्रो का परिचालन रोक दिया जाता है।

भूकंप आने से राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र का इन्कार

डीएमआरसी का दावा है कि भूकंप के चलते मेट्रो का परिचालन प्रभावित हुआ, लेकिन राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दिल्ली एनसीआर में सोमवार को किसी भी तरह का भूकंप आने से साफ इन्कार किया है। केंद्र के कार्यालय प्रमुख डा. जे एल गौतम ने कहा कि डीएमआरसी को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। हकीकत में स्थानीय स्तर पर कोई भूकंप आया ही नहीं। केंद्र की वेबसाइट पर भी सोमवार को केवल चार भूकंप की जानकारी थी, जो क्रमशः तेलंगाना, मणिपुर, पाकिस्तान और चीन में आए थे।

न्यूज गैलरी

फैकल्टी के लिए खुला जेएनयू, पाबंदियां रहेंगी जारी

नई दिल्ली : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में पाबंदियां नौ अगस्त तक बढ़ा दी गई हैं। विवि प्रशासन ने एक परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों के तहत सेंट्रल लाइब्रेरी अगले आदेश तक बंद रहेगी। इसके अलावा फैकल्टी के लिए वर्क फ्राम होम सुविधा खत्म कर दी गई है। सभी अधिकारी व कर्मचारी नियमित रूप से दफ्तर आएंगे। जेएनयू ने परिसर में रह रहे लोगों से गुजारिश की है कि वे बेवजह नहीं घूमें। (जासं)

47,996 निर्माण श्रमिकों को दिए पांच-पांच हजार रुपये

नई दिल्ली : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निर्देश पर दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने 47,996 निर्माण श्रमिकों को पांच-पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद दी है। यह मदद कोरोना राहत राशि के रूप में उन निर्माण श्रमिकों को दी गई है, जिनके आवेदन 28 मई से 18 जुलाई 2021 के बीच स्वीकृत किए गए थे। इससे पहले अप्रैल में दो लाख 16 हजार 602 निर्माण श्रमिकों को कोरोना राहत राशि के रूप में पांच-पांच हजार रुपये दिए गए थे। (राब्यू)

भारतीय विमानों का कोड बदलने की मांग

नई दिल्ली : आजादी के कई दशक बीतने के बाद भी विमानन जगत भारत की पहचान 'वायसराय टेरिटरी' के तौर पर होती है। विमान की पहचान सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गनाइजेशन (आइसीएओ) सभी देशों को एक कोड देता है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत को आइसीएओ की तरफ से 'वीटी' यानी 'वायसराय टेरिटरी' कोड दिया गया था, जो आज तक बरकरार है। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखे पत्र में इस कोड को बदलवाने का अनुरोध किया है। (राब्यू)

निगम पार्षद भगत सिंह टोकस फोन पर मिली धमकी

नई दिल्ली : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के साउथ जोन में शुक्रवार को मुनिरका वार्ड के तहत आने वाले मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम करने का प्रस्ताव रखने वाले निगम पार्षद भगत सिंह टोकस को फोन पर धमकी मिली है। आरोपित ने काल करके टोकस से कहा कि अगर गांव के मुगलकालीन नाम से आपत्ति है तो खुद इस्लाम स्वीकार कर लें, लेकिन गांव का नाम बदलने के बारे में नहीं सोचें। (जासं)

दिल्ली में सर्किल रेट का होगा पुनर्मूल्यांकन, समिति गठित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली में आने वाले दिनों में सर्किल रेट में स्थायी रूप से बदलाव हो सकता है। राजस्व विभाग ने पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद नए सर्किल रेट तय किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने इस बारे में स्पष्ट नहीं किया है कि सर्किल रेट घटेंगे या बढ़ेंगे। मगर जानकार मान रहे हैं कि यह कवायद सर्किल रेट कम करने के लिए ही चल रही है।

राजस्व विभाग ने सभी 11 जिलों को अपने यहां का पुनर्मूल्यांकन कर नई दरें प्रस्तावित करने के लिए कहा है। इस मामले में राज्य स्तर पर भी समिति का गठन किया गया है, जो नगर निगम, डीडीए आदि से प्रस्तावित दरों के बारे में बात कर रही है। जिला स्तर पर भी कवायद तेज हो गई है। पूर्वी जिला प्रशासन ने 25 जुलाई को सार्वजनिक सूचना जारी कर लोगों की राय मांगी है। इसमें 31 जुलाई तक सुझाव देने के लिए कहा गया है। लोगों से दिल्ली में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि संपत्तियों के सर्किल रेट के बारे में सुझाव मांगे गए हैं। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभी यह कहना संभव नहीं है कि सर्किल रेट घटेंगे या बढ़ेंगे। इसके बारे में समिति फैसला लेगी। इसके लिए सभी से सुझाव लिए जा रहे हैं। वहीं इस बारे में जानकारों का कहना है कि दिल्ली में पिछले सालों में संपत्ति की खरीद फरोख्त में कमी आई है। कोरोना काल में लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आर्थिक रूप से लोग परेशान हैं, इसे देखते हुए सर्किल रेट में 30 सितंबर के आगे भी कमी जारी रखी जा सकती है।

दिल्ली सरकार ने फरवरी में संपत्ति पर सर्किल रेट में छह माह के लिए 20 फीसद तक कमी कर दी थी। इस बारे में दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल की अनुमति के बाद राजस्व विभाग ने गत 28 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी थी। अधिसूचना के तहत यह सुविधा 30 सितंबर तक लागू रहेगी। सरकार मान रही है कि इससे संपत्ति की खरीद बिक्री के कार्य में इससे तेजी आ रही है। विभाग का कहना है कि इस निर्णय से संपत्ति खरीदने के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत मिली है और रियल एस्टेट क्षेत्र को एक बढ़ावा मिल रहा है।

मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) के महासचिव रहने के दौरान समिति के धन का दुरुपयोग करने के मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ लुक आउट नोटिस (एलओसी) जारी किया गया है। इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट को दी। मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा के समक्ष दाखिल रिपोर्ट में पुलिस ने एलओसी जारी करने के साथ ही यह बताया कि मामले की जांच प्रगति पर है।

अदालत ने नौ जुलाई को शिकायतकर्ता की ओर से व्यक्त की गई आशंका को देखते हुए जांच अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि सिरसा भागने न पाएं। शिकायतकर्ता भूपिंदर सिंह के अधिवक्ता संजय एबट ने अदालत को बताया था कि सिरसा पहले ही अपनी संपत्तियां बेच चुके हैं और उड़ान बहाल होते ही वह देश छोड़कर भाग सकते हैं। इससे पहले अदालत ने ईओडब्ल्यू को भूपिंदर सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था ।

सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कोरोना के दौरान दवाइयों के अवैध भंडारण का मामला
- शीर्ष अदालत ने कार्यवाही पर रोक लगाने से किया इन्कार, हाई कोर्ट जाने को कहा
- कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान फाउंडेशन पर दवाइयों के अवैध भंडारण का आरोप



सुनवाई से इन्कार : सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो

पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दवाइयों के अवैध भंडारण के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर फाउंडेशन के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया और हाई कोर्ट जाने को कहा। मामले में सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की कि जब लोग दवा के लिए परेशान घूम रहे थे, तभी एक संस्था आती है और कहती है कि वह दवा देगी। संस्था दवा बांटना शुरू करती है। यह ठीक नहीं है। पीठ ने कहा कि हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते लेकिन हमें भी जमीनी हकीकत पता है।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने ये बात गौतम गंभीर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई से इन्कार करते हुए कही। इससे पहले फाउंडेशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कैलाश वासुदेव ने हाई कोर्ट के आदेश पर निचली अदालत में ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया। लेकिन पीठ ने इन्कार करते हुए कहा कि वह कार्यवाही रोकने का आदेश कैसे दे सकती है। पीठ ने कहा कि इस मामले में सिर्फ यही बात है कि याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। इसके लिए उसे हाई कोर्ट में आवेदन करना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। इसके बाद फाउंडेशन ने अपनी याचिका वापस ले ली।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था जांच का आदेश : दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोरोना के इलाज में काम आने वाली फैबीफ्लू जैसी दवाओं के अवैध भंडारण और वितरण के मामले में ड्रग कंट्रोलर को जांच करने का आदेश दिया था। जांच के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों और गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। आप विधायक प्रवीण कुमार के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस याचिका पर जांच के आदेश दिए थे उसमें आरोप लगाया गया था कि कोरोना महामारी के दौरान जब मरीज दवाओं के लिए परेशान घूम रहे थे उस वक्त राजनेताओं ने बड़ी मात्रा मे दवाइयां हासिल कर ली और उनका वितरण किया था।

दिल्ली विवि में दाखिले की दौड़ शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी, एमफिल और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विवि ने शाम करीब साढ़े पांच बजे डीयू दाखिले के लिए नई वेबसाइट लांच की। पहली बार डीयू पंजीकरण फार्म में छात्रों से टीकाकरण की जानकारी भी मांग रहा है। मंगलवार से वर्चुअल ओपन डेज शुरू होंगे।

डीयू की दाखिला वेबसाइट www. https//admission.uod. ac.in/) पर एमफिल, पीएचडी, स्नातकोत्तर के साथ ही स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पंजीकरण का लिंक दिया जाएगा। वेबसाइट पर प्रत्येक यूजी एडमिशन, पीजी एडमिशन, एमफिल-पीएचडी एडमिशन के कालम बने हुए हैं। जिन पर क्लिक करते ही आवेदन प्रक्रिया पूरा करने के लिए नया पेज खुल जाएगा। छात्र शैक्षणिक जानकारी भरकर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर चैटबाक्स की सुविधा भी है। जिसके जरिये छात्र 24 घंटे दाखिले से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। छात्र किस कदर दाखिले के लिए आवेदन का इंतजार कर रहे थे, इसकी बानगी इसी से होती है कि वेबसाइट लांच होने के महज 15 मिनट के अंदर 4500 से अधिक छात्रों ने लाग इन किया।

विश्वविद्यालय प्रशासन टीका लगाने के लिए करेगा प्रेरित : स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को टीकाकरण की जानकारी भी देनी होगी। डीयू ने पंजीकरण फार्म में इस बाबत एक सवाल पूछा है। जिसे भरना जरूरी है। डीयू छात्रों से पूछेगा कि टीका लगवाया है या नहीं। छात्रों को जवाब देने के लिए तीन विकल्प दिए जा रहे हैं। पहले के तहत नहीं का विकल्प है, दूसरे विकल्प में यह बताना होगा कि पहली डोज लगवा लिया है, वहीं तीसरे विकल्प में यह बताना होगा कि दोनों डोज लगवा लिया है। इन तीनों में से कोई एक विकल्प चुनना होगा।

University of Delhi

दिल्ली विश्वविद्यालय। फाइल फोटो

आज से होंगे ओपन डेज

एमफिल-पीएचडी, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आवेदन के दौरान छात्रों को किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए डीयू वर्चुअल ओपन डेज आयोजित करेगा। डीयू दाखिला समिति के चेयरपर्सन प्रो. राजीव गुप्ता ने बताया कि मंगलवार से लेकर 30 जुलाई तक लगातार चार दिन ओपन डेज आयोजित किए जाएंगे।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रवेश परीक्षाएं शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जामिया मिल्लिया इस्लामिया में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं पीजी डिप्लोमा में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई। जामिया प्रशासन ने बताया कि 28 अगस्त तक प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। पहले दिन जामिया परिसर में बनाए गए विभिन्न केंद्रों पर छात्रों ने परीक्षा दी। सुबह की पाली में मास्टर आफ फाइन आर्ट और पीजी डिप्लोमा इन ब्राडकास्ट टेक्नोलाजी एवं दोपहर की पाली में बैचलर आफ फाइन आर्ट (बीएफए), एमए इन उर्दू मास मीडिया की प्रवेश परीक्षा हुई।

ट्रांसजेंडर के लिए सार्वजनिक शौचालय मामले में जवाब तलब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

यौन उत्पीड़न होने के आधार पर ट्रांसजेंडर के लिए अलग से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली नगर पालिका के साथ पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी), दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) व उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ताओं ने इस बाबत अधिकारियों से निर्देश लेने के लिए समय देने की मांग की। इस पर पीठ ने सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

विधि की अंतिम वर्ष की छात्रा जैस्मिन कौर छाबड़ा ने अधिवक्ता रुपिंदर पाल सिंह के माध्यम से याचिका दायर कर कहा कि केंद्र सरकार ने अनुदान तो जारी किया, लेकिन दिल्ली में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से शौचालय नहीं बनाया गया है। उन्होंने मैसूर, भोपाल और लुधियाना में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था किए जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी अभी भी इस तरह की पहल नहीं की जा रही है।

उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडरों के लिए शौचालय की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है और उन्हें पुरुष शौचालयों का ही उपयोग करना पड़ता है। इसके कारण वहां पर ट्रांसजेंडरों को यौन उत्पीड़न का शिकार होने को मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रविधान नहीं जो ट्रांसजेंडरों को किसी पुरुष व महिला द्वारा यौन उत्पीड़न से बचाता हो। जनहित याचिका में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय देश की कुल आबादी का सात से आठ फीसद है।



सुनवाई : दिल्ली हाई कोर्ट। फाइल फोटो

17.70 लाख की मशीन का 18.36 लाख रु. मासिक किराया देगा निगम : आप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) का दावा है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम एकबार फिर ट्रामल मशीनें किराये पर लेकर धन की बर्बादी करने जा रहा है। पार्टी का कहना है कि 17.70 लाख रुपये की कीमत वाली ये मशीन यदि किराये पर ली जाती है, तो उसके लिए 18.36 लाख रुपये प्रति माह किराया देना होगा, जो भ्रष्टाचार का नया तरीका है।

आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम अब कूड़े की प्रोसेसिंग करने वाली ट्रामल मशीनों को किराये पर लेने जा रहा है। इसके लिए एक मीट्रिक टन कूड़े की प्रोसेसिंग करने पर 306 रुपये किराया दिया जाएगा। अगर एक मशीन एक महीने तक आठ घंटे प्रतिदिन कूड़े की प्रोसेसिंग करती है तो निगम को उसे 18.36 लाख रुपये किराया देना होगा। निगम ऐसी 79 मशीनें किराये पर ले रहा है, जिसके लिए दो साल में 348 करोड़ रुपये किराया देना होगा।

उन्होंने कहा कि पहले भी नगर निगमों के चीफ आडिटर की रिपोर्ट भ्रष्टाचार की पोल खोल चुकी है। निगमों ने चार करोड़ रुपये कीमत की 23 मशीनों का डेढ़ साल में 26 करोड़ रुपये किराया देकर 22 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया था।

प्रदूषण

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने किया स्वीकार, कहा- दिल्ली में लगे 35 सीवेज उपचार संयंत्रों में से 22 नहीं करते निर्धारित अपशिष्ट जल शोधन मानकों का पालन

प्रवाह के अभाव में नहाने लायक नहीं रह सकती यमुना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को सौंपी एक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह के अभाव में यमुना नहाने लायक नहीं रह सकती। इस रिपोर्ट में यह भी कहा कि दिल्ली में लगे 35 सीवेज उपचार संयंत्रों में से 22 डीपीसीसी द्वारा निर्धारित अपशिष्ट जल शोधन मानकों को पूरा नहीं करते। यही नहीं, दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में लगे 13 कामन इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) में से भी छह ही अपशिष्ट जल के लिए तय मानकों का अनुपालन करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में यमुना के प्रदूषण को कम करने एवं न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखने के लिए नदी में वांछित जल गुणवत्ता के स्तर बीओडी (बायोलोजिकल आक्सीजन डिमांड) तीन मिलीग्राम प्रति लीटर और डीओ (डिजाल्व आक्सीजन) पांच मिलीग्राम प्रति लीटर को पूरा करने की आवश्यकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलाजी रुड़की की तरफ से किए गए एक अध्ययन में भी सिफारिश की गई है कि डाउनस्ट्रीम पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए कम बारिश वाले मौसम में हरियाणा के यमुना नगर स्थित हथिनीकुंड बैराज से नदी में 23 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड (क्यूसेक) पानी छोड़ा जाए।



यमुना की दुर्दशा। फाइल फोटो

रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में वजीराबाद से ओखला तक यमुना का 22 किलोमीटर लंबा हिस्सा, जो नदी की कुल लंबाई के दो फीसद से भी कम है, में प्रदूषण का करीब 80 फीसद हिस्सा है। शाहदरा, नजफगढ़ और बारापुला सहित 18 प्रमुख नाले हैं, जो नदी में गिरते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अनुपचारित अपशिष्ट जल और सीईटीपी एवं सीवेज उपचार संयंत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट की खराब गुणवत्ता दिल्ली में नदी में प्रदूषण का प्रमुख कारण है।

डीपीसीसी ने मंत्रालय को यह भी बताया कि दिल्ली में 35 सीवेज उपचार संयंत्रों में से 22 कुल घुलनशील ठोस, रासायनिक आक्सीजन मांग, जैविक आक्सीजन मांग, भंग फास्फेट और अमोनिकल नाइट्रोजन के संबंध में निर्धारित अपशिष्ट जल मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

अपशिष्ट जल में अमोनिकल नाइट्रोजन और फास्फेट क्रमशः पांच मिलीग्राम प्रति लीटर और दो मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए। डीपीसीसी नियमों के अनुसार कुल घुलनशील ठोस (टीडीएस) 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए, बीओडी 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए और रासायनिक आक्सीजन डिमांड (सीओडी) 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए। दिल्ली में प्रतिदिन करीब 720 मिलियन गैलन सीवेज उत्पन्न होता है, जिसका उपचार 597 एमजीडी की उपचार क्षमता वाले इन 35 एसटीपी में किया जाता है।

आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उपचार क्षमता का करीब 86 फीसद उपयोग किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है दिल्ली में 13 सीईटीपी में से सात अपशिष्ट मानकों को पूरा नहीं करते हैं। ये सीईटीपी नारायणा, लारेंस रोड, नांगलोई, वजीरपुर, मंगोलपुरी, मायापुरी और झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में हैं। इस महीने की शुरुआत में डीपीसीसी ने ऐसे 12 सीईटीपी संयंत्रों पर 12 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया था।

अस्पताल अधूरा, सियासत पूरी

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

बाला साहिब अस्पताल 19 वर्षों बाद भी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर सियासत जरूर तेज हो गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के पिछले दो चुनावों में यह बड़ा चुनावी मुद्दा बना था। इसी के सहारे शिरोमणि अकाली दल (शिअद बादल) को डीएसजीएमसी में सत्ता मिली है। इस चुनाव में भी इसे लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। पिछले माह इस अस्पताल परिसर में देश का सबसे बड़ा डायलिसिस केंद्र शुरू किया गया है। इसके साथ ही 125 बिस्तरों वाला कोरोना अस्पताल बनाया जा रहा है। शिअद बादल इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर रहा है। वहीं, विरोधी पार्टियां इसे लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। वर्ष 2002 में 12 एकड़ जमीन पर पांच सौ बिस्तरों वाला अत्याधुनिक अस्पताल बनाने का काम शुरू हुआ था। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली (सरना) के कार्यकाल में इसे लेकर एक निजी अस्पताल के साथ समझौता किए जाने पर विवाद शुरू हुआ था। शिअद बादल ने तत्कालीन अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना पर अस्पताल को बेचने व भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। वर्ष 2013 के चुनाव में यह चुनावी मुद्दा बना व सरना को पराजय का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया। वर्ष 2017 के चुनाव में भी यह मुद्दा उठा था।

इस वर्ष मार्च में यहां सौ मशीन के साथ डायलिसिस केंद्र की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही इसी परिसर में कोरोना अस्पताल बनाने का काम चल रहा है। डीएसजीएमसी ने सात अगस्त को इसके उद्घाटन की घोषणा की है। वहीं, सरना का आरोप है कि चुनाव में लाभ उठाने के लिए बगैर जरूरी मंजूरी के और आपातकालीन सुविधाओं की व्यवस्था किए बिना डायलिसिस केंद्र शुरू किया गया है।

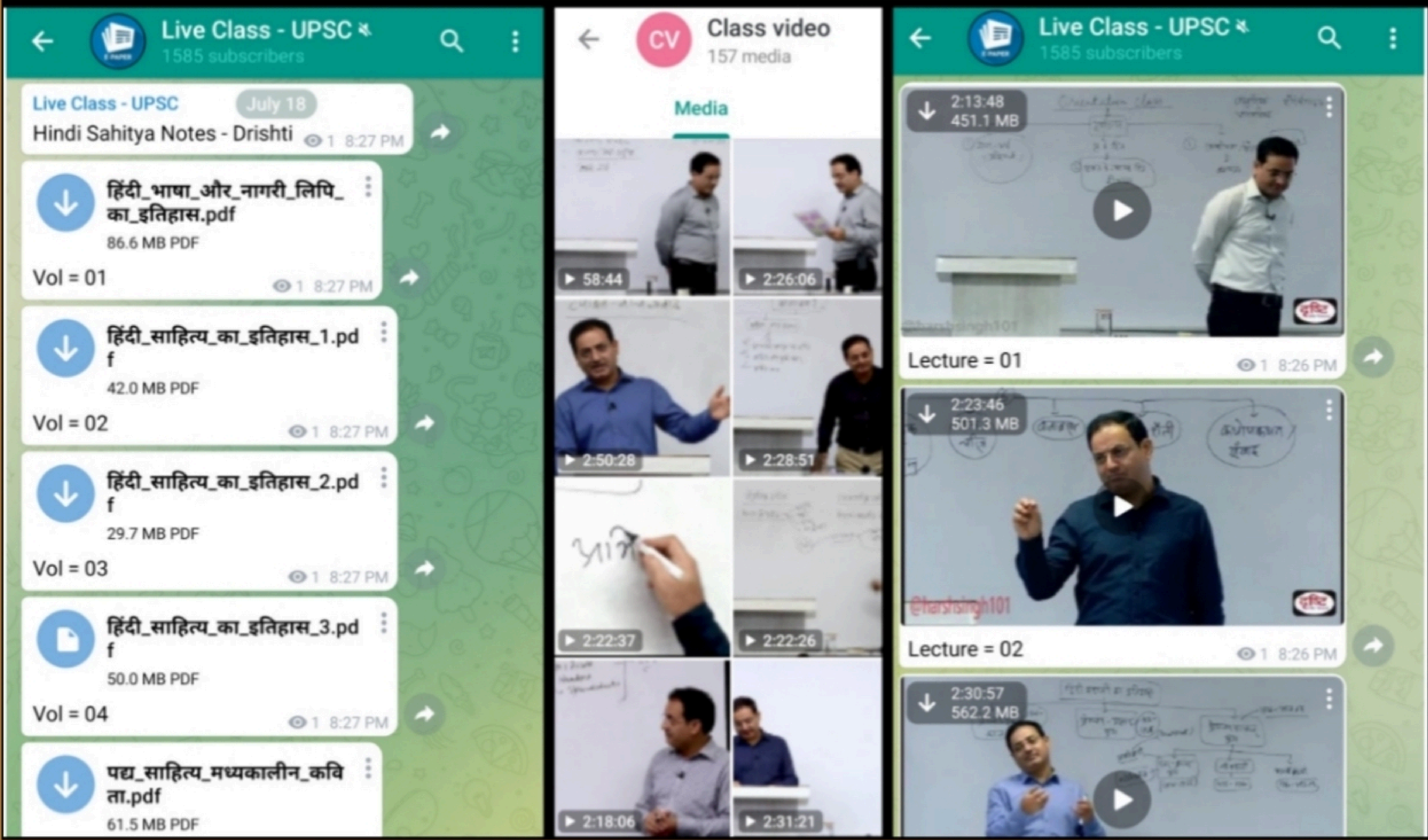
Vikas Divyakriti Sir Hindi literature Full Course

Year - 2020-21
Total - 157 Video lectures + 20 Booklet Pdf

👉(Real Price - 40000/-)
👉We Provide only ₹1499 ✅

दृष्टि The Vision

Contact on Telegram 👉 @prakashstudy24



3 अक्टूबर को किया जाएगा जेईई–एडवांस का आयोजन। पहले यह परीक्षा तीन जुलाई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की स्थितियों को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। इस साल इन परीक्षाओं का संचालन आइआइटी खड़गपुर कर रहा है।

आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में और बिगड़ सकते हैं हालात

बिगड़ते हालात ▸ बदला नहीं है तालिबान, शांति वार्ता के बहाने अमेरिकी सेना की पूर्ण वापसी का कर रहा इंतजार

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

अफगानिस्तान के 426 जिलों में से 212 जिलों में तालिबान ने बढ़त बना ली है इसके बावजूद उसके लिए काबुल की सत्ता अभी काफी दूर है। ना सिर्फ अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी फोर्स (एएनएसएफ) तालिबान का जबरदस्त मुकाबला कर रही है बल्कि जिस तरह से अमेरिका, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों में तालिबान को लेकर संशय बना है उसका भी असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा।

> ▸ हालात पर नजदीकी नजर रखने के साथ ही रूस, ईरान, अमेरिका और पश्चिम एशियाई देशों के संपर्क में भारत

भारत अफगानिस्तान के पूरे हालात पर करीबी नजर रखने के साथ ही रूस, ईरान, अमेरिका और पश्चिम एशिया के देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क बनाये हुए है। भारत का आकलन है कि अगले दो से तीन महीने अफगानिस्तान के लिए अहम होंगे क्योंकि वहां हिंसक वारदातों में भारी बढ़ोतरी होने की आशंका है।

अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखने वाले कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि 19 जुलाई, 2021 तक वहां के जिन 212 जिलों पर तालिबान के कब्जे की पुष्टि हुई है वहां भी हालात तेजी से बदल सकते हैं। अफगानिस्तान के जिला मुख्यालय और कस्बे भारत की तरह घनी आबादी वाले नहीं हैं। कुछ जिला मुख्यालयों में तो मुश्किल से गिने-चुने घर और दफ्तर ही मिलेंगे। तालिबान लड़ाकों का कोई भी एक दस्ता वाहन से जा कर वहां अपना झंडा लहरा देता है और फिर उसे अपने कब्जे में होने का बात करता है। लेकिन कुछ ही घंटे में सरकारी सैन्य बल उसे हटा देते हैं। लेकिन यह सच है कि तालिबान दोहा, तेहरान, मास्को में चल रही शांति वार्ताओं की आड़ में ज्यादा से ज्यादा समय काटने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि तालिबान अगस्त के अंत तक का इंतजार कर रहा है, तब तक वहां से अमेरिकी सेना की पूरी तरह से वापसी हो जाएगी। उसके बाद तालिबान काबुल, कंधार, गजनी, हेलमंद जैसे शहरों पर हमला करने की रणनीति अपना सकता है। अभी तालिबान ने अफगान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर धावा बोलने व कब्जा करने की रणनीति अपनाई है। तालिबान को लगता है कि इससे दूसरे देशों से मान्यता हासिल करने में मदद मिलेगी। भारतीय पर्यवेक्षक यह भी मान रहे हैं कि दो-तीन हफ्तों में तालिबान को लेकर तमाम देशों के विचार में बदलाव आया है। रूस, ईरान जैसे देश जो अभी तक अमेरिका के अफगानिस्तान से वापसी की लगातार मांग कर रहे थे उन्हें भी यह समझ आने लगा है कि आज का तालिबान तीन वर्ष पुराने तालिबान जैसा ही है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद वहां फैलने वाली अस्थिरता को लेकर अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले देश जैसे चीन, ईरान, रूस, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान चिंतित हैं। इनकी चिंता का कारण यह है कि तालिबान के साथ जो आतंकी हैं वो इन देशों के लिए आने वाले दिनों में परेशानी पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि हाल ही में मास्को और ताशकंद में अफगानिस्तान को लेकर संपन्न बैठकों में तालिबान को लेकर काफी प्रतिकूल माहौल बना है। ऐसे में अफगानिस्तान का भविष्य बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत समेत तमाम देश वहां की केंद्रीय सरकार को किस तरह की मदद मुहैया कराते हैं। अमेरिकी सेना की पूरी वापसी के बाद तालिबान शहरों पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। ऐसे में अगर वहां की सेना को दूसरे देशों से मदद मिलती है तो तालिबान को सीमित करना आसान होगा।

तालिबान को असलहे से लेकर इलाज तक पाकिस्तान से मिल रही है पूरी मदद

भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी मिल रही है कि किस तरह से पाकिस्तान व वहां की सेना तालिबान को मदद दे रही है। तालिबान को लड़ाई में असलहे पाक सेना दे रही है। लड़ाई में जो तालिबानी घायल हो रहे हैं उन्हें खैबर पख्तूनख्वा व बलूचिस्तान के शहरों में इलाज के लिए लाया जा रहा है। चमन शहर स्थिति प्रमुख सरकारी अस्पताल व क्वेटा स्थित जिलानी अस्पताल में बड़ी संख्या में तालिबानी लड़ाकों का इलाज चल रहा है। स्थानीय प्रशासन ने मदरसों व दूसरे इस्लामिक इदारों को अफगान में जिहाद के लिए लड़ाकों को भर्ती करने की छूट दे दी है। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का समर्थन अफगानिस्तान में हिंसा को बढ़ावा देगा। भारतीय सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान एक वर्ष पहले तक दुनिया के समक्ष बोलता रहा है कि उसके यहां कोई तालिबान नहीं है लेकिन अब वह तालिबान के साथ रिश्तों को भी छिपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा।

एलएसी पर सैन्य वार्ता को लेकर चीन की आनाकानी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के कुछ हिस्सों से इस साल फरवरी में सैनिकों की वापसी के बाद से चीन का रवैया बदल गया है। वह बाकी के हिस्सों से अपने सैनिकों को हटाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच संवाद का सिलसिला भी पहले के मुकाबले शिथिल पड़ गया है। भारत के आग्रह के बावजूद चीन की तरफ से आगामी सैन्य वार्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही।

दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की 12 दिन पहले यानी 14 जुलाई को मास्को में हुई मुलाकात का भी असर होता नहीं दिख रहा है। एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग ई के बीच चली एक घंटे की बातचीत में दोनों पक्षों ने कहा था कि एलएसी विवाद को लंबा खींचा जाना आपसी रिश्तों के हित में नहीं है, इसके बावजूद विवाद सुलझाने के लिए आगामी वार्ता को लेकर अनिश्चतता बनी हुई है। चीन ने मई, 2020 में एलएसी का उल्लंघन किया था। तनाव बढ़ने के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक व सैन्य स्तर की वार्ता शुरू हुई थी। 25 जून, 2021 को दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच बात हुई थी और यह तय किया गया था कि जल्द ही वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की अगली बैठक होगी। आम तौर पर कूटनीतिक स्तर की वार्ता के बाद 10 दिनों के भीतर ही सैन्य अधिकारियों की बैठक होती थी। लेकिन इस बार एक महीना बीत जाने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ है। इस बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी हो चुकी है। उक्त बैठक में चीन के विदेश मंत्री की तरफ से जल्द ही अगले दौर की बातचीत करने का आश्वासन भी दिया गया।

> ▸ दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की वार्ता के 11 दिन बाद भी सैन्य स्तर की बातचीत को लेकर अनिश्चितता

अभी तक सैन्य स्तर की 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक इलाके में दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटने में इससे मदद भी मिली। लेकिन गोगरा, देपसांग और हॉट स्प्रिंग के इलाके से चीन अपनी सेना को पीछे हटाने को तैयार नहीं हो रहा।

मनमाने तरीके से 95 फीसद से अधिक अंक नहीं दे सकेंगे स्कूल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबंधित स्कूल 10वीं-12वीं के छात्रों को मनमाने तरीके से 95 फीसद से ज्यादा अंक नहीं दे सकेंगे। बोर्ड ने कहा है कि रेफरेंस ईयर (संदर्भ वर्ष) में जितने छात्रों को 95 फीसद से ज्यादा अंक मिले थे, इस वर्ष भी उतने ही छात्रों को इतने अंक मिल सकते हैं।

सीबीएसई के नए निर्देशों के मुताबिक संदर्भ वर्ष में यदि चार छात्रों को 95 फीसद से ज्यादा अंक मिले थे तो इस वर्ष भी स्कूल केवल चार छात्रों को इतने अंक दिए जा सकते हैं। 2020-21 के लिए संदर्भ वर्ष पिछले तीन वर्षों यानी 2017-18, 18-19 और 19-20 को माना जाएगा। यदि कोई स्कूल बोर्ड के नियमों का पालन नहीं करता है तो बोर्ड स्वतः ही छात्रों के अंक कम कर देगा। बोर्ड के मुताबिक संदर्भ वर्ष का नियम केवल 96, 97, 98, 99 और 100 अंक देने के लिए लागू होगा।

दरअसल, कई स्कूलों ने छात्रों को गलत तरीके से 95-100 फीसद के बीच अंक दे दिए थे, जिसकी वजह से परिणाम घोषित करने में देरी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक छात्रों का इंतजार जल्द ही खत्म होने की संभावना है। 10वीं का परिणाम इस हफ्ते और 12वीं का परिणाम 31 जुलाई जारी किया जा सकता है।

ममता सरकार ने गठित किया जांच आयोग

पेगासस जासूसी विवाद ▸ सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के पूर्व जज करेंगे जांच

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

कथित पेगासस जासूसी मामले में जारी सियासत के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाया है। तृणमूल प्रमुख ने इजराइली स्पाइवेयर के जरिये नेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों की जासूसी कराए जाने आरोपों की पड़ताल के लिए दो सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को इसकी घोषणा की। चार दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की विशेष बैठक में जांच आयोग (पैनल) गठित करने का फैसला लिया गया, जिसके सदस्य सुप्रीम कोर्ट एवं कलकत्ता हाई कोर्ट के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं।

बैठक के बाद राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ममता ने कहा कि हमें लगा था कि फोन हैक किए जाने की जांच के लिए केंद्र कोई जांच आयोग गठित करेगा या अदालत की निगरानी में जांच का आदेश दिया जाएगा, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। इसलिए हमने बाध्य होकर इस मामले की पड़ताल के लिए जांच आयोग गठित करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के



सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर।



कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य।

पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य इस आयोग के सदस्य हैं।

जांच आयोग का गठन करने वाला बंगाल पहला राज्य : उन्होंने कहा कि बंगाल पहला राज्य है, जहां इस मामले में जांच आयोग का गठन किया गया है। ममता ने कहा कि पेगासस के जरिये जिन लोगों को निशाना बनाया गया है, उनमें बंगाल के लोगों के भी नाम सामने आए हैं। केंद्र सबकी जासूसी करने की कोशिश कर रहा है। आयोग अवैध रूप से फोन हैक करने, मानीटरिंग, सर्विलांस, फोन रिकार्डिंग के मामले संबंधी पूरी जानकारी का पता लगाएगा।

छह महीने में रिपोर्ट सौंपेगा आयोग : उन्होंने बताया कि जांच अधिनियम-1952 के तहत आयोग का गठन किया गया है और यह छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। दिल्ली रवाना होने से पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। ममता ने कहा कि पेगासस के जरिये न्यायालय से लेकर सभी को नजरबंदी करके रखा है। उन्होंने दावा किया कि हमारे फोन भी टैप किए जा रहे हैं। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल नेताओं, सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों की जासूसी करने के लिए किया गया था, जिसके बाद देश और दुनिया भर में इसे लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।

ममता ने सुप्रीम कोर्ट से भी संज्ञान लेने का किया था अनुरोध : बता दें कि इसके पहले ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध किया था कि वह पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके निशाना बनाने वाले कथित जासूसी प्रकरण का संज्ञान लें। इतना ही नहीं यह प्रकरण सामने आने के बाद ममता ने अपने फोन के कैमरे पर मोदी सरकार द्वारा कथित जासूसी के विरोध में हाल में टेप भी चिपका दिया था। दरअसल ममता और उनकी पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी (ममता के भतीजे) और प्रशांत किशोर (चुनाव रणनीतिकार) की कथित जासूसी को लेकर हमलावर हैं।

अपने मंत्रियों और विरोधियों की जासूसी कराती हैं ममता : भाजपा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

पेगासस जासूसी मामले की पड़ताल के लिए बंगाल सरकार द्वारा जांच आयोग गठित करने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए भाजपा ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार किया। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने दावा किया कि खुद ममता सरकार उसी इजराइली जासूसी साफ्टवेयर का इस्तेमाल अपने विरोधियों, पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों और यहां तक कि अपनी ही पार्टी के नेताओं और मंत्रियों की निगरानी करने के लिए कर रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा फोन टैपिंग की संस्कृति में विश्वास नहीं करती। भट्टाचार्य ने सवाल किया कि क्या पिछले 10 वर्षों में कोलकाता पुलिस का कोई कमिश्नर इस स्पाइवेयर के लिए इजरायल गया था? उन्होंने राज्य सरकार से इस पर स्पष्टीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि टीएमसी के नेता सामान्य फोन पर बात या संदेश साझा इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पता कि उनका फोन टैप हो रहा है।

> ▸ भट्टाचार्य ने पूछा– क्या पिछले 10 वर्षों में कोलकाता पुलिस का कोई कमिश्नर इस स्पाइवेयर के लिए इजरायल गया था?

दूसरी ओर, भाजपा आइटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी जांच आयोग के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि ममता को पहले चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच करानी चाहिए।

माकपा ने ममता को भी कठघरे में किया खड़ा : दूसरी ओर बंगाल विधानसभा के नेता रहे सुजन चक्रवर्ती ने सोमवार को कहा कि विरोधी दल के नेताओं का फोन पेगासस के जरिये टैप कराये जाने का पूरे देश में तीव्र विरोध होना चाहिए। यह अनैतिक है। साथ ही उन्होंने फोन टैपिंग कराने लिए ममता को भी कठघरे में खड़ा किया। वरिष्ठ माकपा नेता ने कहा कि ऐसे ही सवाल भाजपा में रहते समय मुकुल राय ने भी उठाए थे। तब उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार विरोधी नेताओं के फोन टैप करवाती है। इस मुद्दे पर ममता कुछ नहीं कह रहीं। उन्हें मुकुल के उन ओरोपों का जवाब देना चाहिए।

देश की 333 कंपनियों को रक्षा उपकरण बनाने के लाइसेंस

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारत में रक्षा उत्पादों को बनाने में निजी क्षेत्र ने भारी रुचि दिखाई है। देश की 333 प्राइवेट कंपनियों को रक्षा उत्पाद बनाने के लिए 539 लाइसेंस जारी किए गए हैं। इनमें से 110 कंपनियों ने उत्पादन भी शुरू कर दिया है। यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में लिखित जवाब में दी है। मंत्री ने बताया कि ये लाइसेंस उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन के लिए जारी किए गए हैं जो सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित किए हैं। मार्च 2001 में सरकार ने इन वस्तुओं का 100 प्रतिशत उत्पादन निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित कर दिया था। 2020 में रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तमाम रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी और उनकी खरीद स्वदेशी कंपनियों से करने का फैसला किया। रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन विकसित कर उनकी आपूर्ति करनी है।

रक्षा मंत्रालय ने कुल 209 रक्षा उपकरणों-वस्तुओं की सूची बनाकर उनके आयात पर रोक लगाई है। इन उत्पादों की खरीद स्वदेशी कंपनियों से की जाएगी। जारी किए गए लाइसेंस इन्हीं वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं। इसे भारतीय रक्षा उत्पादन उद्योग के लिए बड़ा मौका माना जा रहा है। इससे सेनाओं को अपेक्षाकृत कम मूल्य पर समय से उत्पाद मिल सकेंगे।

बिना चर्चा के लोस से दो विधेयक पारित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेगासस जासूसी विवाद और कृषि कानूनों के विरोध के कारण जारी गतिरोध के चलते मानसून सत्र में कामकाज को लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। लिहाजा सरकार ने जरूरी विधयेकों को पारित कराने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस क्रम में सोमवार को लोकसभा से हंगामे और विपक्ष के भारी विरोध के बीच फैक्ट्री रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फूड टेक्नोलाजी इंटरप्रिंयोरशिप मैनेजमेंट बिल पारित करा लिए गए। विपक्ष ने हंगामे के बीच विधेयक पारित कराने पर सवाल उठाते हुए इसे अलोकतांत्रिक करार दिया और कहा कि सरकार बिना बहस जबरन विधेयक पारित करा रही है।

लोकसभा में फैक्ट्री रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कानून में नए बदलाव से एमएसएमई सेक्टर को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह संशोधन यूके सिन्हा कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप किए गए हैं और सरकार ने संसद की स्थायी समिति के पिछले साल दिए सुझावों को भी विधेयक में शामिल कर लिया है। वित्त मंत्री ने सदन में तीन बजे जब विधेयक पेश किया तो विपक्ष का शोर-शराबा तेज हो गया और बिना चर्चा कराए ही चंद मिनटों के भीतर पीठासीन अधिकारी रमादेवी ने विधेयक को पारित करा दिया।

इसी हंगामे के बीच नए खाद्य मंत्री पशुपति कुमार पारस ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फूड टेक्नोलोजी इंटरप्रिंयोरशिप मैनेजमेंट बिल पेश किया। इसे भी आनन-फानन में विपक्ष के विरोध और शोर-शराबे के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को राज्यसभा बजट सत्र के दौरान मार्च में पहले ही पारित कर चुकी है। प्रेट्र के मुताबिक, इस विधेयक के जरिये हरियाणा में कुंडली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फूड टेक्नोलाजी इंटरप्रिंयोरशिप एंड मैनेजमेंट (एनआइएफटीईएम) और तमिलनाडु में तंजाबुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलाजी (आइआइएफपीटी) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया जाएगा।

मानसून सत्र

> ▸ हंगामे के बीच फैक्ट्री रेगुलेशन अमेंडमेंट व नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फूड टेक्नोलाजी इंटरप्रिंयोरशिप मैनेजमेंट बिल पारित
>
> ▸ हरियाणा में कुंडली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फूड टेक्नोलाजी इंटरप्रिंयोरशिप एंड मैनेजमेंट को मिलेगा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा

विपक्षी दलों ने किया विरोध

संसद में गतिरोध के बीच विधेयक पारित कराने के सरकार के रुख का कई विपक्षी दलों ने विरोध किया। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार ने गलत तरीके से जबरन इन दोनों विधेयकों को बिना चर्चा के पारित किया है।

उनका कहना था कि जब सदन में व्यवस्था की स्थिति नहीं है तब विधेयकों को इस तरह बिना बहस के पारित कराना, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लोगों की आवाज सदन में रखने से रोकने जैसा है। अधीर ने कहा कि यह सांसदों को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का प्रयास है और कांग्रेस इस तरह के प्रयास का विरोध करेगी।

छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का आकलन करेगा एनसीईआरटी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का आकलन करने के लिए एनसीईआरटी इस साल नवंबर में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण करेगा। कक्षा तीन, पांच और आठ के लिए यह सर्वेक्षण इससे पहले 2017 में और कक्षा 10 के लिए 2018 में किया गया था। यह जानकारी लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी। उनसे पूछा गया था कि हाल के दिनों में आनलाइन क्लास में बढ़ोतरी को देखते हुए क्या स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन या सर्वेक्षण किया गया है? इसके जवाब में प्रधान ने कहा, एनसीईआरटी कक्षा-तीन, पांच, आठ और 10 के छात्रों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करता है। कक्षा-तीन, पांच और आठ के लिए यह सर्वेक्षण 13 नवंबर, 2017 को हुआ था। सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 701 जिलों में हुए इस सर्वेक्षण में 1.10 लाख स्कूलों के 22 लाख छात्रों ने भाग लिया था।

धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा को बताया कि केंद्र सरकार उच्च शिक्षा आयोग का गठन करेगी। शिक्षा मंत्रालय इसके लिए विधेयक तैयार करने की प्रक्रिया में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जैसे स्वायत्त निकायों के स्थान पर उच्च शिक्षा आयोग की परिकल्पना की गई है।

आइआइटी मद्रास का नाम बदलने का प्रस्ताव नहीं : धर्मेंद्र प्रधान ने आइआइटी मद्रास का नाम बदलने के किसी प्रस्ताव से इन्कार किया है। लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने इस सिलसिले में बयान दिया। उन्होंने कहा, आइआइटी मद्रास के नाम में संशोधन के किसी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।

> ▸ नवंबर में स्कूलों में किया जाएगा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण
>
> ▸ आनलाइन क्लास में बढ़ोतरी को देखते हुए परखी जाएगी शिक्षा की गुणवत्ता



धर्मेंद्र प्रधान। फाइल/इंटरनेट मीडिया

29 को शिक्षा नीति पर पीएम करेंगे राष्ट्र को संबोधित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश को आत्मनिर्भर बनाने की सोच के साथ पेश की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को 29 जुलाई को एक वर्ष पूरा हो रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह नीति के अमल को लेकर अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। साथ ही शिक्षा नीति के आगे के रोडमैप को भी दिशा देंगे। शिक्षा नीति को कैबिनेट ने 29 जुलाई, 2020 को मंजूरी दी थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पीएम के संबोधन की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को पत्रकारों के साथ अनौपचारिक चर्चा में दी। उन्होंने बताया कि नीति से जुड़े प्रत्येक बिंदु के अमल की जो समय सीमा तय की गई थी, फिलहाल उसी के अनुरूप काम चल रहा है। वैसे भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस सरकार के लिए काफी अहम है, क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया और आम लोगों से जुड़ाव के बाद सामने आई है। इसे तैयार करने में लाखों लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। नीति को लेकर इससे पहले भी पीएम मोदी अलग-अलग मंचों से इसकी सोच को सामने ला चुके हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक में कई बड़े बदलाव की सिफारिशें की गई है। इनमें स्कूलों की नई संरचना बनाई गई है, जिसमें प्री-प्राइमरी को भी शामिल गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कमीशन बनाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन जैसी सिफारिशें हैं।

29 जुलाई, 2020 को कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दी थी मंजूरी



नरेंद्र मोदी। जागरण आर्काइव

इतिहास की झलक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन सभी स्थलों को किया चिह्नित, इन सभी का होगा जीर्णोद्धार, इनमें उत्तर प्रदेश के कुल चार स्थल, मौजूदा समय में देश में राष्ट्रीय महत्व के करीब 37 सौ स्थल और स्मारक

21 और स्मारक होंगे राष्ट्रीय महत्व के स्थल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश के राष्ट्रीय महत्व के स्थलों को चिह्नित करने और उनके संरक्षण में लगातार जुटी केंद्र सरकार ने 21 और स्थलों और स्मारकों को इस सूची में शामिल करने के लिए चुना है। इनमें उत्तर प्रदेश के चार स्थल और स्मारक भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के जिन स्थलों और स्मारकों को इसके लिए चुना गया है, उनमें लखनऊ का नक्कारखाना (नौबतखाना), चित्रकूट के गणेश बाग स्थित पुरातात्विक स्थल, तालाब, होदी और बावड़ी हैं। इसके साथ ही बस्ती जिले के सिसवानिया स्थित पुरातात्विक स्थल, आगरा के फतेहपुर सीकरी स्थित शिक्षा चित्रकारी समूह को इसके लिए चुना गया है।

संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थलों व स्मारकों को लेकर संसद को दी गई जानकारी में यह ब्योरा दिया है। साथ ही कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) लगातार ऐसे स्थलों की पहचान करने का काम करता है। इन नए 21 स्थलों का चयन भी इसी प्रक्रिया के तहत किया गया है। खास बात यह है कि राष्ट्रीय महत्व की सूची के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के भी चार स्थलों और स्मारकों का चयन किया गया है। इनमें लेह के रदनांग का शिला कला स्थल मुरगी, सासपोल की प्राचीन गुफाएं, न्यारमा के प्राचीन बौद्ध संस्थान अवशेष व पवित्र झील (स्लोब फान रसो) के चारों ओर संलग्न अवशेष और त्रिशेर स्पूत शामिल हैं। इस सूची में झारखंड के गुमला जिले के दोइसा नगर स्थित मृदभांड ईंटों का मंदिर और हजारीबाग जिला के आइस्को स्थित शिला चित्रकारी को शामिल किया गया है। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के गांव संयुराकट स्थित प्राचीन नौला व केंद्रीय संरक्षित स्मारक कुबेरे मंदिर के साथ स्थित चार मंदिर भी चयनित किए गए हैं। हरियाणा के राखीगढ़ी स्थित प्राचीन टीला छह और सात, हिमाचल के कांगड़ा जिला के कलेसर स्थित कलेश्वर महादेव मंदिर भी सूची में शामिल हैं।

संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक पुरातात्विक महत्व के इन सभी स्थलों के जीर्णोद्धार का काम जल्द ही शुरू होगा। इसका विस्तृत ब्योरा मांगा गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय महत्व के देश के दूसरे स्थलों का संरक्षण भी किया जाएगा। मौजूदा समय में देश में राष्ट्रीय महत्व के करीब 37 सौ स्थल हैं। यह सभी एएसआइ की ओर से संरक्षित हैं। गौरतलब है कि देशभर में एक मुहिम के तहत बिखरे पुरातात्विक महत्व के स्थलों और स्मारकों का पता लगाने का काम लगातार चल रहा है।



लखनऊ का नौबतखाना। फाइल/इंटरनेट मीडिया

सड़क हादसों में डेढ़ लाख से ज्यादा मौतें

नई दिल्ली, प्रेट्र : सड़क हादसों को लेकर सरकार कई मोर्चों पर जागरूकता अभियान चला रही है। हालांकि तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं सुधरी है। राज्यसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दिए गए जवाब के मुताबिक, 2019 में हादसों में डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। यह इससे सालभर पहले के लगभग बराबर ही है। इस दौरान हादसों की संख्या में थोड़ी गिरावट दिखी। एक अन्य प्रश्न पर उन्होंने कहा कि राजमार्गों के किनारे से शराब की दुकानें हटाए जाने को लेकर सरकार के पास डाटा नहीं है, क्योंकि यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है। सरकार ने निर्धारित गति से तेजी गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, गलत लेन में जाने आदि को हादसों के लिए जिम्मेदार बताया है।

सरकार ने हाईवे पर दुर्घटना की संभावित जगहों की पहचान करने व गाड़ियों की गति नियंत्रण के लिए डिवाइस लगाने की बात कही है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी



सहनी की चेतावनी, उप्र में घुसने से रोका तो हम बिहार में रोकेंगे

राज्य ब्यूरो, पटना : उत्तर प्रदेश में फूलन देवी की प्रतिमा प्रकरण के बाद बिहार के मंत्री मुकेश सहनी के तेवर तल्ख हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मुकेश सहनी से इतना डर लगा कि विधि-व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें प्रेस तक से नहीं मिलने दिया गया। जो काम योगी ने उनके साथ किया, वही काम बिहार में वह योगी के साथ भी कर सकते हैं।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहनी बिहार सरकार में पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री हैं। अपने सरकारी आवास पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार सन आफ मल्लाह (सहनी द्वारा खुद को दी गई उपमा) को बनारस (वाराणसी) आने से रोक सकती है, लेकिन निषाद समाज को सरकार बनाने से नहीं रोक सकती है। मैं वाराणसी में नहीं घुस सकूं, इसके लिए पांच हजार पुलिस जवान लगाए गए।

उन्होंने कहा कि मुझे रोकने के लिए विधि-व्यवस्था का हवाला दिया गया। जो मुख्यमंत्री विधि-व्यवस्था नियंत्रित नहीं कर सकता, उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। योगी आदित्यनाथ तुरंत इस्तीफा दें। सहनी बोले, जिस प्रकार बिहार में राजग के मुखिया नीतीश कुमार सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, वैसे ही योगी को भी रखना चाहिए, लेकिन उप्र में ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि उप्र में उनकी सरकार बनेगी तो वह सभी जिलों में फूलन देवी की प्रतिमा लगाएंगे।

राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल से बाहर होंगे आधा दर्जन मंत्री

फेरबदल ▶ विधानसभा उपाध्यक्ष और संसदीय सचिव भी बनाए जाएंगे

पार्टी हाईकमान तक पहुंची हैं कई मंत्रियों की शिकायतें

जागरण संवाददाता, जयपुर


अशोक गहलोत। जागरण आर्काइव

कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान में सत्ता और संगठन में फेरबदल की कार्ययोजना लगभग तैयार कर ली है। इसके तहत मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ ही मानसून सत्र से पहले विधानसभा उपाध्यक्ष और संसदीय सचिव बनाए जाएंगे। पांच से छह मंत्रियों को संसदीय सचिव बनाए जाने की संभावना है तो आधा दर्जन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन के पास कुछ मंत्रियों की शिकायतें आई हैं। इनके कार्य-व्यवहार से विधायक व पार्टी पदाधिकारी संतुष्ट नहीं हैं। इन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने को लेकर आलाकमान ने प्रारंभिक दौर का विचार-विमर्श कर लिया है। हालांकि आधिकारिक फैसला 28 और 29 जुलाई को विधायकों का मन जानने के बाद होगा। सूत्रों के अनुसार विभिन्न माध्यमों से मिली रिपोर्ट के बाद आलाकमान निर्णय की स्थिति में पहुंच चुका है। पहली बार विधायक बनने वालों को संसदीय सचिव बनाने पर विचार हो रहा है। इनकी संख्या पांच से छह हो सकती है।

इन मंत्रियों पर लटक रही तलवार : खानमंत्री प्रमोद जैन भाया व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं। विधायक भरत सिंह ने कई बार सीएम को पत्र लिखकर खानमंत्री पर अवैध खनन का आरोप लगाया है। सहकारी समितियों में गड़बड़ी को लेकर आंजना की शिकायतें लंबे समय से उच्च स्तर तक पहुंच रही हैं। बाड़मेर के कलमेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पर आरोप लग रहे हैं। मामले की सीबीआइ जांच चल रही है। उच्च शिक्षामंत्री भंवर सिंह भाटी, खेल मंत्री अशोक चांदना व मोटर गैराज मंत्री राजेंद्र यादव की विभागों में पकड़ नहीं होने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने आलाकमान तक शिकायत पहुंचाई है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। पिछले साल पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय खाचरियावास ने कई नेताओं पर व्यक्तिगत आरोप लगाए थे। उल्लेखनीय है कि 200 सदस्यीय विधानसभा के 15 फीसद अर्थात 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 20 मंत्री हैं। ऐसे में नौ मंत्री नए बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मौजूदा मंत्रिमंडल में से पांच से छह मंत्री हटाने के बाद कुल एक दर्जन मंत्री बनाने पर विचार किया जा रहा है। दो स्थान खाली रखे जा सकते हैं।

डोटासरा ने दिए हटाए जाने के संकेत : फेरबदल की कसरत के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सरकार में शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें डोटासरा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली से कह रहे हैं कि मुझसे जो कराना है, करा लीजिए, मैं दो-चार दिन का मेहमान हूं। उनके इस बयान को मंत्री पद से हटा कर अध्यक्ष रखे जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले 11 माह से वह दोनों पदों पर हैं। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत अब उन्हें एक ही पद पर रखा जाएगा।

किसी प्रलोभन या भय के कारण मतांतरण करना गलत : कुशवाहा

जासं, बक्सर : पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारे देश में सबको मतांतरण का अधिकार है। आज यदि वह स्वयं इस्लाम कबूल करना चाहें तो उन्हें कौन रोक सकता है? अगर किसी प्रलोभन या किसी भय के कारण ऐसा किया जाए तो यह गलत है। स्थानीय परिसदन में कुशवाहा रविवार को पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट सहित कई कुछ न्यायालयों ने तथा कई राज्य की सरकारों ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि आप यदि पिछड़ों के लिए योजना बनाते हैं और आपको उनकी संख्या ही नहीं पता है तो योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो सकेंगी। ऐसे में जातीय जनगणना जरूरी है। 1931 के बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई है। यह पूछे जाने पर कि भाजपा तो जातीय जनगणना को लेकर जदयू के स्टैंड से अलग है, कुशवाहा ने कहा कि भाजपा अलग पार्टी है और जदयू अलग पार्टी। गठबंधन में भले ही हम एक साथ हैं लेकिन हमारी राय अलग-अलग हो सकती है।

कुशवाहा ने कहा, मैं नीतीश कुमार के साथ तबसे हूं, जब से समता पार्टी का गठन हुआ था। लंबे समय तक नीतीश के साथ काम करने का अनुभव रहा है। बीच में कुछ परेशानी हुई जिसके चलते रास्ता अलग हो गया लेकिन, इस बार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसका जनादेश यही मिला कि आप दोनों एक साथ हो जाइए।

जातिगत जनगणना : भाजपा-जदयू के स्वर में समन्वय नहीं

राज्य ब्यूरो, पटना

अलग-अलग सुर

- भाजपा विधायक ने दी प्रतिक्रिया, किसी भी हाल में नहीं होने देंगे जातिगत जनगणना
- 31 जुलाई को प्रस्तावित जदयू की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में यह होगा अहम मुद्दा

बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन (सोमवार) ही जातिगत जनगणना जैसे अहम मुद्दे पर भाजपा और जदयू के स्वर में तालमेल नहीं दिखा। दोनों अपने-अपने रुख पर कायम हैं। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि भाजपा जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। इसे किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इससे समाज में फासला बढ़ेगा। सद्भाव खत्म होगा। कोई व्यवस्था अगर पहले से बनी हुई है तो उसमें बदलाव का सवाल ही पैदा नहीं होता।

हरिभूषण ठाकुर का यह बयान वैसे वक्त में आया है, जब बिहार भाजपा के बड़े नेताओं ने इस संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। दूसरी ओर जदयू ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह जातिगत जनगणना के पक्ष में है। दिल्ली में 31 जुलाई को होने वाली जदयू की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि वह इस पर दोबारा विचार करे।

दशक भर पहले से चुनावी मुद्दा बनता रहा है जातिगत जनगणना : बिहार में जातिगत जनगणना दशक भर पहले से ही चुनावी मुद्दा बनता आया है। नीतीश कुमार शुरू से ही इसके पक्ष में हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। हाल में लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से राज्यमंत्री नित्यानंद राय के जवाब के बाद बिहार में इस मुद्दे पर सर्वाधिक चर्चा हो रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो राज्य सरकार को अपने खर्च पर जातिगत जनगणना कराने की सलाह दे डाली है।

मतभेद को हवा देगा विपक्ष

मानसून सत्र में आगे इस मुद्दे के और जोर पकड़ने के आसार हैं। इससे सत्ता पक्ष के दोनों बड़े दलों (भाजपा और जदयू) में समन्वय का संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में विपक्ष की भी कोशिश इस मुद्दे को हवा देने की होगी।

झारखंड सरकार गिराने की साजिश की जांच को एसआइटी गठित

जागरण टीम, रांची

- विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले की जांच के लिए चार टीमें बनाई

झारखंड सरकार गिराने की साजिश और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को झारखंड पुलिस ने गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी है। इसके लिए एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया है, जिसकी चार टीमें एक साथ काम कर रही हैं। रांची से लेकर दिल्ली व महाराष्ट्र तक में छानबीन चल रही है। विपक्षी दल हमलावर हैं और पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं, झामुमो और कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी है। जल्द ही सारा खेल स्पष्ट हो जाएगा।

विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में गिरफ्तार आरोपितों ने कहा था कि झारखंड के तीन विधायक उनके साथ दिल्ली गए थे और वे दिल्ली के होटल विवांता में रुके थे। ऐसे में दिल्ली गई जांच टीम होटल विवांता के सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर खंगालेगी। होटल से निकलने के बाद विधायक कुछ बड़े नेताओं से भी मिले थे, इस बात की भी पड़ताल पुलिस दिल्ली में करेगी।

वहीं, सोमवार को पुलिस की एक टीम ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले विधायकों और साजिश के मामले में शामिल लोगों के बारे में छानबीन की। एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की गई। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। यहीं कहा जा रहा है कि जांच चल रही है। इस मामले में होटल ली-लैक प्रबंधन ने भी कुछ भी जानकारी देने से इन्कार किया और कहा कि वह पुलिस को सारी बात बता चुके हैं।

गौरतलब है कि सरकार गिराने की साजिश के मामले में पुलिस की टीम ने रांची के होटल ली लैक में 22 जुलाई को छापेमारी की थी। कमरा नंबर 310 से चार सूटकेस, दो लाख रुपये नकद, कई हवाई टिकट, कई मोबाइल फोन के साथ साथ कई कागजात जब्त किए गए। इस मामले में पुलिस ने अभिषेक कुमार दुबे, अमित कुमार सिंह, निवारण महतो को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि महाराष्ट्र के कुछ नेताओं के इशारे पर इन लोगों ने विधायकों की खरीद-फरोख्त की साजिश रची और उनके साथ दिल्ली गए। इन्होंने इस डील में महाराष्ट्र के व्यवसायी जय कुमार बेलखंडे उर्फ बालकुंडे, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर राव बावनकुले, व्यवसायी मनोज भारतीय व नेता चरण सिंह का नाम लिया है।

न मेरी औकात है, न हिम्मत है ऐसा करने की : बावनकुले

राज्य ब्यूरो, मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस बात का खंडन किया है कि वह झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गिराने के प्रयास में शामिल थे। उन्होंने नागपुर में एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि ऐसा करने की न मेरी औकात है, न हिम्मत है। बावनकुले कहा कि न मैं कभी झारखंड गया, न उसके नक्शे से परिचित हूं। ये भाजपा को बदनाम करने की साजिश है।

मुख्यमंत्री की चुप्पी संदेह पैदा करती है : बाबूलाल

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को ट्वीट के माध्यम से राज्य सरकार के मुखिया पर निशाना साधा। एक के बाद एक किए गए कई ट्वीट में बाबूलाल ने कुछ सवाल उठाए हैं। पूछा है कि कांग्रेस के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी के अनुसार उन्हें सरकार गिराने के लिए जनवरी में मंत्री पद के साथ मुंहमांगा ऑफर मिला था। लोग बड़ी मात्रा में पैसे लेकर भी आए थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ने के बजाए डांट कर भगा दिया। यह सूचना उन्होंने कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव को भी दी। इतने गंभीर मामले पर भी सीएम ने ऐसे लोगों को पुलिस से पकड़वाने में न ही गंभीरता दिखाई, न ही पुलिस में कोई शिकायत की। इन षड्यंत्रों के आरोप पर ये चुप्पी संदेह पैदा करती है।

ममता पहुंचीं दिल्ली, 2024 के लिए विपक्षी पार्टियों को करेंगी एकजुट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- बंगाल चुनाव में जीत के बाद ममता का पहला दिल्ली दौरा
- पांच दिवसीय दौरे में विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी दीदी


बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को नई दिल्ली पहुंचीं। इस दौरे में वह विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रेट्र

बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली भाजपा को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने और विरोधी दलों को एकजुट करने की मंशा से सोमवार शाम को दिल्ली पहुंचीं। बंगाल चुनाव में जीत और पांच मई को लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाली दीदी का चुनाव बाद यह पहला दिल्ली दौरा है। ममता के पांच दिवसीय दिल्ली दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। टीएमसी प्रमुख 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में हैं।

विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी ममता : इस दौरे में ममता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रमुख विपक्षी नेताओं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार व अन्य से मुलाकात करेंगी। ममता 26 से 30 जुलाई के दौरे के दौरान संसद भी जा सकती हैं, जहां मानसून सत्र चल रहा है। इधर, दिल्ली रवाना होने से पहले ममता ने दोपहर करीब एक बजे कैबिनेट की विशेष बैठक भी की। इस बैठक में पेगासस मामले की जांच कराने के लिए जांच आयोग के गठन पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक के बाद ममता दोपहर में हवाई मार्ग से रवाना हो गईं और शाम लगभग छह बजे दिल्ली पहुंच गईं।

आज पीएम मोदी के साथ करेंगी मुलाकात, 28 को विपक्षी नेताओं के साथ है बैठक : तृणमूल सूत्रों के मुताबिक, ममता मंगलवार शाम पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगी। उसके बाद राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने की संभावना है। इसके साथ ही 28 जुलाई को दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित बंग भवन में वह दोपहर तीन बजे से विरोधी दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगी। इस बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम समेत टीआरएस, राजद, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, डीएमके और शिवसेना के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। इसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि हाल ही में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले थे। उनकी शरद पवार से भी मुलाकात हुई थी।

भाजपा विरोधी शक्ति के रूप में उभरी हैं ममता बनर्जी : ममता के साथ दिल्ली पहुंचे वरिष्ठ नेता मुकुल राय ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा को उन्होंने पराजित किया है, उसके बाद उनपर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं और वह भाजपा विरोधी शक्ति के रूप में उभरी हैं। राय ने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी कई नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी।

गुजरात विस चुनाव में सिर्फ ममता के भरोसे तृणमूल ठोकेगी ताल

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

बंगाल चुनाव में मिली जीत से उत्साहित तृणमूल कांग्रेस ने गुजरात विस चुनाव में भी ताल ठोकने का फैसला किया है। बंगाल की मुख्यमंत्री व पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी का एक भाषण हाल ही में गुजरात में भी वर्चुअल प्लेटफार्म पर दिखाकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मैदान तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। हालांकि, राजनीतिक जानकार बताते हैं कि गुजरात में भाजपा व कांग्रेस के अलावा किसी तीसरे दल के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है।

इसी साल फरवरी-मार्च में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) व आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) को मिली आंशिक सफलता ने तृणमूल कांग्रेस को प्रेरित किया है। तृणमूल के गुजरात प्रदेश संयोजक जितेंद्र खड़ायता बताते हैं कि पार्टी ने वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में भी एक प्रत्याशी उतारा था, लेकिन वह पूरे मन से चुनाव नहीं लड़ा था। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। इसके लिए, आगामी दिनों में जोरदार चुनाव अभियान चलाया जाएगा। हालांकि, तृणमूल का गुजरात में संगठन तथा कैडर कहीं नजर नहीं आता है, लेकिन ममता बनर्जी के चेहरे पर ही पार्टी यह चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है।

बता दें कि इस साल हुए स्थानीय निकाय चुनाव में आप ने सूरत महानगरपालिका में प्रमुख विपक्षी दल की हैसियत हासिल की है, वहीं एआइएमआइएम ने गोधरा, मोडासा व अहमदाबाद में उपस्थिति दर्ज कराई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गुजरात में भाजपा व कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल के लिए कोई स्थान नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला व केशुभाई पटेल ने भी अपनी-अपनी पार्टी बनाकर तीसरा विकल्प पैदा करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।

तृणमूल से हाथ मिलाने को वाममोर्चा तैयार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए वाममोर्चा तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार है। वाममोर्चा के चेयरमैन विमान बोस ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाजपा विरोधी आंदोलन में वह किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं।

गौरतलब है कि बंगाल में वाममोर्चा-तृणमूल की प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर है। वाममोर्चा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर तृणमूल के खिलाफ पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था। वाममोर्चा और कांग्रेस, दोनों को ही विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। बंगाल फतह करने के बाद मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की निगाहें अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। इस बावत वह भाजपा विरोधी दलों को लामबंद करने में जुट गई हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का भी तृणमूल के प्रति रुख नरम हुआ है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा का 'माइक्रोप्लान', पार्टी से जुड़ा दिखेगा हर वर्ग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- विभागों और प्रकोष्ठों के जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक के कराए जाएंगे सम्मेलन

विपक्ष बयानों से यह संदेश देना चाहता है कि उप्र में भाजपा से हर तबका नाराज है, जबकि भाजपा ने ऐसा माइक्रोप्लान बनाया है कि समाज का हर वर्ग सत्ताधारी दल से संतुष्ट और जुड़ा नजर आए। विभाग और प्रकोष्ठों की अलग-अलग टीमें लक्ष्य बनाकर अपने से संबंधित वर्ग के लोगों को उप्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएंगी। शंकाओं का समाधान कर जिला से प्रदेश स्तर तक सम्मेलन भी कराएंगी।

भाजपा ने हाल ही में विभिन्न प्रकोष्ठ और विभागों के संयोजक और सहसंयोजक बनाए हैं। सोमवार को इन सभी की संयुक्त बैठक प्रदेश मुख्यालय में बुलाकर एक-दूसरे से परिचय कराया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें समाज के सभी वर्गों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति समझाई। लक्ष्य सौंपा कि हर प्रकोष्ठ और विभाग अपने-अपने संबंधित वर्ग से लगातार संपर्क कर उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएगा। विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर कर शंकाओं का समाधान भी करना होगा। मसलन, व्यापार प्रकोष्ठ लगातार व्यापारियों के बीच, मछुआरा प्रकोष्ठ तटीय क्षेत्र में सक्रिय रहकर समझाएगा कि अन्य सरकारों की तुलना में भाजपा सरकार ने उनके समाज या वर्ग के लिए क्या हितकारी कदम उठाए हैं। अगस्त में निचले स्तर तक इन प्रकोष्ठ और विभाग का संगठन खड़ा कर जिला और प्रदेश स्तर पर हर वर्ग का सम्मेलन कराना होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विभागों-प्रकोष्ठों के नवनियुक्त संयोजकों और सह संयोजकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संगठन को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही बनाते हुए समाज के हर वर्ग को भाजपा से जोड़ना है। अपने-अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हुए अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि मोदी-योगी सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना है। हम सब विपक्ष के झूठ को बेनकाब करें।

प्रदेश महामंत्री संगठन ने विभागों-प्रकोष्ठों की कार्ययोजना बताई। कहा कि क्षेत्र और जिला स्तर पर विभाग-प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाए। नए दायित्वों से जुड़े कार्यकर्ता जनता से सीधा संवाद रखें।

आइ-पैक टीम से त्रिपुरा पुलिस ने की पूछताछ

अगरतला, प्रेट्र : त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के एक होटल में पिछले हफ्ते से रह रही चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की इंडियन पालिटिकल एक्शन कमेटी (आइ-पैक) की एक टीम से स्थानीय पुलिस ने पूछताछ की है। टीम राज्य की राजनीतिक स्थिति व तृणमूल कांग्रेस के समर्थन की संभावनाएं तलाश रही है। तृणमूल की त्रिपुरा इकाई ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया, जबकि पश्चिम त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक माणिक दास ने कहा कि नियमित जांच के तहत अगरतला स्थित होटल में आइ-पैक के 22 सदस्यों से पूछताछ की जा रही है।

दास ने संवाददाताओं से कहा, 'करीब 22 बाहरी लोग विभिन्न स्थानों पर घूम रहे थे। चूंकि कोविड प्रतिबंध लागू हैं, इसलिए, हम उनके शहर में आने और ठहरने के कारणों की पुष्टि के लिए पूछताछ कर रहे हैं।' तृणमूल की त्रिपुरा इकाई के अध्यक्ष आशीष लाल सिंह ने कहा, 'यह लोकतंत्र पर हमला है।'

गोवा में मुफ्त बिजली देने पर भाजपा और आप के बीच हुई खुली बहस

पणजी, प्रेट्र : गोवा में आम लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने के मुद्दे पर सोमवार को भाजपा और आम आदमी पार्टी यानी आप के बीच खुली बहस हुई। भाजपा की तरफ से गोवा के बिजली मंत्री निलेश काब्राल और आप की तरफ से दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने सार्वजनिक बहस में हिस्सा लेने के लिए एक मंच पर आए।

दिल्ली में सरकार चला रही आप ने गोवा में सत्ता में आने पर लोगों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। बहस के दौरान जैन ने इस वादे को एक बार फिर दोहराया। काब्राल ने कहा कि भाजपा सरकार मुफ्त बिजली नहीं देगी, लेकिन भारी सब्सिडी जारी रखेगी। आप ने जिस तरह की मुफ्तखोरी का वादा किया है, उससे सरकारी खजाने को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में आप सरकार एक तरफ लोगों को मुफ्त बिजली देती है और दूसरी तरफ से उन पर भारी कर लगाकर उससे होने वाले नुकसान की भरपाई भी कर लेती है।

जैन ने कहा कि उनकी पार्टी गोवा के लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त इसलिए देना चाहती है, ताकि वो जो कर चुकाते हैं उसका वो अधिकतम लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि गोवा के लोग भी मुफ्त बिजली के अधिकारी हैं क्योंकि दिल्ली की तुलना में गोवा का प्रति व्यक्ति बजट बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्हें सुविधाएं खराब दर्जे की मिलती हैं। जैन के मुताबिक गोवा में लगातार बिजली कटौती होती रहती है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

- एक मंच पर साथ आए दोनों राज्यों के बिजली मंत्री, लोगों के बीच अपना-अपना पक्ष रखा
- आप ने मुफ्त बिजली देने का वादा दोहराया, भाजपा ने भारी सब्सिडी जारी रखने की कही बात

गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने किया ट्वीट

बहस के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ट्वीट कर कहा, 'काब्राल ने मिथ्या, झूठ की राजनीति और भ्रामक प्रचार के खिलाफ आज गोवा के लोगों का प्रतिनिधित्व किया और मुफ्तखोरी के मिथक को उजागर किया।' उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आर्थिक सुधारों और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के बीच समुचित संतुलन कायम किया है।

प्रतापगढ़ मेडिकल कालेज के नामकरण पर सियासी रार

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़

अपना दल संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल के नाम पर प्रतापगढ़ मेडिकल कालेज का नामकरण सियासी रार का सबब बन गया है। भाजपा नेता व पूर्व विधायक बृजेश मिश्र सौरभ अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक अपनादल नेता के आगे जिले का स्वाभिमान गिरवी रखा जाता रहेगा। मामले में भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के इस कदम को अपने सहयोगी दल अपना दल (एस) के कोर मतदाताओं (कुर्मी समुदाय) को रिझाने के क्रम में देखा जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले में अपना दल (एस) के दो विधायक हैं।

भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पूर्व विधायक बृजेश मिश्र ने मेडिकल कालेज का नाम स्व. सोनेलाल पटेल के नाम पर करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वह बोले पिछड़े वर्ग के ही किसी व्यक्ति के नाम पर नामकरण करना ही था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम कर देते, कोई आपत्ति नहीं होती। बोले, बाबा राम झुंगुरी सिंह, बाबा रामचंदर, राजा रामपाल सिंह जैसे क्रांतिकारी जिले से थे। राजा दिनेश सिंह, अजीत प्रताप सिंह, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय व राम किंकर जैसे दिग्गज राजनीतिक और स्वामी करपात्री महाराज, जगद्गुरु कृपालु महाराज जैसे धर्म के सच्चे ध्वजवाहक निकले, वहां उनका नाम भूलना दुखद है। बृजेश ने कहा कि अगर जिले के बाहर के ही किसी व्यक्ति का नाम रखना था तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अथवा अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख देते।

क्या है मामला : प्रतापगढ़ के पृथ्वीगंज में 213 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कालेज) का नामकरण हो गया है। यह मेडिकल कालेज अपना दल के संस्थापक डा. सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। इससे संबद्ध चिकित्सालय का नाम अब राजा प्रताप बहादुर चिकित्सालय किया गया है।

अनुप्रिया ने प्रतापगढ़ को बताया सोनेलाल की कर्मस्थली : भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रतापगढ़ डा. सोनेलाल पटेल की कर्मस्थली रही है। वहां ऐसा कोई विरला ही गांव हो, जहां के वंचित समाज के बीच वह न गए हों। डाक्टर साहब के संघर्ष का ही प्रतिफल है कि आज यहां का वंचित वर्ग, दलित-पिछड़ा भी गर्व से सिर उठाकर चलना लगा है।

आशीष पटेल ने बृजेश सौरभ पर की कार्रवाई की मांग : बृजेश मिश्र सौरभ के बयान पर अपना दल (एस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उनके विचार को जातिवादी और सामंतवादी तक बता दिया है। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से सौरभ पर कार्रवाई की मांग की।

विरोध में जनांदोलन की हुई शुरुआत

राजकीय मेडिकल कालेज का नाम डा. सोनेलाल पटेल के नाम पर करने के विरोध में बेल्हा नागरिक स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जनांदोलन की शुरुआत हो गई। सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में लोग कचहरी रोड होते हुए चौक पहुंचे। इनकी मांग है कि मेडिकल कालेज का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अथवा प्रतापगढ़ के किसी महापुरुष के नाम पर किया जाए।

जलवायु परिवर्तन में छिपी है अप्रत्याशित मौसम की जड़

हाल में दुनियाभर में मौसम का अप्रत्याशित रुख देखने को मिला है। कनाडा में लू, उत्तरी अमेरिका में जंगलों में आग, जर्मनी व चीन में बाढ़ की खबरें आ रही हैं। लोग मौसम के ऐसे रुख से हतप्रभ हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि मौसम में इस बदलाव के लिए जलवायु परिवर्तन कहां तक जिम्मेदार है। अमेरिका की कोलोरैडो स्टेट यूनिवर्सिटी के एटमास्फेरिक साइंस के प्रोफेसर स्काट डेनिंग ने इस संबंध में कई पहलुओं की पड़ताल की है।



दुनियाभर में गुस्साए मौसम के लिए जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग

अब तक शोध बताते हैं कि मौसम के अप्रत्याशित बदलावों में से ज्यादातर की वजह मनुष्यों की गतिविधियों के कारण जलवायु में आया बदलाव है। अचानक बहुत तेज गर्मी वाले मौसम के लिए ग्लोबल वार्मिंग काफी हद तक जिम्मेदार है। इसे समझने के लिए फिजिक्स और कंप्यूटर माडल का इस्तेमाल किया जाता है।

गर्म हवाएं
शोध बताते हैं कि इनका कारण काफी हद तक ग्लोबल वार्मिंग है।



तटीय इलाकों में बाढ़
गर्मी के कारण बर्फ पिघलती और समुद्र का स्तर बढ़ता है। इससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा रहता है।



तूफान : गर्म समुद्री सतह से तूफानों को ताकत मिलती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग तूफानों को कितना घातक बनाती है। कुछ अध्ययन कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हवा में बदलाव तूफानों की गंभीरता को कम करता है।



सूखा
गर्म हवा विभिन्न जल स्रोतों, फसलों, जंगलों से ज्यादा पानी को भाप बनाकर उड़ा देता है। इससे सूखे की स्थिति बनती है।

जंगल की आग
गर्म हवाओं के कारण बहुत से पौधे सूख जाते हैं। ऐसे में जरा सी चिंगारी बड़ी आग का कारण बन जाती है।



बहुत ज्यादा बारिश
गर्म हवा के कारण ज्यादा भाप एक से दूसरी जगह पहुंचती है। ऐसे में अचानक तेज बारिश की स्थिति बनती है।

बहुत ज्यादा सर्दी
इसके कारणों पर अध्ययनों में कई अलग-अलग निष्कर्ष सामने आए हैं। इसमें ग्लोबल वार्मिंग की भूमिका पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

दो जरूरी बातें

- पहली बात, इंसान ने प्रकृति में कार्बन डाई आक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का स्तर इतना बढ़ा दिया है कि प्रकृति में बहुत कुछ अब सामान्य स्तर से खिसक चुका है।
- दूसरी बात, मौसम में हो रहे हर अप्रत्याशित बदलाव में ग्लोबल वार्मिंग की भूमिका प्रमाणित नहीं है।

न करें चेतावनी की अनदेखी

अध्ययनों से यह बात स्पष्ट है कि मौसम में बदलावों के लिए इंसान कम जिम्मेदार नहीं है। जितना ज्यादा कोयला, पेट्रोलियम और गैस का प्रयोग होगा, धरती उतनी ज्यादा गर्म होती जाएगी और लोगों को ऐसी गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी कल्पना भी नहीं की गई। मौसम के अप्रत्याशित बदलाव के समय आपदा प्रबंधन के सभी उपाय धरे रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपदाओं से निपटने के साथ-साथ आपदाओं को रोकने की दिशा में कदम उठाए जाएं।

इनपुट : प्रेट्र जागरण इन्फो

इसरो कांड में सीबीआइ जांच कर कानूनन कार्रवाई करे : सुप्रीम कोर्ट

फर्जी जासूसी मामला ▶ डीके जैन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को जासूसी के झूठे मामले में फंसाने के दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस (सेवानिवृत्त) डीके जैन जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी। इस मामले में सीबीआइ ने केस दर्ज किया है। वह ही कानून के मुताबिक जांच कर कार्रवाई करेगी।

वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन (79 वर्ष) को फर्जी जासूसी कांड के आरोप में जेल में लंबा वक्त गुजारने के बाद इस मामले से बरी किया जा चुका है। नारायणन को वर्ष 1994 में तकनीक विदेशियों को बेचने के झूठे आरोप में फंसा कर गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद सीबीआइ ने उन्हें वर्ष 1995 में रिहा किया था। झूठे केस में फंसाने और गिरफ्तारी से हुए अपमान पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से 50 लाख रुपये का मुआवजा दिलाया था। अब यह मामला नंबी नारायणन को झूठे मामले में फंसाने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेवानिवृत न्यायाधीश डीके जैन की कमेटी ने जांच कर कोर्ट को रिपोर्ट दी थी। इसके आधार पर सीबीआइ ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है।

सोमवार को मामले में सुनवाई न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। इस दौरान सीबीआइ ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि केरल के पूर्व पुलिस प्रमुख, सिबि मैथ्यू और अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जा चुकी है। एक आरोपित अधिकारी की ओर से पेश वकील ने जस्टिस डीके जैन कमेटी की रिपोर्ट की प्रति देने की मांग करते हुए कहा कि सीबीआइ उस रिपोर्ट पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रही है। पीठ ने रिपोर्ट दिए जाने की मांग खारिज करते हुए कहा कि जांच और कार्रवाई का आधार जस्टिस जैन कमेटी की रिपोर्ट नहीं होगी। सीबीआइ ने केस दर्ज किया है और वह जांच करके सुबूत एकत्र करेगी और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेगी। जांच रिपोर्ट सिर्फ शुरुआती जानकारी के लिए थी। सीबीआइ ने केस दर्ज किया है और कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई करेगी। पीठ ने कहा कि सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज की है लेकिन उसे वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। इस पर सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज की है और संबंधित अदालत में दाखिल की है और सोमवार को ही उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि पिछले आदेश में कोर्ट ने कहा था कि सीबीआइ जैन कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करेगी। अब सीबीआइ ने आगे की कार्रवाई का फैसला लिया है। एफआइआर दर्ज होने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और अब मामले में इस अदालत के निर्देश की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने जैन कमेटी के काम की सराहना करते हुए कमेटी का काम खत्म होने की घोषणा की। कोर्ट ने रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रजिस्ट्रार की निगरानी में रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2018 को झूठे मामले में फंसाने के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था।

केरल हाई कोर्ट ने दो पूर्व पुलिस अफसरों को दी जमानत : कोच्चि, आइएएनएस : केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को इसरो में फर्जी जासूसी कांड से जुड़े राज्य के दो पूर्व पुलिस अफसरों एस.विजयन और थंपी एस.दुर्गादत्त को अंतरिम जमानत दे दी है। बताया जाता है कि इन्हीं दो अफसरों ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को फर्जी मामले में गिरफ्तार किया था।

एकल जज की पीठ ने सोमवार को कहा कि विजयन और दुर्गादत्त को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और अगर जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करती भी है तो सीबीआइ को उन्हें अदालत में पेश कर उसी दिन जमानत देनी होगी।

साजिश रचने और फर्जी दस्तावेज बनाने के इस मामले में केरल के पूर्व पुलिस प्रमुख और आइबी के अधिकारियों समेत कुल 18 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र पर मांगा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को लेकर उच्चतम न्यायालय का निर्णय मांगा है। उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में यह जानने का प्रयास किया गया है कि न्यायाधीशों के विचारार्थ विषय का निर्धारण कैसे होगा तथा मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र का दायरा कहां तक है। हाई कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य की पीठ से डिवीजन बेंच में एक मामले के स्थानांतरण को लेकर हुए विवाद पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की है। दरअसल हाल ही में न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य को एक मामले की वर्चुअल सुनवाई के दौरान तकनीकी दिक्कत आ गई थी। उस समय उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल का ध्यान आकर्षित किया और उच्च न्यायालय के वर्चुअल मीडिया रखरखाव के प्रभारी केंद्रीय परियोजना समन्वयक को कारण बताओ नोटिस भेजा। नोटिस की प्रतियां उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के महापंजीयक को भी भेजी गई हैं। अगले दिन न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की जानकारी के बिना मामला खंडपीठ को स्थानांतरित कर दिया गया।

मानसून सक्रिय ...अगले तीन-चार दिनों में उत्तर भारत में हो सकती है भारी बारिश

नई दिल्ली, प्रेट्र : अगर अगले तीन-चार दिनों में आप जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सतर्क हो जाइए क्योंकि मौसम विभाग ने 29 जुलाई तक इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान पूर्वी भारत में भी भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग के मुताबिक, उत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है। लेकिन उससे जुड़ा चक्रवातीय सर्कुलेशन उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में बना हुआ है। एक और चक्रवातीय सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के उत्तर में बना हुआ है। इसके प्रभाव से 28 जुलाई के आसपास उत्तर बंगाल की खाड़ी और आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। दोनों चक्रवातीय सर्कुलेशन के प्रभाव से 29 जुलाई तक उत्तरी राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बाद में इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। 27 जुलाई और 28 जुलाई को हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड और 27 जुलाई को उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। जबकि पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में 27 जुलाई से भारी बारिश में कमी आएगी। 27 जुलाई से ओडिशा, बंगाल के गंगा तटीय इलाकों और झारखंड समेत पूर्वी भारत और उससे लगे मध्य भारत के इलाकों में और कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाटी इलाकों में अगले तीन दिनों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। 29 जुलाई से बारिश की तीव्रता में वृद्धि होने का अनुमान है।

किन्नौर हादसा : दरकते पहाड़ की होगी जांच, आवाजाही बंद

जागरण संवाददाता, रिकांगपिओ : पर्यटकों का स्वागत करने वाली किन्नौर जिले की सांगला घाटी आज खामोश है। खामोश भी क्यों न हो क्योंकि कुदरत ने वहां ऐसा कहर बरपाया कि हंसते खेलते नौ पर्यटक मलबे की चपेट में आकर काल का ग्रास बन गए। अब पहाड़ से हो रहे भूस्खलन के कारणों की जांच जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया की टीम करेगी। सांगला-छितकुल सड़क को पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सांगला-छितकुल सड़क पर बटसेरी गांव के पास पहाड़ी दरकने से मलबे की चपेट में आकर मारे गए आठ लोगों के शव सोमवार सुबह नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन भिजवा दिए गए। वहां पर आवासीय आयुक्त इन्हें स्वजन को सौंपेंगे। छग निवासी नेवी में लेफ्टिनेंट अमोच बापट का शव कड़छम स्थित सेना के अधिकारियों को सौंपा गया है।

पीडीपी नेता आतंकी गतिविधियों में शामिल, आरोप तय

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की युवा इकाई के अध्यक्ष वहीद उर रहमान परा के खिलाफ सोमवार को एक विशेष अदालत ने आतंकी गतिविधियों के आरोप तय कर दिए हैं। आतंकियों के साथ कथित तौर पर सांठगांठ करने वाले परा के पत्रकार से राजनीतिक नेता बनने के 13 साल के सफर को पुलिस ने आरोपपत्र में छलकपट, झूठ और दोगलेपन की कहानी बताया है। परा ने राजनीतिक फायदे के लिए आतंकियों से सहयोग लिया और बदले में उन्हें आतंकी हमलों व अन्य गतिविधियों में सहयोग व संरक्षण प्रदान किया।

अदालत ने आरोप तय करते हुए आदेश में कहा है कि परा के खिलाफ कथित तौर पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत किए गए अपराधों को साबित करने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। जज ने अपने आदेश में कहा है कि मैंने पुलिस की रिपोर्ट और गवाहों के बयानों का आकलन किया है। यह सभी उसके द्वारा किए गए अपराधों को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं।

पुलिस ने 19 पेज के आरोपपत्र के साथ करीब एक हजार पन्नों पर आधारित सुबूत भी पेश किए हैं। आरोपपत्र में पाकिस्तानी आतंकी अबु दुजाना और अबु कासिम के साथ भी उसके रिश्तों का जिक्र है। यह दोनों आतंकी मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। वह कई बार इन दोनों आतंकियों से निजी तौर पर मिला।

राष्ट्रविरोधी एजेंडे की जड़ें जमा रहा था महबूबा का करीबी : पीडीपी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के करीबियों में शामिल वहीद परा के वर्ष 2007 में पत्रकार बनने से लेकर राजनीतिक नेता के रूप में 2020 तक के सफर के बारे में पुलिस ने विस्तृत जांच की है। वह 2007 में पाकिस्तान गया था और वहां उसने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन का साक्षात्कार लिया था और पुलवामा में संचालित होने वाले एक केबल टीवी नेटवर्क पर प्रसारित किया था।

कारगिल में गूंजा राग... जान देंगे, पर देश की माटी नहीं

कारगिल विजय दिवस

राज्य ब्यूरो, जम्मू

कारगिल में द्रास युद्ध स्मारक पर सोमवार को भारतीय सेना के जवानों ने जब शेर की गर्जना करते हुए प्रण लिया-जान देंगे, पर नहीं देंगे देश की माटी... तो प्रत्येक देश प्रेमी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। यह मौका था कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ का। यह समारोह इस बार इसलिए भी खास रहा क्योंकि भारतीय सेना 1971 के युद्ध में जीत के 50 साल होने पर वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है।

कारगिल युद्ध के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द को द्रास पहुंचना था, लेकिन बारिश के चलते उनके कार्यक्रम को बदलना पड़ा। हालांकि, उन्होंने उत्तरी कश्मीर में बारामुला में युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति के नहीं पहुंचने पर द्रास युद्ध स्मारक पर लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर और सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

527 जवानों ने दिया था बलिदान : वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने कारगिल की दुर्गम चोटियों पर दुनिया का सबसे कठिन युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 अधिकारी और जवान बलिदान हो गए थे।

वहीं, 1300 से अधिक सैनिक घायल हुए थे। इन्हीं शहीदों की याद में द्रास में तोलोलिंग पहाड़ियों की ओट में स्थित युद्ध स्मारक बनाया गया है। इसमें सभी शहीदों के शिलालेख स्थापित हैं। यहां सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, सेना की 14, 15 व 16 कोर के कोर कमांडरों ने भी शहीदों को सलामी दी। परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार, योगेंद्र सिंह यादव के साथ परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे के भाई मनमोहन पांडे समेत कई शहीदों के स्वजन और युद्ध में हिस्सा ले चुके पूर्व सैनिक भी समारोह में शामिल हुए।

हेलीकाप्टर से पुष्पवर्षा : युद्ध स्मारक पर सुबह 10 बजे हेलीकाप्टर से फूल बरसाकर कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद शहीदों को सैन्य अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। लाइट एंड साउंड के जरिये कारगिल युद्ध की यादों को ताजा किया गया। कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल, तोलोलिंग, मुश्कोह वैली व लमोचन टाप जैसी चोटियों पर सेना ने तिरंगा फहराया था।



कारगिल शहीदों को नमन : राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने सोमवार को कारगिल विजय दिवस पर डग्गर वार मेमोरियल बारामुला में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मौसम खराब होने के कारण राष्ट्रपति द्रास वार मेमोरियल नहीं जा पाए। वर्ष 2019 में भी मौसम खराब होने के कारण वे द्रास नहीं जा सके थे। सौजन्य : पीआरओ

कश्मीर विवि के मेधावियों को आज मिलेगा राष्ट्रपति से सम्मान

राज्य ब्यूरो, जम्मू : कश्मीर विश्वविद्यालय मंगलवार को होने वाले 19वें दीक्षा समारोह के लिए तैयार हैं। समारोह शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआइसीसी) श्रीनगर में होगा। इसमें राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में 84 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। विद्यार्थियों के सोमवार दोपहर को मुख्य कैंपस के गांधी भवन में कोरोना टेस्ट हुए। कुछ विद्यार्थी कोविड टेस्ट करवाने के लिए नहीं पहुंचे। उनको मंगलवार सुबह सात बजे मुख्य कैंपस में रिपोर्ट करनी होगी। वाइस चांसलर प्रो. तलत अहमद का कहना है कि समारोह की सारी तैयारियां कर ली गई हैं।

शहीदों को देश ने किया याद

नई दिल्ली, प्रेट्र : कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर सोमवार को देश ने पाकिस्तान के साथ युद्ध में कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संसद के दोनों सदनों के अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने कारगिल के नायकों को याद किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सैनिकों की बहादुरी हर दिन देशवासियों को प्रेरित करती है। उन्होंने ट्वीट किया, हम उनके बलिदानों को याद करते हैं। हम उनकी बहादुरी को याद करते हैं। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए कारगिल में अपने आप को न्योछावर कर दिया। उनकी बहादुरी हमें हर दिन प्रेरणा देती है।

एएनआइ के अनुसार, संसद के दोनों सदनों में कारगिल के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि दी गई। बहादुर सैनिकों के सम्मान में लोकसभा और राज्यसभा में मौन रखा गया। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, आज हम भारतीय सैनिकों की शहादत को याद कर रहे हैं। इस अवसर पर सदन हमारे सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा करता है। हमारे सैनिकों ने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन सेनाओं को परास्त कर दिया। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमारे बहादुर और निडर सैनिकों ने दुश्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने कारगिल की ऊंचाइयों में हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। सैनिकों का अप्रतिम साहस और उनकी प्रतिबद्धता हमें हमेशा याद रहेगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदानियों को याद करते हुए कहा, आपके अदम्य साहस, वीरता और बलिदान से ही कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा पुनः गर्व से लहराया। देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के आपके समर्पण को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। युद्ध के नायकों को याद करते हुए राजनाथ ने ट्वीट किया, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सैनिकों के बलिदान को मैं नमन करता हूं।

उपराज्यपाल का देश के युवाओं को जम्मू-कश्मीर आने का न्योता

▶ पारदर्शिता, जवाबदेही, लोक केंद्रित नीतियों को सुशासन का हिस्सा बनाया
▶ पुराने कानूनों को बदल कर सुधार लाया गया है

राज्य ब्यूरो, जम्मू

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं को जम्मू-कश्मीर आने का न्योता दिया है। ताकि वे यहां बदलाव और विकास की प्रक्रिया को देखें। सोमवार को शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में तीन दिवसीय यंग थिंकर्स मीट के समापन समारोह में उपराज्यपाल संबोधित कर रहे थे। सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, पारदर्शिता, जवाबदेही, लोक केंद्रित नीतियों को सुशासन का हिस्सा बनाया है। पुराने कानूनों को बदल कर सुधार लाया गया है। सभी क्षेत्रों में लाए सुधार का जिक्र करते हुए सिन्हा ने कहा कि जमीनी सतह पर तरक्की हुई है। ई-आफिस, पंचायतों को मजबूत बनाना, कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना, स्वास्थ्य व शिक्षा के ढांचे को मजबूत करना, निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाना, निर्धारित समय में प्रोजेक्ट पूरे करना, विकास की मजबूत नींव रखना जैसे कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि युवा जनसंख्या की आकांक्षा नए जम्मू-कश्मीर, नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया में अभिन्न हिस्सा बनने की है।

देशभर के युवा यहां आकर देखें कि अब जम्मू-कश्मीर नए पथ पर चल पड़ा है। इस साल 30 हजार प्रोजेक्ट को पूरा करने और पचास हजार युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि मैं उन शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। इंडिया फाउंडेशन के बोर्ड आफ गवर्नेंस श्रोया डोभाल ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को उजागर किया। इंडिया फाउंडेशन युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रही है।

रोक रहे हैं सेना के मददगार गड़ेरियों का पलायन

▶ रगों में दौड़ रहा देशप्रेम, सैकड़ों किलोमीटर दूर से गड़ेरियों की कर रहे मदद
▶ मकसद सिर्फ यही, देश की सुरक्षा पर न आए आंच, सेना हमेशा रहे मजबूत

रोहित देवांगन, राजनांदगांव

फौजी की रगों में किस तरह खून के साथ हर वक्त देशप्रेम दौड़ता रहता है, इसे समझना हो तो नौसेना के सेवानिवृत्त कैप्टन एसी पोखरियाल के बारे में जानना होगा। वे करीब दो साल से लद्दाख के कारगिल से गड़ेरियों का पलायन रोकने की मुहिम में जुटे हुए हैं। उनका मानना है कि पहाड़ी इलाकों में गड़ेरिये भारतीय सेना के प्रमुख सूचना तंत्र और विश्वसनीय मददगार होते हैं। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ की जानकारी गड़ेरियों ने ही भारतीय सेना को दी थी। ऐसे में उनका पलायन नहीं होना चाहिए। कैप्टन पोखरियाल कारगिल के गड़ेरियों को उनके जरूरत के सामान सिलाई मशीन, हैंडपंप, सोलर प्लेट, सोलर हीटर, दरी, मच्छरदानी आदि अपनी पेंशन से खरीदकर भेजते हैं। कुछ लोगों की तो उन्होंने वहां किराना दुकान भी खुलवा दी है। मकसद सिर्फ यही, भारत माता पर आंच न आने पाए।

34 साल की नौकरी के बाद 18 सितंबर 2018 को सेवानिवृत्त हुए कैप्टन पोखरियाल चार माह बाद ही छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला सैनिक वेलफेयर आफिसर बना दिए गए।

करीब सालभर बीतने के बाद उन्हें यूं लगा जैसे जीवन में कुछ अधूरा-अधूरा सा है। देश के लिए योगदान देने को काफी कुछ है। ऐसे में उन्हें कारगिल के उन गड़ेरियों की याद आई, जो अभावों के चलते वहां से पलायन करने लगे हैं। कैप्टन पोखरियाल कहते हैं कि गड़ेरिये सेना की ताकत हैं। उनके जाने से सेना कमजोर हो जाएगी, जो कि किसी भी सूरत में देश के हित में नहीं है। ऐसे में वे गड़ेरियों का पलायन रोकने में जुटे हुए हैं।

वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुटाते हैं जानकारी : कैप्टन पोखरियाल ने बताया कि अपनी मुहिम को अमलीजामा पहनाने के लिए उन्होंने कारगिल में तैनात सेना के अधिकारियों से बात की।



कारगिल में जरूरतमंद गड़ेरियों को सामग्री भेंट करते सेवानिवृत्त कैप्टन एसी पोखरियाल। सौ. स्वयं

कारगिल में शहीदों के स्मारक में रोशन हुई स्वर्णिम विजय मशाल

राज्य ब्यूरो, जम्मू : द्रास वार मेमोरियल में सोमवार को 22वें कारगिल विजय दिवस पर कारगिल की दुर्गम चोटियों पर वीरता के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले सैनिकों समेत उन वीरों के बलिदान को भी याद किया गया, जिन्होंने 50 साल पहले 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। इन शहीदों की याद में निकाली गई स्वर्णिम विजय मशाल को सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने द्रास वार मेमोरियल में स्वीकार कर कारगिल के युद्ध स्मारक में लोगों के दर्शनार्थ स्थापित कर दिया। भारतीय सेना 1971 के युद्ध में जीत के 50 साल पूरे होने पर वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है। इसी उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय मशाल को 16 दिसंबर, 2020 को दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रधानमंत्री ने चार विजय मशाल प्रज्ज्वलित कर देश में चार मुख्य दिशाओं में भेजी थीं। कार्यक्रमों का सिलसिला 16 दिसंबर, 2021 तक जारी रहेगा।

आतंकियों की उम्र एक-डेढ़ सप्ताह से ज्यादा नहीं होती

जाब्यू, नई दिल्ली

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भाजपा ने फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की नीतियों को कठघरे में खड़ा किया। पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की फिलासफी है-नो डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन (कोई फैसला न लेना ही सबसे अच्छा फैसला है)। जबकि राष्ट्रवाद के पर्याय भाजपा का दर्शन है-नो मिशन फार कमीशन (कमीशन की खातिर कोई मिशन नहीं।)

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने एक-एक कर कई प्रसंग याद दिलाए। उन्होंने कहा कि रक्षा और सुरक्षा का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन यह सच्चाई है कि देश जानता है कि कौन से नेता और कौन सी पार्टी के आने से फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके भारत आंखें झुकाकर बात करने वाला नहीं है। हमने वे दिन भी देखे हैं, जब आतंकी यहां आकर आराम से उत्पात मचाता था और गायब हो जाता था। अब भारत में किसी आतंकी की उम्र एक डेढ़ सप्ताह से अधिक नहीं होती है। नड्डा ने कहा कि नेतृत्व का असर होता है। कारगिल युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ युद्ध विराम की भीख मांगने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के पास गए थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका जाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, हमारे जवान मोर्चे पर लड़ रहे हैं। जब तक हमारी सीमा दुश्मनों से मुक्त नहीं हो जाती है, मैं देश छोड़कर नहीं जाऊंगा।

राज्यों ने शुरू की कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी

मुसीबत से मुकाबला ▸ तमिलनाडु सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया

जेएनएन, नई दिल्ली : कोरोना महामारी की दूसरी लहर में स्थिरता आने के साथ ही तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए इससे निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में जो खामियां नजर आई थीं, उन्हें दूर किया जा रहा है। इसी कड़ी में तमिलनाडु सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। हालांकि, अभी केरल और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर देश भर में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। पिछले चार दिनों से प्रतिदिन 40 हजार से कम नए मामले मिल रहे हैं।

तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव डा. जे. राधाकृष्णन ने सोमवार को कहा कि तीसरी लहर का सामना करने के लिए डाक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी संक्रमण पर नजर रखने की योजना तैयार की गई है।

राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में बच्चों के विभाग में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर दिया गया है। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। आक्सीजन और कंसंट्रेटर की भी समुचित व्यवस्था की गई है।

इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक केरल और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर देश के शेष भाग में हालात नियंत्रण में हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 40 हजार से कम नए मामले मिले हैं, जिनमें से अकेले केरल से ही साढ़े 17 हजार मामले हैं। मृतकों की संख्या पांच सौ से कम है। हालांकि, सक्रिय मामलों में इस दौरान करीब तीन हजार की वृद्धि हुई है।


जम्मू-कश्मीर के रामबन में सोमवार को टीकाकरण अभियान के दौरान एक व्यक्ति को कोरोना रोधी टीका लगाती स्वास्थ्यकर्मी। एएनआइ

गोवा, ओडिशा व आंध्र के लोगों को नहीं दिखानी होगी रिपोर्ट

राब्यू, लखनऊ : गोवा, ओडिशा व आंध्र प्रदेश से यूपी आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। इन राज्यों में कोरोना का पाजिटिविटी रेट तीन प्रतिशत से कम होने के कारण अब यह बिना रोक-टोक उप्र आ सकेंगे।

देश में कोरोना की स्थिति	
24 घंटे में नए मामले	39,361
कुल सक्रिय मामले	4,11,189
24 घंटे में टीकाकरण	20.45 लाख
कुल टीकाकरण	43.51 करोड़
सोमवार सुबह आठ बजे तक कोरोना की स्थिति	
नए मामले	39,361
कुल मामले	3,14,11,262
सक्रिय मामले	4,11,189
मौतें (24 घंटे में)	416
कुल मौतें	4,20,967
ठीक होने की दर	97.35 फीसद
मृत्यु दर	1.34 फीसद
पाजिटिविटी दर	3.41 फीसद
सा. पाजिटिविटी दर	2.31 फीसद
जांचें (रविवार)	11,54,444
कुल जांचें	45,74,44,011

ट्रेन से हरिद्वार पहुंचे 325 कांवड़ यात्रियों को शटल बसों से वापस भेजा

- जीआरपी ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की
- हरकी पैड़ी जाने से पहले ही जीआरपी ने रोका

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

कांवड़ मेला प्रतिबंधित होने के बावजूद ट्रेन से हरिद्वार पहुंचे 325 कांवड़ यात्रियों को जीआरपी ने हरकी पैड़ी जाने से रोक दिया। उन्हें रेलवे स्टेशन से शटल बसों में बैठाकर वापस भेज दिया गया। अधिकांश यात्री हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली निवासी थे। उन्हें जिले की सीमा से बाहर छोड़ा गया है।

कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर कांवड़ मेले पर प्रतिबंध लगाया गया है। कांवड़ यात्रियों को रोकने के लिए बार्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जबकि जीआरपी की टीमें रुड़की, लक्सर, ज्वालापुर और हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की चेकिंग कर रही हैं। सोमवार को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थानाध्यक्ष अनुज सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने मसूरी, बाड़मेर, अमृतसर, हावड़ा एक्सप्रेस में चेकिंग कर यात्रियों से पूछताछ की। इनमें 325 कांवड़ यात्रियों को जीआरपी ने पहचाना। सभी को हरकी पैड़ी जाने से रोकते हुए रेलवे स्टेशन परिसर से ही शटल बसों में बैठाकर जनपद की सीमाओं से बाहर भेज दिया गया। रेलवे पुलिस के एएसपी मनोज कत्याल ने बताया कि ट्रेनों की चेकिंग में मिले कांवड़ यात्रियों को शटल बसों से भेजा गया है। रेलवे स्टेशनों पर लगातार चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। **तीनों रूटों पर प्रचार-प्रसार कर रही टीमें :** उत्तराखंड आने के लिए रेलवे के तीन रूटों से कांवड़ यात्री व अन्य श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। रेलवे पुलिस के एएसपी मनोज कत्याल ने बताया कि दिल्ली से मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरियाणा, पंजाब से सहारनपुर होते हुए रुड़की पहुंचने वाले दोनों रूटों के अलावा लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद से लक्सर पहुंचने वाले तीनों रूटों पर जीआरपी की टीमें कांवड़ मेला प्रतिबंधित होने का प्रचार-प्रसार कर रही हैं। हरिद्वार नहीं आने की अपील भी की जा रही है।

हरिद्वार आए अहमदाबाद के छह श्रद्धालु कोरोना पाजीटिव

जागरण संवाददाता, हरिद्वार : अहमदाबाद (गुजरात) के छह श्रद्धालु कोरोना पाजीटिव पाए गए हैं। इनमें दो श्रद्धालु अस्थि विसर्जन और चार श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आए थे। बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट हरिद्वार आने पर रेलवे स्टेशन पर ही उनका टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट पाजीटिव आने पर इन सभी को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। इसके बाद से प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार ने कांवड़ मेला प्रतिबंधित किया है। इसके चलते हरिद्वार जिले की सीमाओं और रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग कर कांवड़ यात्रियों को उनके राज्यों को लौटाया जा रहा है। वहीं श्रद्धालु, पर्यटक व यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है। रेलवे पुलिस के एएसपी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि एहतियात के साथ तुरंत कोरोना पाजीटिव श्रद्धालुओं को कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया है।

44 दिन में लगाईं 41 लाख अतिरिक्त डोज

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)

देशभर में कोरोना के टीके की किल्लत के बीच अच्छी खबर है। ज्यादातर राज्यों ने शीशी में उपलब्ध एक अतिरिक्त डोज का भी सदुपयोग किया है। एक मई से 13 जुलाई के बीच 29 राज्यों ने कोविशील्ड की शीशी में उपलब्ध यह अतिरिक्त डोज 41 लाख 11 हजार लोगों को लगाई है। इसमें सबसे अधिक पांच लाख 88 हजार अतिरिक्त डोज तमिलनाडु ने निकालीं। मप्र में छठवें स्थान पर है। प्रदेश में इस अवधि में तीन लाख 55 हजार अतिरिक्त डोज लगाई गईं।

मध्य प्रदेश में टीका बेकार जाने का प्रतिशत जनवरी से अप्रैल के बीच चार तक पहुंच गया था। इसके बाद एक-एक डोज का उपयोग करने की रणनीति बनी। इसी के चलते एक मई से 13 जुलाई के बीच तीन लाख 55 हजार अतिरिक्त डोज लगाई गईं। हालांकि इससे पहले की अवधि 16 जनवरी से 30 अप्रैल तक बेकार हुई डोज की संख्या इतनी ज्यादा थी कि तीन लाख 55 हजार से घटाने के बाद इसकी संख्या दो लाख 88 हजार 046 ही होती है। अतिरिक्त डोज को कोविन पोर्टल पर ऋणात्मक रूप में दर्शाया जाता है। मप्र के राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि एक बार शीशी खोलने के बाद बची डोज चार घंटे में खराब हो जाती हैं।

ऐसे निकाली जाती है अतिरिक्त डोज : राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि भोपाल जिले के फंदा ब्लॉक में एक नर्स शीशी में बची हुई डोज नष्ट करने के लिए रख रही थी। नर्स ने ही खुद सुझाव दिया कि यह अतिरिक्त डोज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लगाई जा सकती है। इसके बाद से ही अतिरिक्त डोज को लगाने की शुरुआत प्रदेश में हुई। एक वीडियो बनाकर यूट्यूब के जरिए टीकाकरण करने वाले कर्मचारियों तक पहुंचाया गया। उन्होंने बताया यह अतिरिक्त डोज करीब दो महीने पहले तक शीशी के साथ फेंक दी जाती थी लेकिन अब इसका उपयोग किया जा रहा है।

अतिरिक्त डोज निकालने वाले टॉप छह राज्य

तमिलनाडु	5,88,243
पश्चिम बंगाल	4,87,147
गुजरात	4,62,819
केरल	3,92,409
महाराष्ट्र	3,59,493
मध्य प्रदेश	3,55,259

डोज निकालने वाले मप्र के टॉप पांच जिले

जिला	निकाले गए अतिरिक्त डोज
उज्जैन	27,978
भोपाल	27,977
मुरैना	21,019
इंदौर	15,779
बैतूल	15,359

(टीकाकरण की शुरआत से लेकर 17 जुलाई तक की स्थिति)

बायोलाजिकल ई की वैक्सीन सितंबर तक

नई दिल्ली, एएनआइ : देश को सितंबर तक एक और कोरोना रोधी वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलाजिकल ई सितंबर तक अपनी कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स लांच कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने तीसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया है। सरकार ने प्री-क्लीनिकल स्टेज फेज तीन के अध्ययन से पहले ही वैक्सीन की खरीद का आर्डर भी दे दिया है।

माना जा रहा है कि बायोलाजिकल ई अगस्त के आखिर तक इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लाइसेंस (ईयूएल) के लिए आवेदन करेगी। कंपनी सरकार को दिसंबर तक 30 करोड़ डोज की आपूर्ति भी करेगी। बता दें कि एक दिन पहले ही विशेषज्ञ समिति ने तीसरी लहर को रोकने के लिए टीकाकरण की गति बढ़ाने का सिफारिश की है। सरकार से कोरोना से बचाव के उपायों को भी सख्ती लागू कराने का सुझाव दिया गया है, जिसमें मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखने और कंटेनमेंट जोन शामिल हैं।

तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने को शिक्षक दंपती मुफ्त बांट रहे सब्जियां

राधाकिशन शर्मा/बिलासपुर (नईदुनिया)

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के वनांचल स्थित ग्राम बंशीताल की प्राथमिक शाला में दिनेश प्रसाद चंद्रा व उनकी पत्नी गायत्री चंद्रा शिक्षक हैं। अध्ययन-अध्यापन के साथ ही वे बागवानी का शौक भी रखते हैं। वे बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए घर-घर जाकर मुफ्त में हरी सबजियों का वितरण करते हैं। यह उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा है। मोहल्ला क्लास में आने वाले बच्चों को भी सेहत के प्रति जागरूक करते हैं। आदिवासियों को जैविक खेती की पाठ भी पढ़ा रहे हैं।

शिक्षक चंद्रा की बाड़ी में लौकी, बरबट्टी, कुंदरू, करेला और टमाटर के पौधे फलों से लदे हुए हैं। वे पूरी तरह जैविक खेती कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग भी करते हैं। उनकी बाड़ी में चारो तरफ हरियाली ग्रामीणों को इस कदर लुभा रही है कि शाम को ग्रामीण बाड़ी घूमने के लिए आते हैं। उन्हें शिक्षक दिनेश प्रसाद जैविक खेती के फायदे बताना नहीं भूलते। बाड़ी में ही एक किनारे उन्होंने गहरा गड्ढा बनाया है। यहां गोबर इकठ्ठा करते हैं। गोबर के साथ ही पत्ते, पैरा डाल देते हैं। जब यह पूरी तरह सड़ जाता है तब इसे वे फलों के पौधों में घोल बनाकर डालते हैं। खास बात ये कि बाड़ी से निकलने वाली सबजियों को वे ग्रामीणों को मुफ्त में देते हैं। वे बताते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चों के प्रभावित होने की आशंका के चलते उन्होंने अपना पूरा ध्यान बाड़ी में ज्यादा से ज्यादा सबजियों के उत्पादन की ओर लगा रखा है। गांव के प्रत्येक घर में हरी सब्जी बांटना और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हरी सबजियां खिलाने माता-पिता को समझाइश देना भी नहीं भूलते। मोहल्ला क्लास में करते हैं काउंसिलिंग शिक्षक दंपती स्कूल परिसर में ही मोहल्ला क्लास लगाते हैं। जिस दिन क्लास में कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता है बच्चों से अनुपस्थिति का कारण पूछते हैं। पढ़ाई के बाद शिक्षक दंपती सीधे बच्चे के घर पहुंच जाते हैं।

कुछ बंदिशों के साथ उमरा यात्रा को अनुमति

जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद : पिछले साल कोरोना काल में हज के साथ बंद हुई उमरा यात्रा सऊदी सरकार ने कुछ बंदिशों के साथ शुरू कर दी है। फिलहाल भारत के साथ पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, तुर्की, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और लेबनान देश के जायरीनों को अनुमति दी गई है।

हज सेवा समिति के प्रदेश सचिव मौलाना आलम मुस्तफा याकूब का कहना है कि सऊदी सरकार ने 10 अगस्त से शुरू हो रहे मोहर्रम के पहले दिन से उमरा की अनुमति दी है। मौलाना ने बताया कि उमरा यात्रा पूरे साल चलती है, जबकि हज इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने की नौ से 13 तारीख तक होता है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जब पूरी दुनिया में लाकडाउन या उस जैसी बंदिशें लगीं तो हज और उमरा पर भी रोक लगा दी गई थी। इस साल भी हज यात्रा नहीं हुई।

राष्ट्रीय फलक

काली कमाई खपाने को पत्नी का खाता कराया सक्रिय

पोर्नोग्राफी रैकेट मामला

जागरण संवाददाता, कानपुर

उद्योगपति और फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का प्रोडक्शन हाउस चलाने वाले अरविंद श्रीवास्तव ने पोर्न फिल्मों की काली कमाई खपाने के लिए अपनी पत्नी हर्षिता श्रीवास्तव के निष्क्रिय बैंक खाते को सक्रिय कराया था। पांच साल पहले पर्याप्त बैलेंस और लगातार संचालन न होने से निष्क्रिय घोषित खाते में अब 2.36 करोड़ रुपये हैं। पहले 50-50 हजार रुपये खाते में डाले गए। 2019 से इसमें नियमित रूप से 10-10 लाख रुपये प्रतिमाह आने लगे।

पोर्न एप को लेकर चर्चा में आए राज कुंद्रा के करीबी सहयोगी अरविंद का घर कानपुर में श्याम नगर में है। उसकी पत्नी हर्षिता ने शादी के 14 वर्ष बाद अपनी मां नीरजा के साथ 2015 में संयुक्त बचत खाता बर्रा आठ स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में खोला था। इसी बैंक में उसका लाकर भी है। खाता खुलने के बाद न तो उसमें ज्यादा रकम आई न ही लाकर का किराया चुकाया गया। कम बैलेंस और नियमित संचालन न होने से बैंक ने पांच अक्टूबर, 2016 को इस खाते को निष्क्रिय घोषित कर दिया। तब खाते में सिर्फ एक हजार रुपये ही पड़े थे। दो माह यह खाता निष्क्रिय रहा। इसके बाद 13 दिसंबर, 2016 को अरविंद ने रुपये जमा कर और केवाइसी देकर खाते को दोबारा सक्रिय कराया। रुपये जमा होते ही लाकर का तीन हजार किराया भी उसमें से कट गया। हर्षिता का यह स्माल साइज का लाकर है। इसके बाद कुछ माह तो थोड़े-थोड़े रुपये आते रहे, लेकिन उसके बाद यूपीआइ भुगतान के जरिए 50-50 हजार रुपये आने शुरू हो गए। 2019 में रुपये आने की रफ्तार बढ़ी। उस समय से इस खाते में नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) के जरिए 10-10 लाख रुपये प्रतिमाह आने लगे।

हर्षिता के खाते में सबसे ज्यादा 12 लाख रुपये एक बार में आए। कई बार तो एक-एक सप्ताह के अंदर ही ये रकम भेजी गई। ज्यादातर रुपये अरविंद श्रीवास्तव ने ही भेजे। खाता दोबारा सक्रिय किए जाने के बाद लगभग चार वर्ष में ढाई करोड़ रुपये आए, लेकिन इसमें से करीब 14 लाख रुपये ही निकाले गए। इसमें 2,36,01,620 रुपये जमा हैं। हर्षिता की मां नीरजा का कहना है कि उन्हें खाते में जमा रुपयों के बारे में मालूम नहीं है।

बदायूं में प्रेमी के घर जाने पर अड़ी बेटी की हत्या

जागरण संवाददाता, बदायूं : कच्चे प्यार में नाबालिग बेटी इस तरह बहकी कि सोमवार तड़के प्रेमी के पास जाने के लिए घर से निकलने लगी। आहट सुनकर पिता की आंख खुली। बेटी को रोका तो नोकझोंक होने लगी। इससे बौखलाये पिता ने कमरे में रखा तमंचा उठाया और बेटी के सिर में गोली मार दी। उसके सिर का आधा हिस्सा उड़ गया। पुलिस ने आरोपित पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मामला उप्र के बदायूं का है। बिल्सी के गांव परौली में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी का गांव के ही युवक से डेढ़ वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गांव में इसके चर्चे हुए तो पिता को नागवार गुजरा, उस पर बंदिश लगा दी। किशोरी इसका विरोध करती थी। सोमवार तड़के वह सोकर जल्दी उठी और घर से जाने लगी। पिता ने बेटी से बाहर जाने की वजह पूछी तो उसने बेहिचक कह दिया कि प्रेम के रास्ते से पीछे नहीं हटेगी। वह प्रेमी के साथ रहेगी। पिता ने पहले समझाया। न मानने पर कड़ा रुख अपनाया तो, दोनों में नोकझोंक होने लगी। बेटी ना मानी तो पिता ने कमरे में रखा तमंचा उठाया। पुलिस के अनुसार तड़के 4.30 बजे बेटी से कहा कि उसने जिद नहीं छोड़ी तो जान से मार देगा। बेटी फिर भी नहीं मानी तो, उसके सिर में गोली मार दी। इससे वहीं मौत हो गई। ग्रामीणों के फोन पर पहुंची पुलिस ने आरोपित पिता को गिरफ्तार कर लिया।

ट्रैक्टर चलाकर संसद जा रहे राहुल को थाने ले गई पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। पुलिस ने रास्ते में ही रोककर थाने ले गई। वहां से राहुल को संसद भवन जाने की अनुमति दे दी, लेकिन रणदीप सुरजेवाला समेत अन्य नेताओं को शाम तक हिरासत में रखा।

कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे राहुल गांधी ने कहा कि वह संसद तक किसानों की आवाज पहुंचाने आए हैं क्योंकि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है। कृषि कानून वापस लिए जाएं क्योंकि इससे केवल दो-तीन उद्योगपतियों को लाभ पहुंचने वाला है। राहुल गांधी के साथ पार्टी के सांसद प्रताप सिंह बाजवा, रवनीत सिंह बिट्टू, दीपेंद्र सिंह हुड्डा व जसबीर सिंह गिल के साथ ही वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला तथा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। ये सभी 'कृषि कानून वापस लो' व 'किसानों की मांगें पूरी करो' का प्लेकार्ड लिए हुए थे। डीसीपी दीपक यादव के मुताबिक सुबह करीब 10.50 बजे संसद मार्ग इलाके में पुलिसकर्मियों ने देखा कि राहुल गांधी व रणदीप सुरजेवाला के साथ बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद भवन की तरफ आ रहे हैं। ट्रैक्टर राहुल गांधी चला रहे थे।

महिलाओं ने कहा, कृषि क्षेत्र में उनके योगदान को मिले सम्मान


कृषि सुधार कानूनों के विरोध में सोमवार को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद में महिला आंदोलनकारियों को संबोधित करती अभिनेत्री गुलपनाग। संजय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कृषि कानूनों के विरोध में जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में तीसरे दिन महिलाओं ने संसद की तरह कार्यवाही चलाई। अब तक एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर बनाया जाता था, लेकिन महिलाओं ने दो डिप्टी स्पीकर बनाए। इस दौरान 110 महिलाओं ने आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, 2020 पर चर्चा की और बाद में इसे खारिज करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। वहीं, पंचायतों और स्थानीय निकायों की तर्ज पर संसद व विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 फीसद आरक्षित करने की मांग की गई। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चल रहे प्रदर्शन में अभिनेत्री गुल पनाग भी पहुंचीं। उन्होंने कृषि कानूनों को रद करने की मांग की। मोर्चा से जुड़ीं मेधा पाटकर ने कहा कि कृषि कानूनों को गलत ढंग से संसद में पारित किया गया है, इसलिए इनमें संशोधन नहीं, बल्कि इन्हें रद किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सोमवार को हुई चर्चा में दो प्रस्ताव प्रमुख रूप से पारित किए गए।

झूठ के सहारे राजनीतिक वजूद बचाने की कोशिश में राहुल : तोमर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कृषि सुधार कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर पर संसद भवन आने और इन कानूनों को किसान विरोधी बताने पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। तोमर ने कहा कि राहुल गांधी पर झूठ के सहारे राजनीतिक वजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचने के बाद राहुल गांधी के बयानों के बारे में पूछे जाने पर तोमर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार झूठ के सहारे राजनीतिक वजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। चुनावी घोषणापत्र में कांग्रेस ने इन कानूनों को लाने का वादा किया था और अब जब मोदी सरकार इन कानूनों को लेकर आई है, तो वे विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि या तो कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में झूठ बोला था या फिर राहुल गांधी विरोध कर अब झूठ बोल रहे हैं। दोनों सही कैसे हो सकता है?

डीएनए एक है

मानते हैं इस्लाम के उसूल, अपने हिंदू गोत्र पर भी है गर्व

यहां बरसों से पल्लवित हो रही सांप्रदायिक सौहार्द की बगिया, ईद के साथ-साथ दीपावली भी मिलकर मनाते हैं

सतीश राघव, सोहना (गुरुग्राम)

अरावली की तलहटी में बसा सोहना। करीब 70 हजार की आबादी वाला एक कस्बा जहां हिंदू-मुस्लिम एकता और भाईचारे के गुलदस्ते से इंसानियत की खुशबू महकती है। सोहना से सटे नूंह जिले के गांवों की बात करें तो यहां मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहे हैं। वर्षों पुराने अपने सोच, संस्कृति और विचारों में हिंदुत्व को सम्मानजनक स्थान देते हैं।

नूंह जिले में मुस्लिम समुदाय के लोग स्वयं को भगवान श्रीराम की संतान बताते हैं। गांव हाजीपुर के खुर्शीद बताते हैं कि उनके परदादा यानी चौथी पीढ़ी के पूर्वज का नाम कंवर सिंह था, जिनका बढ़गुजर यानी राघव गोत्र था। आज भी उनकी बढ़गुजर गोत्र के नाम से ही पहचान है। गांव सामदीका के सुभान खान के मामा हरि सिंह, रवि सिंह, जयसिंह का गहलोत गोत्र था।

अपने हिंदू पूर्वजों पर गर्व करने वाले ये लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की उस बात की पुष्टि करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सबका डीएनए एक है। आज भी नूंह जिले में रहने वाले मेव (मुस्लिम) समुदाय के लोगों का आसपास के गांवों के हिंदू परिवारों से भाईचारा है जिसे सभी लोग बरसों बीत जाने के बाद भी निभाते आ रहे हैं।

सोहना की शाही मस्जिद के इमाम मौलवी नसीम अहमद बताते हैं कि उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे और वह भगवान श्रीराम को मानते हैं। खुद उनका मूल राजपूत बहुल भोंडसी गांव है और गोत्र बढ़गुजर था। उनका मानना है कि मजहब कोई भी हो सबसे पहले भाईचारा व इंसानियत है। पूरा परिवार आज भी होली, दीपावली व ईद साथ मिल-जुल कर मनाता है। सैकड़ों वर्ष बाद भी इनकी परंपराएं नहीं बदलीं। शादियों में हिंदुओं की तरह ही रस्में होती हैं। सोहना के आसपास मुस्लिम बहुल गांवों में बसने वाले लोगों में नंबरदार सूबे खान, नूरदीन, सुलेमानी बताते है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। हजारों साल बीत जाने के बाद भी वे अपने हिंदू पूर्वजों का सम्मान करते हैं। इनका कहना है कि बरसों से आपसी भाईचारे की जो मिसाल बनी है, उसे निभाते रहेंगे।

अब्दुल्ला से अमित, अकबर से अरविंद, रोशन अली से फिर बने रोशन

जासं, मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर में मतांतरण कर अमित से अब्दुल्ला, अरविंद से अकबर व रोशन लाल से रोशन अली बनने वाले तीन युवकों ने फिर हिंदू धर्म में वापसी की। सोमवार को हिंदू जागरण मंच ने शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी कराई। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष नरेंद्र पंवार व महामंत्री अंकुर राणा ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व मतांतरण करा मुस्लिम बनाए गए छपार थानाक्षेत्र के गांव बढ़ीवाला निवासी अकबर उर्फ अरविंद, चरथावल निवासी अब्दुल्ला उर्फ अमित, राजस्थान के भरतपुर व हाल में चरथावल निवासी रोशन अली उर्फ रोशन लाल की सोमवार को घर वापसी कराई गई। मंदिर में मुंडन करा गंगाजल से तीनों को नहलाया गया। हवन-यज्ञ कराया गया। बघरा से पहुंचे यशवीर महाराज व चरथावल के आचार्य अभयदेव वेद गुरुकुल से आचार्य योगेश ने विधि विधान से तीनों का शुद्धिकरण कराया। तीनों युवकों ने यज्ञ में आहुति देकर भविष्य में कभी धर्म परिवर्तन नहीं करने का संकल्प लिया।

अपने धर्म में वापसी पर खुशी जताई

युवक रोशन लाल ने कहा कि नशीला पदार्थ खिलाकर उनका मतांतरण कराया गया था। मकान पर भी कब्जा कर लिया था।

चुनौतियों के बीच केरल के स्कूली छात्रों ने खड़ा किया रोजगार

कन्नूर, एएनआइ : चुनौतियों के सामने अक्सर लोग बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उन्हें मात देते हुए नया मुकाम हासिल कर लेते हैं। केरल के गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले तीन छात्रों के सामने कोविड-19 ने ऐसी ही चुनौतियां पेश कीं, लेकिन उन्होंने सूझबूझ और हिम्मत का परिचय देते हुए न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि रोजगार खड़ाकर परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत भी किया।

कन्नूर जिले के चेरुपुझा निवासी सेबस्टियन भाइयों की मुसीबतों की शुरुआत 10 पहले हुई थी, जब उनके पिता की मौत हो गई थी। फिलहाल तीनों भाइयों में सबसे छोटा सेंजो कक्षा सात में पढ़ता है, जबकि दो अन्य भाई स्टीफन व सोनी क्रमशः कक्षा आठ व 12 में पढ़ते हैं। पिता की मौत के बाद मां ने सिलाई का काम करके घर को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाफी था। इसलिए, तीनों बच्चों को पढ़ने के साथ-साथ छोटे-मोटे काम भी करने पड़े। इस बीच कोरोना महामारी आ गई और उनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया। सोनी के अनुसार, 'हमने पड़ोसियों के खराब बल्ब की मरम्मत शुरू की। लाकडाउन के कारण हमें मरम्मत के आर्डर ज्यादा मिलने लगे, क्योंकि सारी दुकानें बंद थीं। इससे घर के साथ-साथ पढ़ाई के खर्च की भी पूर्ति होने लगी।' उन्होंने कहा, 'शुरुआत में हम एलईडी और स्पाटलाइट की मरम्मत करते थे। धीरे-धीरे हमने बाजार से कच्चे माल की खरीद शुरू की और भाइयों की मदद से एलईडी बल्ब बनाना शुरू किया। लोगों को हमारे बल्ब पसंद आ रहे हैं।' स्टीफन व सोनी आसपास में समाचार पत्र व पंफलेट आदि का भी वितरण करते हैं।

सरकार ने खरीदा रिकार्ड 433.3 लाख टन गेहूं

नई दिल्ली : सरकार ने रबी सीजन 2021-22 में कुल 433.3 लाख टन गेहूं की खरीद की है। खाद्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि चालू मार्केटिंग सीजन 2021-22 में विभिन्न राज्यों से कुल 433.3 लाख टन गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदारी हुई है। इसके तहत करीब 49.15 लाख किसानों को 85,581.39 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। पिछले रबी मार्केटिंग वर्ष में 389.9 लाख टन गेहूं की खरीदारी हुई थी। (प्रेट्र)



कोरोना की दूसरी लहर से आर्थिक विकास पर थोड़ा-बहुत असर दिख सकता है। लेकिन इकोनामी की बुनियाद मजबूत है।
– कुमार मंगलम बिड़ला, चेयरमैन, आदित्य बिड़ला ग्रुप

सेंसेक्स	52,852.27	▼ 123.53
निफ्टी	15,824.45	▼ 31.60
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 46,753	▲ 169
चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 66,080	▲ 396
डॉलर	₹74.42	▲ 0.02
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 73.85	

रियल एस्टेट के करीब तिहाई कर्ज पर संकट

नई दिल्ली, प्रेट्र : बैंकों और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर को दिए गए कर्ज के एक-तिहाई हिस्से पर खासा दबाव है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनाराक के अनुसार विभिन्न बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) ने सेक्टर को करीब 10,000 करोड़ डालर (वर्तमान भाव पर लगभग 7.4 लाख करोड़ रुपये) का कर्ज दिया हुआ है। इसमें से 67 फीसद या 6,700 करोड़ डालर (लगभग 4,95,800 करोड़ रुपये) का कर्ज पूरी तरह सुरक्षित है, यानी बैंकों को यह हिस्सा मिल जाना लगभग निश्चित है। हालांकि शेष हिस्से पर या तो थोड़ा-बहुत, या अत्यधिक दबाव है। एनाराक की शाखा एनाराक कैपिटल ने रिपोर्ट में कहा है, सेक्टर को दिए गए 15 फीसद कर्ज यानी 1,500 करोड़ डालर (करीब 1.11 लाख करोड़ रुपये) के कर्ज पर थोड़ा-बहुत दबाव है। बैंकों को इस रकम में से मूलधन वापस मिल जाने की उम्मीद है।

छह कंपनियों को मिली आइपीओ लाने की अनुमति

पूंजी जुटाने वालों में हाउसिंग फाइनेंस से लेकर स्पेशलिटी केमिकल्स सेक्टर तक की हैं कंपनियां

नई दिल्ली, प्रेट्र: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने छह कंपनियों को प्रारंभिक पब्लिक आफर (आइपीओ) लाने की इजाजत दे दी है। इनमें एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, कारट्रेड टेक, सुप्रिया लाइफसाइंस, क्रस्ना डायग्नोस्टिक्स, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर तथा एमी आर्गेनिक्स के नाम शामिल हैं। इन कंपनियों ने इस वर्ष मई और जून में आइपीओ के लिए आवेदन दिए थे। इन्हें सेबी ने 19-23 जुलाई के दौरान मंजूरी प्रदान की।

मर्चेंट बैंकिंग से जुड़े स्रोतों के अनुसार एप्टस वैल्यू के आइपीओ का अनुमानित आकार 2,600-3,000 करोड़ रुपये है। इसके तहत कंपनी ताजा शेयर जारी कर 500 करोड़ रुपये जुटाएगी। वहीं, आफर फार सेल (ओएफएस) के माध्यम से अधिकतम 6,45,90,695 शेयर जारी कर शेष रकम जुटाई जाएगी।

आनलाइन आटो क्लासिफाइड प्लेटफार्म कारट्रेड टेक अपने आइपीओ के तहत पूरी रकम ओएफएस के माध्यम से 1,23,54,811 शेयर जारी कर जुटाएगी। इस ओएफएस में सीएमडीबी 2 (16.07 लाख इक्विटी शेयर), हाईडेल इंवेस्टमेंट लिमिटेड (53.79 लाख शेयर), मैक्रिची इंवेस्टमेंट्स पीटीई लिमिटेड (35.68 लाख शेयर), स्प्रिंगफील्ड वेंचर इंटरनेशनल (11.24 लाख शेयर) तथा बीना विनोद सांघी (1.83 लाख शेयर) जैसे निवेशक हिस्सेदारी लेंगे। कारट्रेड की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी और कंपनी को वारबर्ग पिंकस, टेमासेक, जेपी मोर्गन तथा मार्च कैपिटल जैसे दिग्गज निवेशकों का समर्थन हासिल है।

एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (एपीआइ) निर्माण क्षेत्र की अग्रणी घरेलू कंपनी सुप्रिया लाइफसाइंस अपने आइपीओ के तहत ताजा शेयर जारी कर 200 करोड़ रुपये जुटाएगी। इसके साथ ही कंपनी के प्रमोटर सतीश वामन वाघ अपने 1,000 करोड़ रुपये मूल्य तक के शेयर बेचेंगे। इस आइपीओ से हासिल रकम का उपयोग कर्ज के भुगतान तथा पूंजीगत खर्च के अलावा सामान्य कारपोरेट कामकाज के लिए किया जाएगा।

सेबी के पास उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार क्रस्ना डायग्नोस्टिक्स के आइपीओ के तहत ताजा पूंजी जारी कर 400 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। वहीं, कंपनी ओएफएस के माध्यम से अधिकतम 94,16,377 शेयर जारी कर रकम जुटाएगी। इन विधियों से हासिल रकम का उपयोग पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश व महाराष्ट्र में नए डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करने समेत कर्ज भुगतान करने और सामान्य कामकाज में किया जाएगा।

विजया डायग्नोस्टिक्स के आइपीओ के तहत पूरी तरह ओएफएस के माध्यम से रकम जुटाई जाएगी। ओएफएस में कंपनी के प्रमोटर एस. सुरेंद्रनाथ रेड्डी समेत काराकोरम लिमिटेड तथा केदारा कैपिटल अल्टरनेटिव इंवेस्टमेंट फंड जैसे निवेशकों के कुल 3,56,88,064 इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे। इस आइपीओ के बाद कंपनी में प्रमोटर और इन निवेशकों की हिस्सेदारी 35 फीसद घट जाएगी।

स्पेशलिटी केमिकल निर्माता कंपनी एमी आर्गेनिक्स के आइपीओ के तहत ताजा शेयर जारी कर 300 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। कंपनी ओएफएस के माध्यम से अधिकतम 60,59,600 इक्विटी शेयर जारी कर अतिरिक्त पूंजी जुटाएगी।

आइपीओ से हासिल रकम में से 140 करोड़ रुपये का उपयोग कर्ज चुकाने तथा 90 करोड़ रुपये का सामान्य कामकाज के लिए किया जाएगा। कंपनी मुख्य रूप से अनुसंधान आधारित स्पेशलिटी केमिकल्स का निर्माण करती है।



आंकड़ों में आइपीओ

3,000 करोड़ रुपये तक का हो सकता है एप्टस वैल्यू का आइपीओ

200 करोड़ ताजा शेयर से, बाकी ओएफएस से जुटाएगी सुप्रिया लाइफसाइंस

400 करोड़ रुपये जुटाएगी ताजा शेयर से क्रस्ना डायग्नोस्टिक्स, बाकी ओएफएस से जुटाए जाएंगे

रोलेक्स रिंग्स का आइपीओ 28 को खुलेगा

आटो कंपोनेंट निर्माता कंपनी रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड का 731 करोड़ रुपये का आइपीओ 28 जुलाई को खुलेगा। कंपनी ने 880-900 रुपये प्राइस बैंड निर्धारित किया है। आइपीओ का सब्सक्रिप्शन 30 जुलाई को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए यह 27 जुलाई को खुल जाएगा। कंपनी ताजा शेयर जारी कर 56 करोड़ जुटाएगी। शेष ओएफएस के माध्यम से जुटाई जाएगी। इसके तहत कंपनी निवेशक रिवेंडेल पीई एलएलसी के अधिकतम 75 लाख इक्विटी शेयर बेचेगी।

हुडको में सरकारी हिस्सेदारी बिक्री आज से

सरकार हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन (हुडको) में अपनी आठ फीसद या करीब 16.01 करोड़ शेयर की बिक्री प्रक्रिया मंगलवार से शुरू करेगी। संस्थागत निवेशक 45 रुपये प्रति शेयर के भाव से यह हिस्सेदारी खरीद सकेंगे। इस आठ फीसद हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को करीब 720 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। इसके तहत सरकार ओएफएस के माध्यम से करीब पांच फीसद हिस्सेदारी बिक्री का लक्ष्य रख रही है। सरकार के पास अतिरिक्त ढाई फीसद हिस्सेदारी बिक्री का विकल्प रहेगा।

जस्ट डायल के लिए ओपन आफर 13 सितंबर से

जस्ट डायल का अतिरिक्त 26% शेयर खरीदने के लिए रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) 13 सितंबर को ओपन आफर लांच करेगी। यह आफर 24 सितंबर तक खुला रहेगा। इससे पहले आरआरवीएल ने इसी माह जस्ट डायल में 40.95% हिस्सेदारी 3,497 करोड़ में खरीदने की घोषणा की थी।

पहली तिमाही में प्रत्यक्ष कर 109 फीसद बढ़ा

70.3 फीसद की अप्रत्यक्ष कर में बढ़ोतरी, सरकार का कर्ज घटने की उम्मीद

- चालू वित्त वर्ष में आरबीआइ से लांग टर्म सिक्युरिटीज खरीदने की कोई योजना नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2021) में राजस्व प्राप्ति की स्थिति मजबूत होने से सरकार पिछले साल के मुकाबले कम कर्ज लेगी। इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 109.3 फीसद और अप्रत्यक्ष कर में 70.3 फीसद बढ़ा। समीक्षाधीन अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह 2,46,519.82 करोड़ रुपये और अप्रत्यक्ष कर संग्रह 3,11,398 करोड़ रुपये रहा। पिछले वर्ष समान अवधि में प्रत्यक्ष कर के मद में 1,17,783.87 करोड़ रुपये और अप्रत्यक्ष कर के रूप में 1.82,862 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि चालू वित्त वर्ष में आरबीआइ से लांग टर्म सिक्युरिटीज खरीदने की कोई योजना नहीं है। वहीं, सरकार पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम कर्ज लेगी। सरकार के अनुसार गत वित्त वर्ष 2020-21 के राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए बाजार से 10,48,788 करोड़ रुपये उधार लेने का संशोधित बजटीय अनुमान है। वहीं चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए बाजार से 9,17,708 करोड़ रुपये उधार लेने का बजटीय अनुमान रखा गया है। संशोधित अनुमान के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष के लिए सरकार 2,25,000 करोड़ रुपये का शार्ट टर्म कर्ज, जो चालू वित्त वर्ष में सिर्फ 50,000 करोड़ रुपये तक जाने का अनुमान है।

सरकार की नोट छापने की कोई योजना नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद को बताया कि नोट छापने को मौजूदा संकट का विकल्प बनाना सरकार की योजना में शामिल नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि संकट से उबरने के लिए नोट छापने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

सीतारमण ने बताया, बीते वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी में 7.3% गिरावट का अनुमान है। उनका कहना था, सरकार ने कोरोना संकट के दौरान पिछले वर्ष से अब तक अभूतपूर्व उपाय किए हैं, जिनके चलते बीते वित्त वर्ष में विकास दर की गिरावट इस स्तर पर सिमटती दिख रही है। कई अर्थशास्त्रियों व विशेषज्ञों ने सरकार को कोरोना संकट से पैदा हुई मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से उबरने को करेंसी नोट छापने व रोजगार बचाने की सलाह दी है। नोट छापने को राजकोषीय घाटे का मौद्रीकरण कहा जाता है। इसके तहत सरकार के खर्च की भरपाई को आरबीआइ सरकारी सिक्युरिटीज की प्राथमिक बाजार से खरीदारी कर लेता है।

एमएसएमई का बकाया भुगतान 45 दिनों में : वित्त मंत्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र एमएसएमई का सभी बकाया भुगतान 45 दिनों में कर देगा। उनके अनुसार एमएसएमई के बकाया भुगतान के मामले में केंद्र सरकार का यही रुख है और वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रही हैं। वित्त मंत्री के इस आश्वासन से एमएसएमई को बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना की पहली लहर के बाद से ही एमएसएमई नकदी की संकट के जूझ रहे हैं। बकाए के भुगतान से एमएसएमई की नकदी की समस्या दूर होगी। वहीं, एमएसएमई के पास नकदी आने से अर्थव्यवस्था की रिकवरी भी तेज होगी। देश की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 29 फीसद है।

सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री ने केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों (पीएसयू) और केंद्रीय विभाग पर एमएसएमई के बकाया को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के दौरान यह आश्वासन दिया। बाद में वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट के जरिये भी बताया कि केंद्र 45 दिनों में एमएसएमई का पूरा बकाया भुगतान कर देगा। उन्होंने संसद में कहा कि एमएसएमई का बकाया काफी गंभीर मामला है और इस मुद्दे पर पूर्व एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी के साथ चर्चा की गई थी। गडकरी ने एमएसएमई के बकाए पर चिंता जताते हुए वित्त मंत्री से इस मसले पर बात की थी।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ● फाइल फोटो

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पीएसयू और केंद्रीय विभाग पर एमएसएमई के बकाया को लेकर दिया आश्वासन

सीतारमण ने कहा कि पिछले साल से केंद्र सरकार अपने सभी विभागों के बकाए की समीक्षा कर रही है जिन्हें एमएसएमई को भुगतान करना है। इनमें केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियां भी शामिल हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि बकाया भुगतान के नियम के मुताबिक 45 दिनों की समय-सीमा का उल्लंघन नहीं हो। एमएसएमई मंत्रालय पिछले डेढ़ वर्षों में बकाया भुगतान में तेजी के लिए कई बार वित्त मंत्रालय को पत्र लिख चुका है। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी केंद्रीय विभागों को एमएसएमई के भुगतान को लेकर चुस्त रहने के लिए कहा जा चुका है। राज्यों को जीएसटी भुगतान के संबंध में वित्त मंत्री ने बताया कि इस संबंध में अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी। उन्होंने कहा कि जब हम सरकारी बकाया की बात करते हैं तो उनमें केंद्र के साथ केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियां, राज्य सरकार और उनकी कंपनियां भी शामिल होती हैं।

मसूर दाल से आयात शुल्क हटा

राहत

- महंगाई पर काबू पाने के फैसले की जानकारी संसद में दी गई
- बीते फसल वर्ष में 2.56 करोड़ टन दालों के उत्पादन का अनुमान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : घरेलू बाजार में मसूर की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने को सरकार ने आनन-फानन में सोमवार को इस पर आयात शुल्क खत्म कर दिया है। सेस में भी 50 फीसद की कटौती कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में जारी अधिसूचना को संसद के दोनों सदनों में रखा। मसूर दाल से हटे सीमा शुल्क व घटे एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का फैसला मंगलवार से प्रभावी हो जाएगा।

सीतारमण ने कहा, मसूर दाल के आयात पर लगने वाला 10 फीसद शुल्क हटा दिया गया है। दाल के आयात पर एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस को 20 से घटाकर 10 फीसद कर दिया गया है। इससे कीमत घटने की उम्मीद है। देश में मसूर दाल की कीमतों में भारी तेजी का रुख रहा है। इस वर्ष पहली अप्रैल को मसूर दाल का मूल्य जहां 70 रुपये प्रति किलो था, जो बढ़कर 85 रुपये पर पहुंच गया है। महंगाई का यह आंकड़ा केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित है।

कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते फसल वर्ष में देश में कुल 2.56 करोड़ टन दालों के उत्पादन का अनुमान है। इसमें मसूर दाल की हिस्सेदारी 12.6 लाख है। इसकी घरेलू खपत आमतौर पर 20 लाख टन के आसपास होती है। ऐसे में इस दाल का कुल आयात आठ से नौ लाख टन होता है। दलहन फसलों में मसूर का एमएसपी 51 रुपये प्रति किलो घोषित किया गया था।

राष्ट्रीय फलक

सैनिक की पत्नी को 41 वर्ष बाद मिली स्पेशल फैमिली पेंशन

जासं, लखनऊ : 'सेना की यूनिट में रोजाना सुबह होने वाली पीटी-परेड में शामिल जवान उस समय भी आन डयूटी ही रहता है। पीटी सेना की नियमित दिनचर्या का ही हिस्सा है। ऐसे में पीटी के दौरान यदि जवान की मृत्यु हो जाती है तो उसे आन ड्यूटी मानकर आश्रित को स्पेशल पेंशन दी जानी चाहिए।' सशस्त्र बल अधिकरण की लखनऊ बेंच ने पति की मौत के बाद स्पेशल फैमिली पेंशन के लिए भटक रही महिला के पक्ष में आदेश देते हुए यह तीखी टिप्पणी की है।

उप्र के फर्रुखाबाद निवासी जगदीश 1971 में सेना की आर्टिलरी रेजीमेंट में गनर के रूप में भर्ती हुए थे। 1980 में पीटी के दौरान उनके सीने में तेज दर्द होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां उनको हार्ट फेल होने के कारण मृत घोषित किया गया। गनर जगदीश की पत्नी कलश कुमारी के स्पेशल फेमिली पेंशन के आवेदन को रक्षा मंत्रालय ने 1981 में खारिज करते हुए 1982 में सामान्य फैमिली पेंशन जारी कर दी। 2016 में वादिनी ने फर्रुखाबाद सैनिक कल्याण बोर्ड के डीएस यादव से मुलाकात की, जिसके बाद उनके माध्यम से अधिवक्ता विजय कुमार पांडेय ने सशस्त्र बल अधिकरण की लखनऊ बेंच में वाद दायर किया। भारत सरकार ने 36 साल बाद मुकदमा दायर करने का विरोध करते हुए वाद को तत्काल खारिज किए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि न्याय पाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो अपने अधिकार के प्रति सजग हों, न कि अपनी सुविधानुसार कोर्ट आने वाले को। अधिवक्ता विजय कुमार पांडेय ने दलील दी कि एक विधवा जिसकी आय का स्रोत न हो, कानूनी बारीकियों से परिचित न हो और लगभग अनपढ़ हो, उनके पेंशन संबंधी मामले को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। इसमें भी भारत सरकार ने कहा कि वादिनी का पति ड्यूटी पर नहीं था। इस पर वादिनी के अधिवक्ता ने ड्यूटी की परिभाषा और स्पेशल फैमिली पेंशन संबंधी कानूनों का हवाला दिया।

सुनवाई के बाद अधिकरण के न्यायिक सदस्य अवकाशप्राप्त न्यायधीश उमेश चंद्र श्रीवास्तव और वाइस एडमिरल (अवकाश प्राप्त) अभय नाथ कार्वे ने कहा कि वादिनी स्पेशल फैमिली पेंशन की हकदार है।

जुड़वा भाइयों के हत्याकांड में पांच को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : चित्रकूट के जुड़वा भाइयों श्रेयांश और प्रियांश के बहुचर्चित अपहरण-हत्याकांड के मामले में मध्यप्रदेश के जिला सतना की एंटी डकैती कोर्ट ने पांचों आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीन आरोपितों को अपहरण व हत्या और दो को अपहरण और साजिश रचने का दोषी माना है। मामले में छह आरोपितों में से एक ने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी। इस फैसले का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। मासूमों के पिता ने फैसला आने के बाद कहा कि ऐसे निर्दयी लोगों को जीने का हक नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि बांदा निवासी अभियुक्त राजू की मां माया ने बेटे को गलत फंसाने की बात कहते हुए हाई कोर्ट में गुहार लगाने की बात कही है।


तेल व्यापारी के जुड़वा बेटे श्रेयांश और प्रियांश। फाइल फोटो

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की कर्वी कोतवाली की सीतापुर पुलिस चौकी क्षेत्र के रामघाट निवासी आयुर्वेदिक तेल कारोबारी बृजेश रावत के छह वर्षीय जुड़वा बेटों प्रियांश और श्रेयांश का 12 फरवरी, 2019 को नकाबपोश बदमाशों ने तमंचा दिखाकर अपहरण कर लिया था। अपहरण मध्यप्रदेश के नयागांव थानांतर्गत सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के सद्गुरु पब्लिक स्कूल परिसर से ही छुट्टी के बाद बस से किया गया था। पहले आरोपितों ने दो करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी। 19 व 20 फरवरी की रात एक करोड़ और फिर 20 लाख की फिरौती पर अपहरणकर्ता बच्चों को छोड़ने को राजी हुए थे। अगले दिन फिरौती की रकम चौसठ बल्लान क्षेत्र में छोड़े जाने के बाद भी पहचान उजागर होने के डर से दोनों की हत्या करके शव जंजीर से बांध कर बांदा में यमुना नदी के औगासी घाट पुल के पास फेंक दिए गए थे। घटना के मास्टरमाइंड ट्यूशन टीचर रामकेश यादव ने सेंट्रल जेल सतना में फंदा लगाकर जान दे दी थी।


मासूम जुड़वा भाइयों की हत्या के आरोपितों को कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को अदालत में पेश किया गया। सौजन्य : पुलिस

अपहरण-हत्याकांड : सजा दिलाने में यह बने मददगार

- 76 गवाह, 6000 पेज की चार्जशीट
- 348 दस्तावेज और 176 आर्टिकल
- आरोपितों से 2000 से ज्यादा सवाल
- बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए 18 गवाह, सुबूतों के आगे दलील फेल

'पेड़ नहीं कटेंगे, सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई घटाने पर विचार करें'

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जिला बरनाला के काहनेके-रुड़के कलां संपर्क मार्ग के दोनों तरफ खड़े 900 पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि सड़क को चौड़ा करने में पेड़ बाधा बन रहे हैं तो उन्हें बचाने के लिए इस योजना पर फिर से विचार कर करके सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई कम की जाए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा व जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ पर आधारित डिविजन बेंच ने यह आदेश पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट एचसी अरोड़ा की ओर से दायर एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिए। हाई कोर्ट ने सरकार को यह आदेश भी दिया है कि इस मामले में याची ने 19 जुलाई को जो मांग पत्र दिया था, सरकार उस पर उचित निर्णय ले। याची ने कोर्ट को बताया कि काहनेके से रुड़के कलां को जोड़ने वाली सड़क 10 फुट चौड़ी है। इसे 18 फुट (दोनों तरफ चार-चार फुट) चौड़ा किया जा रहा है। वास्तव में यह सड़क कच्चे हिस्से को मिलाकर 27 फुट चौड़ी है।

अलीगढ़ में चोरी कर बच्चा बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 16 गिरफ्तार

जासं, अलीगढ़

पुलिस ने अंतरजनपदीय बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है। गिरोह के 16 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें नौ महिलाएं भी शामिल हैं। इनके पास से पांच बच्चे भी बरामद किए गए हैं। इनमें तीन बच्चे अलीगढ़ व दो बच्चे गाजियाबाद से चोरी किए गए थे। ये झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को निशाना बनाते थे। दो से पांच लाख रुपये में बच्चे का सौदा करते थे।

अलीगढ़ के सरोज नगर में सड़क किनारे झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले राजा की दो वर्षीय बेटी 22 जून की रात लापता हो गई थी। इससे पहले भी गांधीपार्क क्षेत्र से ऐसे ही परिवारों के दो बच्चे लापता हुए थे। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बच्चों की तलाश के लिए 'आपरेशन खुशी' चलाया था। एसएसपी ने बताया कि रविवार शाम पुलिस ने बोरना तिराहे से दुर्योधन (गंगा नगर, अलीगढ़), अनिल (साहिबाबाद, गाजियाबाद) और शुभम (हसायन, हाथरस) को गिरफ्तार किया। दुर्योधन मूलरूप से एटा जिला के ग्राम अनारपुर और अनिल मप्र के सागर जिले का है।

यहां से बरामद हुए बच्चे : गंगानगर कालोनी में बबली के घर से दो बच्चे, बाबा कालोनी में आकाश, खैर में संजय गोयल, देहली गेट में जाहिद के घर से एक-एक बच्चा बरामद कर लिया गया। ये बच्चे डेढ़ से तीन वर्ष की उम्र के हैं।

पकड़े गए अन्य आरोपित : धर्मवीर उर्फ धौनी, संजय गोयल, बबली, रश्मि, अनीता, नेहा, रेखा, चांदनी उर्फ राजकुमारी, गुलफ्शा, जाहिद, रुकसार और हाजरा। ये सभी अलीगढ़ जिले के हैं।

दो बच्चे गाजियाबाद से चुराए थे : एक बच्चा फरवरी में विजय नगर से और दूसरा मार्च में साहिबाबाद से चोरी किया था।

महिलाएं करती थीं बच्चों की सौदेबाजी : एसएसपी ने बताया कि दुर्योधन, अनिल व शुभम बच्चा चुराने के बाद गिरोह की महिला सदस्यों के पास ले जाते थे। ये महिलाएं सौदेबाजी में मध्यस्थता करती थीं। किसी परिवार से संपर्क कर दो से पांच लाख रुपये में बच्चे को बेच दिया जाता था।

खेल जागरण

भारतीय निशानेबाजों की नजरें पदक पर

टोक्यो, प्रेट्र : टोक्यो ओलिंपिक में अभी तक निराश करने वाले भारतीय निशानेबाज जब मंगलवार को उतरेंगे तो उनकी कोशिश निराशा को पीछे छोड़कर देश को पदक दिलाने की रहेगी। मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी से अच्छे प्रदर्शन की आस रहेगी जो अपनी अभी तक अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। इस स्पर्धा में अभिषेक वर्मा और यशस्विनी सिंह देसवाल की जोड़ी भी उतरेगी जो पदक जीतने की कोशिश करेंगे। वहीं, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इलावनिल वलारिवान और दिव्यांश सिंह पंवार जबकि अंजुम मौदगिल और दीपक कुमार की मिक्स्ड टीम देश को इस खेल में पदक दिलाने के लिए उतरेंगे।

हाकी : आस्ट्रेलिया से बुरी तरह शिकस्त का सामना करने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने तीसरे पूल ए मैच में अपने से कम रैंकिंग वाली टीम स्पेन के खिलाफ लय और टूटे हुए मनोबल को फिर से हासिल करने की कोशिश करेगी। अपने अभियान के शुरुआती मैच में न्यूजीलैंड पर 3-2 से जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम को दूसरे मैच में दुनिया की नंबर एक टीम ऑस्ट्रेलिया से 1-7 के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इस बड़ी पराजय ने भारतीय टीम की हर कमजोरी को उजागर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में पहले क्वार्टर के बाद भारतीय रक्षापंक्ति में मनमाने तरीके से सेंध लगाते हुए गोलों की बौछार कर दी और टूर्नामेंट में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अप्रैल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के ग्राहम रीड के कोच बनने के बाद से यह भारत की सबसे बड़ी हार भी थी। भारत की कमजोर रक्षापंक्ति पर ऑस्ट्रेलिया ने मैच की शुरुआत से ही दबाव डालकर पहले हाफ में चार और दूसरे हाफ में तीन गोल किये। न्यूजीलैंड के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरी तरह से बेरंग नजर आयी। इन खेलों से पहले कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के बाद भारतीयों को वापसी करने के बारे में अच्छी तरह से पता है। मुख्य कोच ग्राहम रीड स्पेन के खिलाफ दमदार वापसी की उम्मीद करेंगे। वही दूसरी तरफ स्पेन की कोशिश भी टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करने की होगी। उसने अर्जेंटीना को 1-1 की बराबरी रोका था लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उसे 3-4 से हार का सामना करना पड़ा।

टेबल टेनिस : स्टार महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा के बाहर होने के बाद अब टेबल टेनिस में पदक की उम्मीद अचंता शरत कमल से ही बची है जो तीसरे दौर के मुकाबले में चीन के मा लोंग के खिलाफ उतरेंगे। शरत कमल अनुभवी खिलाड़ी हैं लेकिन उनका प्रदर्शन ऊपर-नीचे रहता है इसलिए देखना यह है कि उनका यह सफर कहां तक चलता है।

मुक्केबाजी : छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मेरी कोम को छोड़ दिया जाए तो अभी तक पुरुष मुक्केबाजों ने खराब प्रदर्शन किया है और तीन मुक्केबाज अभी तक बाहर हो गए हैं। ऐसे में लवलीना बोरगेहन से उम्मीद रहेगी कि वह जीत से आगाज करें।

खिलाड़ियों को लंबे बाल कटवाने होंगे : लक्ष्मीरतन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान व पूर्व खेल राज्यमंत्री लक्ष्मीरतन शुक्ला ने सोमवार को फिटनेस शिविर के साथ अंडर-23 कोच के रूप में नई पारी का आगाज किया। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए कड़े नियम बनाए हैं, जिसमें इंटरनेट मीडिया से दूर रहना और लंबे बालों को कटवाना शामिल है। घरेलू क्रिकेट में दिग्गज खिलाड़ी रहे शुक्ला 2016 में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे और इस साल जनवरी तक वे खेल राज्यमंत्री थे। क्रिकेट पर अधिक ध्यान देने के लिए शुक्ला ने मंत्रिपद और राजनीति छोड़ दी थी। 40 साल के शुक्ला ने कहा, 'मैंने लड़कों से कहा है कि वे इंटरनेट मीडिया पर कुछ भी पोस्ट न करें। उन्हें शिष्टाचार और अनुशासन बनाए रखना होगा। लंबे बाल वाले खिलाड़ियों को तुरंत अपने बाल कटवाने होंगे। टीम एकजुटता के लिए उन्हें बांग्ला भाषा सीखनी होगी। जूनियर स्तर से सीनियर टीम में खिलाड़ियों का आना बेहद महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि मैंने जूनियर खिलाड़ियों के साथ काम करने का विकल्प चुना है।' फिटनेस शिविर चार घंटे से अधिक समय चला, जिसमें 60 क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया।

टी-20 सीरीज भी जीतने के इरादे से उतरेगा भारत

कोलंबो, प्रेट्र : भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ मंगलवार को यहां दूसरे मैच में जीत के साथ तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी तो उसे उम्मीद होगी कि संजू सैमसन अपनी प्रतिभा पर खरे उतरकर अपने प्रदर्शन में निरंतरता ला पाएंगे।

श्रीलंका को पहले मुकाबले में हराने के बाद भारत के विजयी संयोजन में बदलाव करने की संभावना नहीं है। हालांकि उम्मीद है कि पृथ्वी शा और सूर्यकुमार यादव कम से कम यह मुकाबला जरूर खेलेंगे और भारत के सीरीज जीतने की स्थिति में उन्हें अंतिम मैच से आराम दिया जा सकता है। दोनों खिलाड़ियों को ब्रिटेन में विराट कोहली की टीम के साथ जुड़ना है। दोनों को चोटिल शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर के विकल्प के तौर पर भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। स्टैंड बाई खिलाड़ियों में शामिल बंगाल के बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को मुख्य टीम में शामिल किया है जबकि स्टैंड बाई तेज गेंदबाज आवेश खान बायें अंगूठे में चोट के कारण स्वदेश लौटेंगे। गिल के पैर में घुटने के नीचे के अगले हिस्से में चोट है जबकि सुंदर के दायें हाथ की अंगुली में चोट है।

योजना में बदलाव होने की स्थिति में खराब फार्म से जूझ रहे मनीष पांडे पर देवदत्त पडीक्कल और रुतुराज गायकवाड़ को तरजीह दी जा सकती है। मंगलवार को नजरें सैमसन पर होंगी जिनसे काफी उम्मीदें हैं लेकिन, उन्हें जब भी भारतीय जर्सी में खेलने का मौका मिला तो वह इन उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहे।

सैमसन को शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी के पर्याप्त मौके मिले लेकिन, इसके बावजूद वह आठ मैचों में 13.75 की औसत से ही रन बना पाए। सामने आ रहे प्रतिभावान खिलाड़ियों को देखते हुए सैमसन की राह इस प्रदर्शन के साथ आसान नहीं होने वाली। प्रदर्शन के आधार पर रिषभ पंत ने सैमसन को काफी पीछे छोड़ दिया है जबकि इशान किशन ने भी सीमित मौके मिलने पर प्रभावी प्रदर्शन किया है।

दैनिक जागरण
भक्ति में भाव ही सर्वोपरि होता है

विपक्षी एका का भविष्य

विपक्षी एकता को बल देने के इरादे से दिल्ली आईं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने इस उद्देश्य में कितना सफल होंगी, यह समय ही बताएगा, लेकिन उन्हें जिस तरह विपक्षी दलों को गोलबंद करने वाली संभावित नेता के तौर पर देखा जा रहा है, वह कांग्रेस की दयनीय दशा को बयान करने के लिए पर्याप्त है। राष्ट्रीय दल होने के नाते विपक्षी एका का जो काम कांग्रेस को करना चाहिए, वह यदि किसी क्षेत्रीय दल को करना पड़ रहा है तो इससे कांग्रेसी नेतृत्व की कमजोरी का ही पता चलता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस या तो विपक्षी दलों को एकजुट करने में अपना हित नहीं देख रही है या फिर उसमें यह काम करने की सामर्थ्य ही नहीं रह गई है। जो भी हो, यह किसी से छिपा नहीं कि उसकी राजनीतिक हैसियत एक क्षेत्रीय दल जैसी होती जा रही है। बड़े राज्यों में उसका वजूद केवल पंजाब और राजस्थान तक ही सीमित है। वह अपने गढ़ों में या तो सिमटती जा रही है या फिर उसकी राजनीतिक जमीन पर क्षेत्रीय दल काबिज होते जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है तो उसकी अपनी राजनीतिक अदूरदर्शिता के कारण। वह न तो वास्तविक मुद्दों को उभार पा रही है और न ही ऐसे किसी विमर्श का निर्माण कर पा रही है, जिससे विपक्षी दल उसके नेतृत्व में एकजुट हो सकें और जनता का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सके।

क्या जो काम कांग्रेस नहीं कर सकी, उसे तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी कर सकेंगी? इस सवाल का जवाब बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण का परिचय दे पाती हैं या नहीं? क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ यह एक बुनियादी समस्या है कि वे अपने राज्य के आगे और कुछ देख ही नहीं पाते। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी उनका रवैया संकीर्णता से भरा और कई बार तो राष्ट्रहित की अनदेखी करने वाला होता है। इससे भी बड़ी समस्या है उनकी समाजवादी सोच। उन्हें लगता है कि सब कुछ सरकार को करना चाहिए। इस मामले में ममता बनर्जी भी अपवाद नहीं। यह विडंबना ही है कि वह राष्ट्रीय नेता तो बनना चाहती हैं, लेकिन बंगाल में अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने का इरादा रखती हैं-ठीक वैसे ही जैसे एक समय वाम दल करना चाहते थे। ममता बनर्जी की मानें तो बंगाल में चुनाव बाद कहीं कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हुई और इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट फर्जी है। ममता चाहे जो दावा करें, वह बंगाल को जिस तरह संचालित कर रही हैं, उससे यह नहीं लगता कि वह राष्ट्रीय राजनीति को कोई सही दिशा दे सकेंगी।

एनआइए जांच से उम्मीद

पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को तोड़ना पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। कई ऐसे मामले हैं, जिन्हें पुलिस अब तक हल नहीं कर सकी है। पिछले साल अमृतसर में पकड़ी गई करीब 197 किलोग्राम हेरोइन का मामला भी ऐसा ही है, जिसे पुलिस अभी तक हल नहीं कर सकी है। यह मामला दरअसल 2018 का है, जब इटली में बैठे तस्करी के मुख्य आरोपित अमृतसर के सिमरनजीत सिंह संधू ने करीब तीन सौ किलो हेरोइन पाकिस्तान से गुजरात के मांडवी में पहुंचाई थी। यहां से पिछले साल हेरोइन पंजाब लाई गई और पुलिस ने करीब 197 किलो हेरोइन यहां बरामद की। अब तक इस मामले की जांच पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स कर रही थी। इस मामले में शिअद नेता अनवर मसीह सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कानून के लंबे हाथ इस धंधे की बड़ी मछलियों तक नहीं पहुंच सके। यही कारण है कि अब इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंप दी गई है। इससे उम्मीद जगी है कि शीघ्र कुछ और गिरफ्तारियां होंगी तथा कई बड़ी मछलियां भी कानूनी शिकंजे में फंसी दिखेंगी। यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को और पहले सौंपा जाना चाहिए था, क्योंकि जांच और कार्रवाई में देरी से अपराधियों के हौसले और बढ़ जाते हैं। कदाचित यही कारण है कि प्रदेश में हेरोइन तस्करी का धंधा बदस्तूर जारी है। जून में भी पाकिस्तान से ही ड्रोन के माध्यम से पंजाब में 120 किलोग्राम हेरोइन भेजी गई, जिसकी तलाश में पुलिस अब तक छापे मार रही है। इन मामले में जिन लोगों को पकड़ा गया था, उनसे पता चला कि हेरोइन की यह खेप अमेरिका में बैठे दमनजीत सिंह काहलों ने भिजवाई थी। हेरोइन व अन्य नशीले पदार्थों के अलावा सीमापार से हथियारों की सप्लाई भी पंजाब में की जा रही है। यह बड़ा रैकेट है, जिसके तार पाकिस्तान, इटली से लेकर अमेरिका तक जुड़े हुए हैं। इसलिए इसकी जांच एनआइए को देना ही उचित है। उम्मीद है कि एनआइए जल्द से जल्द देश में छिपे तस्करों के मददगारों को बेनकाब करेगी, अपितु विदेशों में छिपे बैठे देश के दुश्मनों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा।

> यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को और पहले सौंपा जाना चाहिए था, क्योंकि जांच और कार्रवाई में देरी से अपराधियों के हौसले बढ़ जाते हैं

देश को चाहिए मुफ्तखोरी से मुक्ति



भरत झुनझुनवाला

बेहतर होगा कि सरकारें जनता को मुफ्त सेवाएं देने के बजाय उसे उन सुविधाओं को हासिल करने में सक्षम बनाएं

तमाम देशों में इस समय जनता को मुफ्त सुविधाएं बांटकर वोट हासिल करने का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। इंग्लैंड के पिछले चुनाव में मुफ्त ब्राडबैंड, बस यात्रा एवं कार पार्किंग की घोषणा की गई। हम भी पीछे नहीं। कुछ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में मुफ्त लैपटाप, तमिलनाडु के हालिया चुनावों में किचन ग्राइंडर एवं साइकिल, दिल्ली में मुफ्त बिजली एवं पानी और केंद्र सरकार द्वारा गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इनसे जनहित तो होता है, मगर कहावत है कि किसी को 'मछली बांटने के स्थान पर यदि उसे मछली पकड़ना सिखाएं तो वह अधिक लाभप्रद होता है।' विचारणीय है कि ऐसे मुफ्त वितरण से क्या वास्तव में जनहित होता है? चुनाव पूर्व ऐसी घोषणाएं निश्चित रूप से अनैतिक हैं, क्योंकि इनमें सार्वजनिक धन का उपयोग वोट मांगने के लिए किया जाता है। जैसा कि कांग्रेस ने किसानों की ऋण माफी एवं मनरेगा जैसी योजनाओं से जीत हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पूर्व ऐसी बंदरबांट पर रोक लगाने की पहल की थी।

बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव के बाद भी ऐसा वितरण सही है? भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद की प्रोफेसर रितिका खेड़ा के अनुसार सरकारी सेवाएं तीन प्रकार की होती है। पहली श्रेणी में सार्वजनिक सेवाएं होती हैं। जैसे रेल, हाईवे अथवा कोविड के बारे में जानकारी जो कि केवल सरकार ही उपलब्ध करा सकती है। निःसंदेह ये सुविधाएं सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दूसरे प्रकार की सुविधाएं वे होती हैं जो व्यक्ति स्वयं हासिल कर सकता है, परंतु किसी व्यक्ति को ये सुविधाएं मिलने से समाज का भी हित होता है। जैसे यदि किसी को मास्क मुफ्त दे दिया जाए तो कोविड संक्रमण कम होगा। यद्यपि मास्क व्यक्तिगत सुविधा है, परंतु उसे उत्तम अथवा मेरिट वाली सुविधा कहा जाता है। तीसरे प्रकार की सुविधाओं में लाभ व्यक्ति विशेष को ही होता है। जैसे दिल्ली में एक तय सीमा तक मुफ्त बिजली देना। ऐसे वितरण का सामाजिक सुप्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सरकार को इससे बचना चाहिए। उसे सीधे देने के स्थान पर जनता को सक्षम बनाना चाहिए कि वह इस सुविधा को स्वयं बाजार से खरीद सके।

विषय यह रह जाता है कि मेरिट और व्यक्तिगत सुविधा में भेद कैसे किया जाए? इसका स्पष्टीकरण दो योजनाओं की तुलना से ही सकता है। केंद्र सरकार ने किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष नकद देने की योजना लागू की है। वहीं दिल्ली सरकार ने मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा किया है। दोनों मुफ्त सुविधाएं हैं। अंतर है कि किसान को नकद राशि मिलने से उसका खेती के प्रति रुझान बढ़ता है और देश की खाद्य व्यवस्था सुदृढ़ होती है, जबकि बिजली मुफ्त बांटने से ऐसा लाभ नहीं मिलता। इसलिए किसान को दी जाने वाली नकद मदद को मेरिट सुविधा में गिना जाना चाहिए जबकि मुफ्त बिजली को व्यक्तिगत सुविधा में। इसका यह अर्थ नहीं कि किसान को नकद राशि देना ही सर्वोत्तम है। उत्तम यह होता कि किसान को पराली न जलाने, भूजल के पुनर्भरण, रासायनिक उर्वरक का उपयोग घटाने के लिए सब्सिडी दी जाती। इससे किसान की आय भी बढ़ती और समाज का हित भी होता।



अवधेश राजपूत

केंद्र सरकार को तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। वर्तमान में केंद्र द्वारा किसान पेंशन के अतिरिक्त मातृत्व वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं को नकद राशि दी जा रही है। उन्नत जीवन योजना के अंतर्गत एलईडी बल्ब वितरित किए जा रहे हैं। ग्रामीण कौशल योजना एवं दीनदयाल अंत्योदय कौशल योजना के अंतर्गत लोगों को उपयुक्त क्षमताओं में ट्रेनिंग दी जा रही है। इन योजनाओं को बनाए रखना चाहिए, लेकिन केंद्र द्वारा तमाम मुफ्त सुविधाएं भी दी जा रही हैं। जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत बीमा पर सब्सिडी दी जा रही है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जा रही है। जन-धन योजना में बैंक में खाते खुलवाए जा रहे हैं। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को लगभग मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इन तमाम योजनाओं का विशेष सामाजिक सुप्रभाव नहीं दिखता। उलटे प्रशासनिक भ्रष्टाचार से रिसाव का जोखिम और पैदा होता है। इन योजनाओं की रकम को लोगों के खाते में सीधे वितरित कर दिया जाए तो बेहतर। इससे न केवल इन योजनाओं में प्रशासनिक व्यय और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, अपितु लाभार्थी तक वास्तविक लाभ भी पहुंचेगा। दूसरा लाभ यह होगा कि जनता अपने विवेक एवं आवश्यकता के अनुसार उस रकम का उपयोग कर सकेगी।

आज हमारे देश के नागरिक जागरूक हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जाता है कि वे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में शिक्षा दिलाने के लिए खर्च करने से गुरेज नहीं करते। अब उस धारणा को तिलांजलि दे देनी चाहिए कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति केवल सरकारी तंत्र ही कर सकता है। हमें जनता पर भरोसा कर उसे इन तमाम योजनाओं में उलझाने के बजाय सीधे रकम देनी चाहिए। ऐसे वितरण के विरोध में कहा जाता है कि यदि देश के सभी नागरिकों को यह रकम दी जाएगी तो यह अमीरों को भी मिलेगी, जिसका कोई तुक नहीं। मान लीजिए किसी अमीर को किसान की भांति 6,000 रुपये सालाना नकद दिए गए तो वे उससे अतिरिक्त कर के रूप में वसूल भी किए जा सकते हैं। इससे लाभ यह होगा कि गरीब पर 'गरीब' का ठप्पा नहीं लगेगा और नौकरशाही के खेल से देश मुक्त हो जाएगा।

कल्याणकारी खर्चों का दूसरा पक्ष सरकार की वित्तीय क्षमता का है। सरकार को निर्णय करना होता है कि वह सड़क बनाएगी अथवा गरीब को पेंशन देगी। सरकार जब जनता को मुफ्त सुविधाएं देती है तो उसकी हाईवे इत्यादि बनाने की क्षमता कम हो जाती है। वह नई तकनीक में निवेश नहीं कर पाती। इसका आखिरकार देश के आर्थिक विकास पर ही कुप्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरूप गरीब का ही जीवन दुष्कर हो जाता है। वेनेजुएला इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तमाम सुविधाएं मुफ्त प्रदान करने से आज उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। समय आ गया है कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने के लिए मुफ्तखोरी पर विराम लगाना चाहिए। इसके बजाय नई तकनीकों में निवेश किया जाए और नागरिकों को सीधे रकम दी जाए।

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

संसाधनों पर बोझ बनती बढ़ती आबादी



स्वामी चिदानंद सरस्वती

जब तक बढ़ती आबादी नहीं रुकेगी, तब तक प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी भी नहीं थमेगी



तमाम समस्याओं की जननी है अधिक आबादी। फाइल

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। यह स्वतंत्रता हमें अपने संविधान से मिली हुई है, परंतु बात जब हमारे देश या धरती की, प्राकृतिक संसाधनों या सतत विकास की हो तब हम सभी का दायित्व बनता है कि उस पर मिलकर चिंतन किया जाए। आज सभी को मिलकर सोचना होगा कि बढ़ती जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए? वैश्विक स्तर पर दिन-प्रतिदिन बढ़ती आबादी के कारण प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति करना अब संभव नहीं दिख रहा है। वर्तमान में धरती के पास जो संसाधन हैं हम उनका तेजी से उपभोग कर रहे हैं। जनसंख्या की लगातार वृद्धि के लिए जो विकास किया जा रहा है उससे प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंच रहा है तथा उनकी खपत भी तीव्रता से बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर हमारे विकास के लक्ष्य भी कहीं न कहीं बेअसर हो रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने तथा उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ रूप से बनाए रखने के लिए जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि पर अंकुश लगाना ही होगा।

बढ़ती जनसंख्या प्रकृति के विनाश का कारण बनती जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों की जिस वेग से मांग बढ़ रही है, उसकी आपूर्ति के लिए प्रकृति के नियमों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अतः बढ़ती जनसंख्या के प्रति सभी को जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि यह केवल परिवार का मुद्दा नहीं है, बल्कि प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों में द्रुत गति से हो रही कमी का भी मुद्दा है। जब तक बढ़ती आबादी नहीं रुकेगी, तब तक प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी भी नहीं रुकेगी। भारत में जिस वेग से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वह वास्तव में चिंतन का विषय है। अगर जनसंख्या वृद्धि इसी गति से होती रही तो यह हमारी जीवन प्रणाली और जीवन स्तर के लिए खतरनाक साबित होगी। जल, जलवायु, भोजन और प्राकृतिक संसाधनों पर ग्रहण लग जाएगा। अब हर भारतीय को बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूक होना होगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह धरती का, पर्यावरण का, पानी का और प्राकृतिक संसाधनों की हो रही कमी का मुद्दा है। इसलिए उतने ही बच्चे पैदा करें जितनों का ठीक तरह से पालन-पोषण कर सकें। अन्यथा उन प्यारे बच्चों का बचपन ही नहीं, बल्कि जिंदगी भी नरक बन जाएगी। ज्यादा बच्चे होने पर न उन्हें उचित पोषण मिल पाता है, न शिक्षा और न ही अच्छा जीवन स्तर।

अगर इसी तरह से जनसंख्या वृद्धि होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब धरती पर न स्वच्छ जल होगा, न शुद्ध हवा, न जलवायु स्वच्छ होगी, न खाने को पर्याप्त अन्न होगा और न सुविधापूर्वक रहने को जमीन होगी। साथ ही बीमारी, बेरोजगारी और हिंसा भी बढ़ेगी। वर्तमान को ही देख लीजिए। कोविड-19 के समय हमारे देश और दुनिया का क्या हाल है? जिन्हें अस्पतालों में वेंटिलेटर पर होना चाहिए था, वे सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। हमारे देश में कई परिवार ऐसे भी हैं, जिनके पास बच्चे तो हैं, पर खाने को रोटी नहीं है। इससे देश में कुपोषित बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कुपोषण के कारण बच्चों के सोचने-समझने की शक्ति कमजोर होती है। उनके शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। बेरोजगारी की समस्या के लिए जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण है। बेरोजगारी और गरीबी के कारण परिवार और समाज स्तर पर धीरे-धीरे हिंसा बढ़ती जा रही है। इसके चलते भुखमरी और भिक्षावृत्ति में भी वृद्धि हो रही है। कई शहरों में सड़कों पर भीख मांगते बच्चे, फटेहाल नौनिहाल देखे जा सकते हैं। बच्चों को भिक्षा नहीं, शिक्षा चाहिए और शिक्षा भी संस्कार युक्त। वर्तमान में कई बच्चों के पास न तो उचित शिक्षा है और न चिकित्सा।

पर्यावरणविद् बार-बार कह रहे हैं कि हमें जल एवं भूमि के प्रभावी प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भारत सहित विश्व के लगभग सभी देश अपने-अपने स्तर पर योजनाएं बना रहे हैं और धरती को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भू-विज्ञानियों का दावा है कि पृथ्वी पर संसाधन सीमित हैं इसलिए उनका उपयोग सोच-समझकर करना होगा। इस समय जल, जंगल और जमीन घटते जा रहे हैं। हम जल की ही बात करें तो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल की लगभग 2.5 प्रतिशत मात्रा ही पीने योग्य है। इसमें से वर्ष 2030 तक पीने का पानी 50 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। सोचो तब कहां से लाएंगे पानी। पानी नहीं तो जीवन कैसा? कहा भी गया है कि 'जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं।' जाहिर है इस अनमोल संपदा का प्रबंधन ठीक से करना होगा। इसके अलावा हमारे जंगल भी तेजी से कट रहे हैं। नदियों का दम घुट रहा है। धरती पर लोगों को रहने के लिए पहले से ही जगह कम है और जनसंख्या का हाल यह है कि भारत में हर साल लगभग दो से ढाई करोड़ बच्चे जन्म ले रहे हैं। ऐसे में कैसा होगा आने वाली पीढ़ियों का भविष्य?

सच तो यह है कि अब समय केवल सोचने का नहीं, बल्कि कुछ करने का है। इसका केवल एक ही उपाय है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। हम दो, हमारे दो और सबके दो। चाहे राशनकार्ड हो या नौकरी हो या कोई भी सरकारी सुविधा, जिनके दो बच्चे हों उन्हीं को ये सुविधाएं दी जाएं। देश में एक परिवार के लिए दो बच्चों के जन्म का प्रविधान किया जाना चाहिए। दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्येक व्यक्ति को देश के हर क्षेत्र में समानता के साथ अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों या राजनीति से जुड़े लोग हों। यह प्रविधान सभी पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसी से भविष्य के लिए सही राह निकलेगी।

(लेखक परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के परमाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

वाणी का संयम

संयम रखना एक अद्भुत कला है। यह मानव जीवन को सुखी बनाने का रहस्य है। यही हमारे जीवन का मूल आधार भी है। जिसने भी अपनी सभी कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया वही मनुष्य बुद्धिमान, विद्वान और महापुरुष बन सकता है। वाणी के संयम का एक उदाहरण यहां देना समीचीन होगा। द्वापर युग समाप्ति की ओर था। महाभारत को बोलकर लिखवाने के लिए महर्षि वेदव्यास जी के मन में किसी योग्य व्यक्ति की कामना जागृत हुई। उनकी इस कामना को पूर्ण करने के लिए गणेश जी ने महाभारत लिखने का संकल्प लिया। महर्षि वेदव्यास जी बोलते गए तथा गणेश जी लिखते गए। बहुत दिनों तक यह कार्य चलता रहा। महाभारत का लेखन कार्य पूर्ण हुआ तो वेदव्यास जी ने गणेश जी से पूछा, 'महाभाग! मैंने चौबीस लाख शब्द बोलकर आपको लिखवाए हैं। आश्चर्य है कि इस बीच आप एक शब्द भी नहीं बोले। सर्वथा मौन ही रहे। बस लिखते गए।' तब गणेश जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, 'बादरायण, बड़े कार्य संपन्न करने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति का आधार संयम है। संयम ही समस्त सिद्धियों का प्रदाता है। यदि मैं वाणी का संयम न रख सका होता तो आपका ग्रंथ कैसे पूरा हो पाता?' इससे स्पष्ट होता है कि संयम से ही सभी कार्य संपन्न होते हैं।

प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, पर जो उन्हें सहज रूप से स्वीकार कर संयम से रहते हुए उनका सामना करते हैं, वे उसे जीतकर आनंद का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य अपनी वाणी पर नियंत्रण कर पाने में सक्षम होते हैं, वे तन-मन से स्वस्थ और प्रसन्न तो रहते ही हैं। साथ ही अपनी मंजिल को भी वे सहज रूप से पा लेते हैं। वाणी पर संयम करने वाले मनुष्य समाज के लिए प्रेरणास्रोत होते हैं। वे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। अनगिनत मानवीय गुणों से संपन्न भी होते हैं। हम भी अपनी जीवन यात्रा में संयम से रहने का संकल्प लें।

डा. राकेश चक्र

हादसों का सबब बनता चाइनीज मांझा

नरपतदान चारण

> चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है, पर चोरी-छिपे इसे खूब बेचा जाता है। सरकारों को हर हाल में इसके इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए

चाइनीज मांझे की चपेट में आकर देश में लोगों के घायल होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसकी वजह से पिछले दिनों दिल्ली में बाइक सवार एक युवक की गर्दन और अंगूठा कट गए। एक और युवक भी घायल हो गया। इसी तरह उदयपुर में भी बीते दिनों ऐसी ही दिल दहला देने वाली एक घटना में पिता के साथ बाइक पर जा रही पांच साल की मासूम बच्ची की गर्दन हवा में लहराते चायनीज मांझे से कट गई। मासूम को बचाने के लिए उसकी गर्दन पर 36 टांके लगाने पड़े। देश में बारिश के मौसम के साथ ही पतंग उड़ाने का चलन शुरू हो जाता है, जो मकर संक्रांति के दिन तक लगातार चलता रहता है। चिंता की बात यह है कि पतंग उड़ाने में प्रयोग किए जाने वाला चायनीज मांझा मौत बनकर सामने आ रहा है। हर साल देश के कई शहरों में इस मांझे के भंवरजाल में फंसकर लोग घायल हो रहे हैं और मौत का शिकार हो रहे हैं।

बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट चाइनीज मांझे की बिक्री पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है, फिर बाजार में इसकी धड़ल्ले से बिक्री कैसे हो रही है। दरअसल पतंग उड़ाने में प्रयोग होने वाले इस चाइनीज मांझे को बनाने में कई घातक रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जो इंसानी जिंदगी के साथ ही पक्षियों के लिए बड़ा खतरा साबित होते हैं। चायनीज मांझे को बनाने में डेगचून के बुरादे की परत चढ़ाई जाती है, जो शरीर पर तुरंत घाव कर घायल कर देती है। विशेषकर इससे बाइक सवारों की गर्दन कटने का खतरा अधिक रहता है। मांझे को बनाने में शीशे का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे यह कई बार मौत का सबब बन जाता है। पतंग कटने के बाद कई बार मांझा पेड़ों और बिजली के तारों आदि पर लटके रहते हैं। इसकी वजह से भी हादसे होते हैं। अगर मांझा बिजली की लाइन में छूट जाए तो पतंग उड़ा रहे बच्चे को करंट भी लग सकती है। चाइनीज मांझे को बनाने में प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है। इस कारण यह आसानी से टूटता नहीं। शीशे का इस्तेमाल होने के कारण इसमें धार भी होती है। इसके कारण पतंग उड़ाते समय यह कई बार लोगों की हथेली को काट भी देता है। सवाल है जिस चाइनीज मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध है, वह लोगों के हाथों में आखिर कैसे पहुंच रहा है?

दरअसल पतंग उड़ाने के लिए जो मांझे बाजार में मौजूद हैं, वे सभी घातक हैं, लेकिन चाइनीज इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है। पतंग कारोबारी बताते हैं कि देसी मांझे के मुकाबले चाइनीज मांझा बेहद सस्ता और मजबूत होता है। करीब आठ-नौ साल पहले भारत में यह मांझा आया था। इसके बाद लोग बेहद कम समय में इसे पसंद करने लगे। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ लोग चोरी-छिपे इसे बेचते हैं। अब सरकारों को हर हाल में इसके इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

प्राचीन शिक्षा पद्धति का स्याह पक्ष

प्रोफेसर शंकर शरण ने अपने लेख 'गुरु-शिष्य परंपरा की महत्ता' में शिक्षा की सनातनी पद्धति पर प्रकाश डाला है, परंतु यह प्रकाश सिर्फ एक ही पक्ष पर जान पड़ता है, जो हमारी शिक्षा पद्धति की महत्ता को दिखाता है। इससे इतर इस शिक्षा परंपरा का जो दूसरा पक्ष है वह आज के समय में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। यह पक्ष है उन शूद्र, जनजातीय और महिला समाज का पक्ष जिन्हें इस महान शिक्षा पद्धति में शिक्षा का अधिकार नहीं था। लेखक महोदय ने अपने लेख में एकलव्य का नाम भी लिया है और इस नाम को गुरु-शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु की अनुपस्थिति में भी उनके द्वारा शिष्य को दिए गए मार्गदर्शन से जोड़ दिया है, परंतु क्या यह उचित है कि एकलव्य को शिक्षा के अधिकार से सिर्फ इसलिए वंचित रखने का प्रयास किया गया, क्योंकि वह क्षत्रिय अथवा राजकुल से नहीं था? इस तिरस्कार के बाद भी यदि विद्यार्थी निज अभ्यास से शिक्षित हुआ तो उसे ईर्ष्यावश दंड देकर उसे गुरु दक्षिणा का नाम देना कहां की महानता थी। ऐसा ही प्रश्न आप कर्ण के विषय में द्रोण और परशुराम जैसे गुरुजनों से कर सकते हैं। क्या शिक्षा जाति और लिंग के आधार पर बंटनी चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। और यदि अगर ऐसा है तो उस शिक्षापद्धति को महान नहीं कहा जा सकता। उस शिक्षा पद्धति से आज की शिक्षा पद्धति कई मायनों में बेहतर है। बस कमी है तो उस गुरु-शिष्य के संबंधों और आचरणों की, जिसको पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा पद्धति ने धीरे-धीरे करके हमसे छीन लिया। यदि प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का इस प्रकार उपयोग किया जाए कि सभी को समतामूलक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित हो और भारत का वह बड़ा वर्ग जो प्राचीन काल में इस शिक्षा पद्धति से वंचित रहा वह भी अन्य वर्गों की भांति ही समान शिक्षा प्राप्त कर सके तो निश्चित रूप से हम और हमारा देश एक ऐसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे, जहां आचरण की सभ्यता विकसित होगी। इसके साथ-साथ एक महान शिक्षा पद्धति का भी विकास होगा, जिसमें आज के सारे विषयों के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है, उसका भी विकास होगा। तब सही मायने में हमारा राष्ट्र विश्वगुरु के सपने को सच कर दिखाने के समीप होगा।

अनुभव सिंह, प्रयागराज

खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की आस

टोक्यो पहुंचे भारतीय दल से देशवासियों को बहुत आशाएं हैं। पिछले कई वर्षों से भारत सरकार का खेल और खिलाड़ियों के प्रति सकारात्मक रुझान रहा है। खेल प्रशासन यह समझ चुका है कि मात्र इच्छाशक्ति के बल पर ही बेहतरीन परिणाम की आशा नहीं की जा सकती, इसके लिए खिलाड़ियों की क्षमताओं का विकास उचित स्तर का होना भी जरूरी है। आने वाले दिनों में भी खेल परिणाम हमारे पक्ष में ही रहें इसके लिए भारतीय खिलाड़ियों को संयम, आपसी तालमेल और जीत की उचित रणनीति बनाकर खेलना होगा। हार-जीत खेल का अभिन्न अंग है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी को हल्का समझना घातक है। आगे बचे दो हफ्तों में भारतीय खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें बंधी हुई हैं। विश्वास मानिए समग्र देशवासी उनके उत्साह को हमेशा बनाए रखेंगे।

मृदुल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

अन्न को बचाना जरूरी

भारतीय संस्कृति में सदियों से अन्न को न सिर्फ खाने की वस्तु समझा जाता है, बल्कि इसको भगवान की तरह पूजा जाता रहा है। वहीं आधुनिकता के दौर में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि थाली में भोजन को छोड़ना एक फैशन मानने लगे हैं। शायद इन लोगों को भोजन के अभाव में सोने वालों और भूखे मरने वालों की जानकारी नहीं है। विश्व खाद्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का हर सातवां व्यक्ति हर दिन भूखा सोता है। वही भारत में यह आंकड़ा हर पांचवें व्यक्ति पर स्थिर है। अगर इस अन्न की बर्बादी को रोका जा सके तो कई लोगों का पेट भरा जा सकता है। कई लोगों को हम भूखे मरने से बचा सकते हैं। अन्न बर्बादी एक बड़ी समस्या है। इस पर समाज के हर एक व्यक्ति को खासा ध्यान देने की जरूरत है।

श्याम मिश्रा, छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

आजकल



लालजी जायसवाल
अध्येता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

कार्यपालिका के काम करती न्यायपालिका

पिछले दिनों ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जिनमें यह देखा गया है कि कार्यपालिका ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसमें बदलाव के लिए न्यायपालिका यानी अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया कांवड़ यात्रा से जुड़े फैसले का मामला हो या फिर केरल में बकरीद के मौके पर कोविड प्रोटोकाल के तहत लागू प्रतिबंधों में ढील देने का मामला हो, इन सभी में जनहित को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर राज्य सरकारें ऐसे फैसले लेती ही क्यों हैं, जिससे अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ता है


कुछ राज्य सरकारों द्वारा जनहित में लिए गए कई फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रवैया। फाइल

पिछले दिनों एक मामले पर टिप्पणी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वह इस तथ्य की समीक्षा करेगा कि कार्यपालिका के दायरे में आने वाले कोविड प्रबंधन से जुड़े मामलों में अदालतें किस सीमा तक हस्तक्षेप कर सकती हैं। बहरहाल, संविधान में भाग चार के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करते हुए दोनों के बीच के फर्क को विश्लेषित किया गया है। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका, दोनों ही एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे और उसमें हस्तक्षेप से बचेंगे। लेकिन यह मामला नीति निदेशक तत्व में आता है, इसलिए इसका पालन करना कर्तव्य तो है, परंतु बाध्यकारी नहीं है।

दरअसल पिछले दिनों कोविड प्रबंधन से संबंधित मामलों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी थी कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक नहीं रहेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को उसके इस फैसले पर फिर से विचार करने की बात कही थी। खैर, कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें कांवड़ संघों की तरफ से यात्रा स्थगित करने की आधिकारिक जानकारी दी गई।

इसी तरह पिछले ही दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के मौके पर कोविड प्रोटोकाल के तहत लागू प्रतिबंधों में ढील देने के लिए केरल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि यह चौंकाने वाली स्थिति है कि केरल सरकार ने लाकडाउन के मानदंडों में ढील देने की व्यापारियों की मांग को मान लिया। राज्य को ध्यान देना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 21 में लोगों को जीवन का अधिकार प्राप्त है और लाकडाउन में ढील देने से जीवन का संकट उत्पन्न हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार की ओर से दी गई ढील के चलते कोरोना का संक्रमण फैलता है, तो कोर्ट उचित कार्रवाई करेगी।

खैर, इसे न्यायिक सक्रियता के तौर पर नहीं देखा जा सकता। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अतिवाद और न्यायपालिका का कार्यपालिकीय उपयोग, ये तीनों बातें अलग-अलग हैं। न्यायिक सक्रियता का मतलब न्यायालय द्वारा कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप है। न्यायिक सक्रियता सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देती है। कभी न्यायालयों की सक्रियता लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो कभी यह किसी दूसरे अंग में हस्तक्षेप प्रतीत होते हुए संवैधानिक संकट की स्थिति भी पैदा करती है। लेकिन न्यायिक अतिवाद को हम एक उदाहरण से बेहतर रूप से समझ सकते हैं।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे एसएन श्रीवास्तव ने कुछ वर्षों पूर्व यह कहा था कि श्रीमद्भगवद्गीता को भारत का धर्मग्रंथ माना जाए। यह निर्णय संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है, क्योंकि भारत में अनेक जाति व मत के लोग रहते हैं। सबको अपने-अपने मत को मानने की आजादी प्राप्त है। इसलिए ऐसे निर्णय न्यायिक अतिवाद की श्रेणी में आते हैं। लेकिन न्यायपालिका का कार्यपालिकीय उपयोग का मतलब ऐसा लगता है कि कार्यपालिका स्वयं ऐसा आमंत्रित करती है कि न्यायपालिका उसके कार्यों में हस्तक्षेप करे।

लोकतंत्र में सरकारें अपने वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती हैं। केरल और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैसे हालिया निर्णय देखने को मिले हैं, उनमें सरकारें अक्सर ऐसा चाहती हैं कि न्यायालय हस्तक्षेप करे, ताकि यह साबित हो सके कि अमुक प्रतिबंध सरकार ने नहीं, बल्कि न्यायालय ने लगाएं हैं। पिछले दशकों के दौरान यह देखा गया है कि आरक्षण जैसे व्यापक परिदृश्य और परिप्रेक्ष्य वाले मुद्दे न्यायालय में जाते रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि सरकारें अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए आरक्षण की सीमा इस प्रकार तय करती हैं, जो 50 प्रतिशत को पार कर जाता है और ऐसे मामले न्यायालय पहुंच ही जाते हैं, फिर उसे निरस्त किया जाता है। इन सभी बातों के माध्यम से जनता को यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि सरकार तो जनहित में ही निर्णय लेती है, लेकिन न्यायालय ने उसे असंवैधानिक करार दिया।

ध्यातव्य है कि तीन नए कृषि कानूनों के विरोध स्वरूप किए जा रहे आंदोलन के समय जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का आंदोलनकारियों ने निर्णय लिया था तो सरकार ने स्वयं न्यायालय में जाकर उससे ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने के बाबत आदेश जारी करने की बात कही थी, जो कार्य सरकार का अपना था। न्यायालय ने उस समय यह कहा था कि कार्यपालिका को देखना है कि विधि और व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि यह कार्य न्यायपालिका का नहीं है। लिहाजा, न्यायालय ने इस संबंध में कोई आदेश देने से इन्कार कर दिया और कहा कि अगर ऐसे मामलों पर आदेश जारी किया गया तो यह कार्यपालिका के कार्यों में दखल के समान होगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कैसे न्यायापालिका का कार्यपालिकीय उपयोग किया जाता है, जिसे लोकतंत्र में किसी भी लिहाज से उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसे में न्यायपालिका का समय बरबाद होता है और भविष्य में न्यायिक अतिवाद की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिनों का एक वक्तव्य सटीक बैठता है कि 'हमें समीक्षा करनी होगी कि कार्यपालिका के मामलों में संवैधानिक अदालतें किस सीमा तक हस्तक्षेप कर सकती हैं।'

उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र शक्ति के संतुलन पर चलता है और वह तीन स्तंभों पर आधारित है। हर स्तंभ की भूमिका परिभाषित है। यदि तीनों स्तंभ- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने दायरे में काम करें तो एक स्वस्थ लोकतंत्र दिखता है। यदि कोई भी एक क्षेत्र दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करने की कोशिश करे, तो उससे असंतुलन पैदा होता है। न्यायालयों की कुछ टिप्पणियों में उत्तेजना दिख सकती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह बताया था कि न्यायालयों में सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियां न्याय का भाग नहीं, बल्कि त्वरित प्रतिक्रिया मानी जाती है, जिसका रिकार्ड नहीं रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायालयों को संयमित रूप से वक्तव्य देना चाहिए, जिसमें अतिवाद की झलक न दिखे। पिछले ही माह मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है और उसके अधिकारियों पर कोविड मानकों का पालन किए बिना रैलियों की अनुमति देने के लिए संभवतः हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बाद में, आयोग ने कहा कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, यह कार्य प्रशासन का है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने मेडिकल आक्सीजन की कमी के मामले पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर डाल सकते हैं, हम नहीं। इन बातों से यह जाहिर होता है कि इसे हम सीधे तौर पर न्यायिक सक्रियता नहीं कह सकते भले न्यायालय की बातों में कठोरता दिखती है।

मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व

जीवन का अधिकार मूल अधिकार है। कोई भी व्यक्ति इस मसले पर न्यायालय जा सकता है, क्योंकि मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व न्यायालय का है। अतः न्यायालय को हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है। सवाल उठता है कि कार्यपालिका का क्या दायित्व बनता है? हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना संक्रमण की वजह से न्यायालय भी प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में देश की अदालतों में करीब 3.84 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। ऐसे में अगर न्यायपालिका का कार्यपालिकीय इस्तेमाल बढ़ता रहा तो न्याय मिलना आम लोगों को कठिन हो जाएगा। ध्यान रखना चाहिए कि न्यायालय के समय का स्वहित में बर्बाद करना उचित नहीं है, यह एक प्रकार से अपराध है। इस पर न्यायालय कठोर कार्रवाई भी कर चुकी है। पिछले महीने दो ऐसी ही घटनाएं सामने आई थीं जिनमें जनहित के बजाय स्वहित के तहत न्यायालय का समय बर्बाद किया गया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री जूही चावला और दो अन्य को 5जी नेटवर्क प्रौद्योगिकी को चुनौती देने के मामले में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसी प्रकार दिल्ली हाई कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था, क्योंकि यह राजनीति प्रेरित याचिका थी।

विधायिका और कार्यपालिका को अब गहन मंथन की आवश्यकता है कि आखिर चूक कहां हो रही है कि न्यायालय को सक्रिय होना पड़ रहा है। खासकर कोरोना काल में ऐसे अति सक्रियता के मामले तेजी से बढ़े हैं। यह भी देखा गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिकीय उपयोग भी बढ़ रहा है। ध्यान देना होगा कि जब राज्य के सभी अंग अपना-अपना कार्य संविधान के अनुरूप करें तो कोई विपरीत हालात उत्पन्न ही न हो। कानून बनाना और कानूनों के बीच अंतर को भरना विधायिका का कर्तव्य है और इसे उचित तरीके से लागू करना कार्यपालिका का कार्य है।

बहरहाल, यह देखने में आ रहा है कि अदालतें सरकार को नीति बनाने के लिए कह रही हैं, जबकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। यह विधायिका का काम है, उसे ही करने दिया जाना चाहिए।

संविधान में न्यायपालिका के दो काम बताए गए हैं, एक यह कि वह देखे कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है और दूसरा दो पक्षों के बीच विवाद सुलझाना और देखना कि दोषी कौन है? न्यायिक सक्रियता संविधान द्वारा समर्थित नहीं है, यह न्यायिक अधिकारियों द्वारा पूरी तरह तैयार एक उत्पाद है। जब न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के नाम पर दी गई शक्तियों की सीमा रेखा पर कदम उठाती है, तो न्यायपालिका तब संविधान में निर्दिष्ट शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को समाप्त करने लगती है। रोजमर्रा के और छोटे-छोटे कार्यों के लिए न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना अथवा कार्यपालिका के द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करना लोकतंत्र में जनहित के विरुद्ध होगा। इसलिए, न्यायपालिका का कार्यपालिकीय उपयोग से बचना ही स्वस्थ लोकतंत्र की जरूरत है।

खरी-खरी

आसमान से आफत की बारिश

डा. तीरथ सिंह खरबंदा

यह खबर सुनकर कि आसमान से आफत की बारिश हुई, मैं विस्मित हूं! क्या सचमुच आफत की बारिश आसमान से ही होती है? सच कहें तो चांद और तारों से सजे आसमान से बारिश के मौसम में तो रहमत बरसती है।

आफत की बारिश का भी भला कोई खास मौसम होता है! हर मौसम में आफत की बारिश गरीब पर गिरती है, जो जाड़े के दिनों में शीत लहर बनकर और तपती गर्मी में लू बनकर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है।

आसमान से बिजली सी महंगाई तो सुबह उठते ही हर दिन गरीब पर गिरती है, कभी महंगाई के बादल फटते हैं तो कभी टैक्स के बादल। छोटी मोटी आफत तो अब हमें सावन की फुहारों सी लगने लगी है। कहते हैं कि जब आफत आती है तो वह अकेली नहीं आती, अपनी सखी सहेलियों को भी साथ लिए चली आती है।

शहरों, गांवों में कभी कहीं जल भराव, तो कहीं गंदगी कीचड़ की आफत है तो कहीं सूखे की आफत, कभी चुनाव की आफत, कभी दंगों की आफत, तो कभी बढ़ते अपराधों की आफत। कभी भूख की आफत तो कभी प्यास की आफत। कई आफतों की आफत महंगाई की आफत है। सबसे सस्ती आफत जहरीली शराब की आफत।

कहते हैं जिस पर रहमत हो उस पर आई आफत दबे कदमों से कहीं छूमंतर हो जाती है। लोग कई बार आफत का उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले लेते हैं यानी खुद ही आफत को दावत दे बैठते हैं गोया वे अपनी ही शादी में अपनी प्रेमिका को भी न्यौता दे बैठे हों।

कुछ लोग आफत की पुड़िया को नमकीन की पुड़िया समझ आफत को खुद ही मुंह लगा लेते बैठते हैं। कई लोग बैठे बिठाए आफत बुला लेते हैं। वैसे तो आफत बिना मोल के मिलती है, किंतु आफत के शौकीन कुछ लोग झूठे वादे करके बदले में आफत मोल भी ले लेते हैं।

वैसे देखा जाए तो जंगल काट-काट कर भी तो हमने ही आफत मोल ली है और अब ये आफत है कि हमारा पीछा छोड़ती नहीं। इसलिए हमें इस आसमानी आफत की वास्तविकता को भी समझना चाहिए।

ट्वीट-ट्वीट

राहुल गांधी का यह दावा है कि आइबी वाले उन्हें बता रहे हैं कि सरकार उनका फोन टैप करा रही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि फिर पेगासस दो कौड़ी का काम करता है, क्योंकि जासूसी वाले हालिया आरोपों के मुताबिक तो पेगासस का इस्तेमाल करने वाले को तो फोन का सारा डाटा मिल ही जाता है।
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

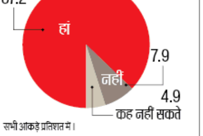
मुख्यमंत्री पद से बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के साथ ही कर्नाटक में एक युग का समापन हो गया। उनका परिवार बहुत गरीब था। कम उम्र में ही उनकी मां का देहांत हो गया। अपने परिवार की मदद के लिए उन्होंने नींबू बेचने से लेकर चावल मिल में क्लर्क तक का काम किया। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित कर उसे सत्ता तक लाए। वह आठ बार विधायक, एक बार सांसद, तीन बार नेता-प्रतिपक्ष और चार बार मुख्यमंत्री बने।
डीपी सतीश@dp_satish


कारगिल विजय दिवस पर हमने उन 527 शहीदों को याद किया तो एक खास मित्र का स्मरण भी बनता है। तब हम पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए थे। फिर भी अमेरिकी आपत्तियों को दरकिनार कर इजरायल ने हमें उस वक्त जरूरी रक्षा साजोसामान और लेजर गाइडेड मिसाइल की आपूर्ति की थी। शुक्रिया मित्र।
आनंद रंगनाथन@ARanganathan72

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या उदारीकरण के तीस वर्षों बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को नए सिरे से गति देने की जरूरत है?



सभी आकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या बीएस येदियुरप्पा के लिए इस्तीफा देना जरूरी हो गया था?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

गेहूं देखा तक नहीं ना पहचानें धान,
चढ़े चने के पेड़ पर भैया बने किसान।
भैया बने किसान लगे ट्रैक्टर दौड़ाने,
भ्रम की खेती बोय सियासत को चमकाने।
राजनीति का खेल पीढ़ियों से है सीखा,
क्या पड़ता है फर्क जो ना है गेहूं देखा!
- ओमप्रकाश तिवारी



जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

दिल्ली पहुंची राज्य की सियासी जंग

करीब एक साल से बंगाल में लड़ी जा रही सियासी जंग अब दिल्ली पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री व तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी खास रणनीति के तहत इस जंग को दिल्ली ले जाकर अब वहीं से इसे लड़ना चाहती हैं, ताकि बंगाल की ओर से नजर हटाई जा सके। इसकी वजह भी है। जिस तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की वृहत्तर पीठ के निर्देश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा गठित विशेष समिति की बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा पर रिपोर्ट सामने आई है, उससे ममता सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है।

एनएचआरसी ने कानून-व्यवस्था को लेकर जो टिप्पणी अपनी रिपोर्ट में की है वह काफी चिंताजनक है। सीबीआइ से लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआइटी) गठित कर हिंसा की पड़ताल कराने की भी सिफारिश की गई है। लिहाजा ममता के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी।

ममता भले एनएचआरसी की रिपोर्ट को गलत और राजनीति से प्रेरित कहें, लेकिन हाई कोर्ट यदि समिति की सिफारिश को मान लेता है तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा विरोधी मोर्चे का चेहरा बनने का जो सपना तृणमूल प्रमुख देख रही हैं, उस पर ग्रहण लग सकता है। यही वजह है कि पेगासस जासूसी फोन टैपिंग मामले को लेकर संसद के अंदर और बाहर, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक तृणमूल अन्य विपक्षी दलों की तुलना में अधिक आक्रामक है। इसी को लेकर तृणमूल के राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन अति उत्साह में सदन में ऐसा अशोभनीय आचरण कर बैठे कि उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित होना पड़ा है। यही नहीं,


चुनाव बाद हुई हिंसा के खिलाफ दिल्ली में राजघाट पर धरना देते बंगाल के भाजपा नेता व सांसद। फाइल

अपने वार्षिक आयोजन 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली के अवसर पर विपक्षी नेताओं को आमंत्रित कर ममता ने अपनी रणनीति को और धार देने की कोशिश की है। इन गतिविधियों के बीच भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी मुहिम को तेज करने के लिए ममता बनर्जी स्वयं भी पांच दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वह राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगी। सोनिया गांधी व अन्य विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं से भी वह मुलाकात करेंगी। वह कृषि कानून विरोधियों को भी अपना समर्थन देने जाएंगी।

तृणमूल की रणनीति का मुंहतोड़ जवाब देने में भाजपा भी पीछे नहीं है। ममता के दिल्ली दौरे से पहले ही बीते शुक्रवार को भाजपा विधायकों को साथ लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंच गए। वहां पहुंचने के साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और चुनाव बाद हिंसा को लेकर पूरी जानकारी दी। संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए बंगाल के सभी भाजपा सांसद दिल्ली में हैं और उसी क्रम में सुवेंदु भी विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। ममता की यात्रा से पहले राजधानी में बंगाल के भाजपा नेताओं का जमावड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां ममता बंगाल की जंग को दिल्ली से लड़ने की कोशिश कर रही हैं तो दूसरी ओर भाजपा ने भी दिल्ली से ही उन्हें जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। इसकी बानगी 21 जुलाई को ही देखने को मिली।

ममता जब पिछले बुधवार को 1993 में वामपंथी सरकार के कार्यकाल में 'राइटर्स अभियान' के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए 13 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की याद में वर्चुअल शहीद रैली कर रही थीं, तो भाजपा के नेता-कार्यकर्ता कोलकाता से लेकर दिल्ली के राजघाट पर चुनाव बाद हिंसा में कथित रूप से तृणमूल के हमले में मारे गए 38 कार्यकर्ताओं की याद में 'शहीद श्रद्धांजलि दिवस' मनाते हुए धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। राजघाट पर भाजपा के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में भाजपा सांसदों ने भी धरना दिया। ममता बनर्जी और बंगाल के भाजपा नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा यह बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा और अन्य मसलों से ध्यान दिल्ली यानी केंद्र सरकार की ओर ले जाने की तृणमूल प्रमुख ने जो कोशिश की है, उसमें वह कितना सफल होती हैं, यह तो वक्त ही बताएगा।

मंथन



रिजवान अंसारी
सामाजिक मामलों के जानकार

बहुविवाह पर लगे पूर्ण प्रतिबंध

जब दुनिया के बड़े-बड़े मुस्लिम देश बहुविवाह पर पाबंदी लगा चुके हैं तो इसके सभी पहलुओं को समझते हुए भारत में भी इसे प्रतिबंधित किए जाने में कोई हर्ज नहीं है


भारतीय मुस्लिमों में बहुविवाह पर पूर्ण पाबंदी लगाने पर गंभीरता से हो विचार। फाइल

पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने 'समान नागरिक संहिता' लागू करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही। कोर्ट ने इसे वक्त की मांग बताया। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद इस मुद्दे का चर्चा में आना तय था। दरअसल, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की पीठ राजस्थान की मीणा जनजाति की महिला और उसके हिंदू पति की तलाक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

मामला था कि 2012 में इस जोड़े की शादी हुई और 2015 में पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की। महिला का पति हिंदू विवाह कानून-1955 के मुताबिक तलाक चाहता था। लेकिन महिला का कहना था कि वह मीणा समुदाय से ताल्लुक रखती है, इसलिए उस पर हिंदू विवाह कानून लागू नहीं होता। महिला की इस दलील को मानते हुए फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। लिहाजा, महिला के पति ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आधुनिक भारतीय समाज में धीरे-धीरे जाति, मत और समुदाय का भेद मिट रहा है। इस बदलाव के कारण देश के युवाओं को शादी, तलाक और उत्तराधिकार आदि के मामलों में परेशानियों से बचाने के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है।

वैसे, यह पहली बार नहीं है जब देश में समान नागरिक संहिता की वकालत कोर्ट द्वारा की गई है। वर्ष 1985 में शाह बानो मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संहिता की जरूरत बताने के बाद देश कई बार इस चर्चा का गवाह बन चुका है। लेकिन यह शायद पहला मौका है जब इस चर्चा की वजह मुस्लिम समुदाय का कोई मामला नहीं है, अन्यथा मुस्लिमों में तीन तलाक और बहुविवाह पर हिंदुओं से अलग नियम के चलते बार-बार इस मुद्दे पर बहस हो चुकी है। हालांकि मुस्लिमों में तीन तलाक की प्रथा को 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है और अब इस पर कानून भी बन चुका है। लिहाजा तीन तलाक अब कोई मुद्दा नहीं रहा। लेकिन मुस्लिमों में बहुविवाह अब भी एक मुद्दा बना हुआ है।

वैसे देश में करीब सभी समुदायों में बहुविवाह का प्रचलन रहा है। आंकड़े बताते हैं कि आजाद भारत में भी यह प्रथा विभिन्न समुदायों में रही है। वर्ष 1974 में भारत सरकार के एक सर्वे के मुताबिक तब मुस्लिमों में बहुविवाह का प्रतिशत 5.6 था और हिंदुओं में 5.8 था। लेकिन 2006 आते-आते इसमें बड़ी गिरावट देखी गई। तब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने बताया कि हिंदुओं में यह घटकर यह 1.7 फीसद रह गई। लेकिन मुस्लिमों में यह 2.5 फीसद थी।

जहां तक मुस्लिमों में बहुविवाह का सवाल है, तो इसे अक्सर धर्म से जोड़ कर देखा जाता रहा है और इस पर काफी विवाद भी हो चुका है। मुस्लिम समुदाय इस प्रथा का बचाव यह कह कर करते हैं कि मजहब ने उन्हें यह हक दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या मजहब ने यह सहुलियत बिना शर्त के दी है? जवाब है नहीं। कुरान की एक आयत में इसका उल्लेख भी किया गया है। उसमें यह जिक्र किया गया है कि यदि कोई पुरुष एक से ज्यादा शादी करता है, तो उसे अपनी सभी पत्नियों के साथ न्याय करना होगा। लेकिन मौजूदा वक्त में देखा जाता है कि लोग धर्म की आड़ में इस सहुलियत का गलत फायदा उठाते हैं। अपनी पहली पत्नी की खुशी का ख्याल किए बिना, लोग इस व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं।

दूसरी ओर हमें यह भी देखना होगा कि कुरान ने ऐसी व्यवस्था क्यों दी और किन परिस्थितियों में दी? दरअसल, कुरान की यह संबंधित आयत तब अवतरित हुई, जब युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष मारे जा रहे थे। इसके चलते बेवा (विधवा) औरतों की तादाद तेजी से बढ़ रही थी। ऐसे में देखा गया कि विधवा औरतों के सामने अपनी बाकी जिंदगी बिताने और बच्चों के पालन-पोषण का बड़ा संकट खड़ा हो रहा था। ऐसे में अंदेशा इस बात का था कि मजबूरी में कुछ औरतें गलत कार्यों की ओर कदम बढ़ा सकती हैं। इसलिए मर्दों को एक से ज्यादा शादी की अनुमति दी गई, ताकि विधवा विवाह का रास्ता खुला रहे और विधवा औरतें नई जिंदगी शुरू कर सकें। लेकिन मौजूदा वक्त में वैसी कोई स्थिति नहीं है।

कुरान की संबंधित आयत से यह भी पता चलता है कि किसी गरीब और बेबस लड़की को सहारा देने के लिए उससे शादी कर लेनी चाहिए ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन आज ऐसे कितने लोग हैं जो इस नेक काम को करने की कोशिश करते हैं? किसी का सहारा बनने की नीयत से शादी करते हैं? यानी बहुविवाह उस दौर में ही प्रासंगिक था और अब इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि दुनियाभर में मुस्लिम आबादी निवास करती है। मुस्लिम देशों की संख्या 50 से भी अधिक है, लेकिन कई देशों में इस पर पाबंदी है। तुर्की और ट्यूनीशिया जैसे कई इस्लामिक देशों में बहुविवाह प्रतिबंधित है और दर्जनभर देशों में यह मुद्दा वहां की अदालतों में विचाराधीन है। कुछ देशों में इसकी इजाजत अगर है भी, तो इसके लिए पति को पत्नी से इजाजत लेना अनिवार्य किया गया है। यानी हर हालत में महिला के जीवन की सुरक्षा और उन्हें समानता का अधिकार मिलना जरूरी है। ऐसे में भारतीय मुस्लिमों में भी बहुविवाह पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए।

58,189 ग्राम पंचायतों में भर्ती होंगे पंचायत सहायक उत्तर प्रदेश में। दो अगस्त से लिए जाएंगे आवेदन, 10 सितंबर तक पूरी होगी नियुक्ति। 10वीं व 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट के जरिये यह भर्ती होगी।

उत्तराखंड

विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है। विशेषज्ञ चिकित्सक कितनी कम संख्या में हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में स्वीकृत विशेषज्ञों के 1147 पदों के सापेक्ष केवल 493 विशेषज्ञ चिकित्सक ही तैनात हैं। यानी विशेषज्ञ चिकित्सकों के 654 पद खाली हैं। उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों में से भी अधिकांश चिकित्सक मैदानी जिलों में ही नियुक्त हैं। देहरादून जिले में 92 फीसद विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, तो टिहरी में यह आंकड़ा महज 13 फीसद है। यह स्थिति चिंता पैदा कर रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर पर्वतीय क्षेत्रों में काफी अधिक देखने को मिला था। स्वास्थ्य व्यवस्था और चिकित्सकों की कमी के कारण स्वजन मरीजों को लेकर मैदानी जिलों के अस्पतालों में आए। इससे स्वाभाविक रूप से अस्पतालों पर लोड बढ़ गया।

> कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार को विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने होंगे

नतीजतन अस्पतालों में बेड की किल्लत हो गई। अब संक्रमण की संभावित तीसरी लहर का सबसे अधिक असर 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की आबादी पर होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इस आयु वर्ग का टीकाकरण अभी शुरू नहीं हुआ है। इस आयुवर्ग की संख्या प्रदेश में 30 लाख से अधिक है। ऐसे में इस आयुवर्ग के लिए बाल रोग विशेषज्ञों की सबसे अधिक जरूरत महसूस की जा रही है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अभी लगभग 250 बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। यह संख्या कुल स्वीकृत पदों की 41 फीसद है। ऐसे में सरकार अब निजी क्षेत्र के बाल रोग विशेषज्ञों की सेवाएं लेने पर विचार कर रही है। कोरोना संक्रमण के बाद मरीज मानसिक अवसाद का भी शिकार हो रहे हैं। इनके इलाज को मानसिक रोग विशेषज्ञों की जरूरत है। इनके प्रदेश में 28 पद स्वीकृत हैं। इसके सापेक्ष मात्र चार मानसिक रोग चिकित्सक ही सरकारी अस्पतालों में तैनात हैं। इसी तरह महिला रोग विशेषज्ञ भी महज 36 फीसद ही हैं।

इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि स्वास्थ्य महकमे में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी वास्तव में चिंताजनक है। सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने और चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए जरूरी कदम जल्द उठाने होंगे। इसके लिए चिकित्सकों, खासकर संविदा पर नियुक्त किए गए चिकित्सकों का वेतन बढ़ाने के साथ ही इन्हें दी जाने वाली सुविधाओं में इजाफा किया जा सकता है। जब प्रदेश में आबादी के अनुपात में पर्याप्त चिकित्सक और विशेषज्ञ होंगे तो निश्चित रूप से कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में आसानी होगी।

बिहार

पूरे देश में चलें ऐसी योजनाएं

पहले साइकिल योजना और अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। बिहार सरकार की अच्छी और प्रभावशाली योजनाओं को अन्य राज्य भी अपनाते रहे हैं। स्कूली छात्राओं को साइकिल और अन्य सुविधाएं देकर बिहार में राज्य सरकार ने साक्षरता दर को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। बीच में स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या तेजी से घटी है और अब वे कालेज तक पढ़ाई कर रहीं। सरकार सुविधाएं दे रही हैं। साइकिल योजना का यही लाभ है। बड़ी कक्षाओं में या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में दाखिला लेने की इच्छा रखने वाले छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलता है। इससे आर्थिक दिक्कत की वजह से आगे की पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की मुश्किल कम हुई है। कम ब्याज पर ऋण की मदद से वे अब पढ़ने लगे हैं।

बिहार में यह योजना दो अक्टूबर 2016 को लागू हुई और अब तक डेढ़ लाख छात्रों को इसका लाभ मिला है। दूसरे राज्य भी इसे अपने यहां लागू कर रहे हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और राजस्थान ने इसकी जानकारी ली है। बंगाल ने तो इसे लागू भी कर दिया है। बिहार में योजना लागू करने में सबसे पहले बैंकों ने बाधा उत्पन्न की थी। उसके बाद राज्य सरकार ने स्वयं फंड की व्यवस्था की। तबसे इसे अबाध ढंग से संचालित किया जा रहा है। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि सर्वाधिक 63 फीसद युवाओं ने तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण लिया है। ऐसी शिक्षा हासिल करने के बाद युवा रोजगार से जरूर जुड़ जाएंगे। यानी एक यह एक ऐसी ऋण योजना है, जो मेधावी युवाओं को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करती है। दरअसल इस योजना को बेहतर ढंग से तैयार किया गया है। इसके पहले कई रोजगार योजनाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने ऋण की व्यवस्था की थी, लेकिन वे भ्रष्टाचार और गलत सोच की भेंट चढ़ गए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ यह है कि संस्थानों में नामांकन लेने के बाद समय-समय पर आवश्यक राशि मिलती है। पैसे के दुरुपयोग होने की आशंका कम रहती है। उम्मीद है और लोग इसका लाभ लेंगे। पूरे देश में बिहार माडल लागू होना चाहिए।


नीतीश सरकार की सराहनीय पहल है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इंटरनेट मीडिया

> स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं पूरे देश में चलनी चाहिए। बिहार को देखकर कुछ अन्य राज्य इसे लागू कर रहे तो यह अच्छा कदम है

उत्तर प्रदेश

वसूली की याद

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (इविवि) का 30 प्रोफेसरों से नोटिस भेजकर 19 वर्ष पुराने खर्च का हिसाब मांगना चकित करता है। इस दौरान एक पूर्व कुलपति समेत कई प्रोफेसर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। विश्वविद्यालय ने उन्हें सेवा उपरांत प्रोविडेंट फंड, पेंशन आदि परिलाभ तभी दिए होंगे, जब अपना बकाएदार नहीं माना होगा। वैसे विश्वविद्यालय के मुताबिक वर्ष 2002 से अभी तक इन प्रोफेसरों ने यूनिवर्सिटी के काम से दूसरे शहर या राज्य जाने पर एडवांस रकम ली, मगर लौटने के बाद खर्च का कोई हिसाब-किताब नहीं दिया।

नियमानुसार दौरे से लौटने के अधिकतम दो हफ्ते के अंदर खर्च का ब्योरा देने का प्रविधान है। बावजूद इसके इन लोगों ने कोई जानकारी नहीं दी। इस सूची में प्रोफेसरों के साथ 30 जून को ही सेवानिवृत्त हुए विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति भी हैं, जिन्हें प्रशासनिक दायित्व संभालते हुए बखूबी पता होगा कि दस्तावेजों का पेट भरने के लिए खर्च के बिल आदि तो चाहिए ही। यही नहीं, लांछन यह भी है कि पूर्व कुलपति ने लाइब्रेरी से आवंटित 30 पुस्तकें भी नहीं लौटाईं। अब पुस्तकें वापस पाने के लिए विश्वविद्यालय को उनकी जुलाई की पेंशन रोकनी पड़ी है। यद्यपि पूर्व कुलपति दावा करते हैं कि उन्होंने न सिर्फ सभी किताबें लौटा दी हैं, बल्कि विश्वविद्यालय को 80 किताबें दान भी की हैं। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी दलील मानने को तैयार नहीं है। सभी को चेताया गया है कि हफ्तेभर में नोटिस का जवाब नहीं देने पर पेंशन रोकी जाएगी, तनख्वाह से कटौती होगी।

> यह बदनसीबी ही है जो इविवि अपना गौरवशाली इतिहास भी नहीं सहेज पा रहा। यह क्षरण रोका जाना चाहिए


कार्य संस्कृति पर सवाल : इलाहाबाद विश्वविद्यालय। फाइल

बकाएदारी का जिन्न अचानक बोतल के बाहर निकल आना यूनिवर्सिटी की बदहाल कार्य संस्कृति को तो उजागर करता ही है, आंतरिक राजनीति का भी संकेत देता है। दुर्भाग्य से कई विश्वविद्यालय ऐसे रोग से पीड़ित हैं। एक जमाने में 'पूरब के आक्सफोर्ड' में लोग इस भरोसे पर बच्चे भेजते थे कि उनका जीवन संवर जाएगा। होता भी यही था। कच्ची माटी से विद्यार्थी यहां आते और ज्ञान की भट्ठी में तपकर देश-दुनिया में नाम रोशन करते। ऐसे में यह बदनसीबी ही है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना गौरवशाली इतिहास भी नहीं सहेज पा रहा। यह क्षरण हर हाल में रोका जाना चाहिए।

बंगाल

लाल-नीली बत्ती के प्रयोग पर सवाल

करीब चार साल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में लालबत्ती कल्चर पर विराम लगा दिया था। बावजूद इसके केंद्र के नियम को बंगाल में लागू नहीं किया गया। बीते सप्ताह तक बंगाल में लालबत्ती लगी गाड़ी में नेता-मंत्री घूम रहे थे। यहां तक कि कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम मौलाना बरकती भी लालबत्ती लगी गाड़ी में घूमा करते थे। इसे लेकर मई 2017 में काफी काफी विवाद हुआ था और बाद में उनका लालबत्ती के साथ-साथ शाही इमाम का पद भी छिन गया था। बावजूद इसके बंगाल में मंत्री से लेकर कई नौकरशाह और वीआइपी लाल से लेकर नीली बत्ती लगी गाड़ियों में घूमा करते थे। परंतु पिछले दिनों जब फर्जी आइएएस, आइपीएस से लेकर सीबीआइ और सीआइडी अधिकारियों का भंडाफोड़ हुआ और इन सभी जालसाजों द्वारा लाल-नीली बत्ती इस्तेमाल की बातें सामने आईं तो राज्य प्रशासन की नींद टूटी है और बत्ती के इस्तेमाल पर सख्ती शुरू की है।

> अधिसूचना में केवल उन्हीं का जिक्र है जो आपातकालीन या आपदा प्रबंधन दायित्वों से जुड़े हुए हैं। इसे लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए

वीवीआइपी और वीआइपी बत्ती को लेकर बंगाल परिवहन विभाग नए नियम बनाए हैं जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया है। परिवहन मंत्री से जब यह पूछा गया कि चार प्रमुख लोगों का नाम शामिल नहीं है तो उनका तर्क था कि वे सभी लोग सूचियों से ऊपर हैं। वे अपने वाहनों पर लाल-नीली बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिसूचना में केवल उन्हीं का जिक्र है, जो आपातकालीन या आपदा प्रबंधन दायित्वों से जुड़े हुए हैं। इसे लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। परिवहन अधिकारी का कहना है कि नई सूची छूट पाने एवं लाभ लेने के लिए खुद को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताने और अपने वाहनों पर नीली बत्ती लगाकर चलने वाले कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद प्रकाशित की गई है। इसीलिए इस पर किसी भी विवाद का कोई सवाल ही नहीं है। हमने यह सूची केवल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रकाशित की है कि अनधिकृत लोग नियमों का उल्लंघन नहीं करें। अधिसूचना के अनुसार सभी मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव रैंक के अधिकारी, संभागीय आयुक्त, डीजीपी, एडीजीपी, आइजीपी, अग्निशमन सेवा के डीजी, आबकारी, वाणिज्यिक कर आयुक्त और सभी जिलाधिकारी, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ और पुलिस गश्त वाहन और दमकल की गाड़ियों पर बत्तियां लगाई जा सकती हैं। सूची में नेता प्रतिपक्ष का भी नाम नहीं है। इसे लेकर सवाल उठना लाजिमी है। हालांकि लाल बत्ती कल्चर खत्म होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में इस तरह की संस्कृति नहीं होनी चाहिए।

श्रद्धा का महासावन

जहां शिव, वहां आनंद ही आनंद

शिव आदि देव हैं। शिव महादेव हैं। सभी देवों में भगवान शिव को सर्वोच्च स्थान हासिल है। ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। पुराणों में उन्हें महादेव के रूप में स्वीकार किया गया है। जब सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, दिन था न रात्रि, सत था न असत, तब केवल निर्विकार शिव ही थे। शिव ही दाता हैं और भोक्ता भी शिव ही हैं। जो दिखाई पड़ रहा है, वह सब शिव ही है। शिव का अर्थ है आनंद। शिव का अर्थ है परम मंगल, परम कल्याण। सामान्यतः ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालक और शिव का संहारक माना जाता है, लेकिन, मूलतः शक्ति एक ही है जो तीन अलग-अलग रूपों में अलग-अलग कार्य करती है। वह मूल शक्ति शिव ही हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि ब्रह्मा, विष्णु व शंकर की उत्पत्ति माहेश्वर अंश से ही होती है। सृष्टि का आदि कारण शिव ही हैं। इस ब्रह्मांड व्यवस्था में परमात्मा के पारमार्थिक आनंदमय स्वरूप को प्रकट करने वाली शक्ति को हम विद्या व अविद्या कह सकते हैं। शिव के रूप में हम लिंग की पूजा क्यों करते हैं, इसका रहस्य शिव पुराण, लिंग पुराण व स्कंद पुराण में बताया गया है। सृष्टि का अनादि तत्व शिव हैं। वही कारण हैं सृष्टि, स्थिति और प्रलय का। उन्हीं शिव का स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में है। इस ज्योतिर्लिंग में ही सबकुछ समाहित है। शिवलिंग की जलहरी ब्रह्मांड का स्वरूप है। पूरा ब्रह्मांड शिव का ही साकार स्वरूप है। शिव का स्वरूप निराकार एवं साकार दोनों है।


भीमाशंकर लिंग
रावल, केदारनाथ धाम

स्कैन करें और पढ़ें 'श्रावण मास' से संबंधित सभी सामग्री

बीएसएफ जवानों ने छह सैनिकों को डूबने से बचाया

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के गश्ती दल ने छह सैनिकों को कोरी क्रीक में डूबने से बचा लिया।

बीएसएफ ने बताया कि रविवार को कोरी क्रीक (समुद्र की संकरी खाड़ी) में छह सैनिक नियमित अभ्यास कर रहे थे। तभी उनकी नाव पलट गई और वे डूबने लगे। नजदीक में ही गश्त कर रही बीएसएफ की टीम वहां पहुंची और सैनिकों को सुरक्षित निकाला। स्पीड बोट से उन्हें लक्की नाला पर लाया गया तथा बीएसएफ एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर के महानिरीक्षक जीएस मलिक ने टीम के कमांडर को दो हजार रुपये तथा अन्य सात सदस्यों को एक-एक हजार रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की।

अलबेली सरकार की चाकरी में पूर्व सरकारी अफसर

विनीत मिश्र, मथुरा

- सरकारी नौकरी के बाद कान्हा की भक्ति में रम गए बड़े अफसर
- किसी ने ब्रजवास किया, किसी ने राधा-कृष्ण को ही माना जीवन का आधार

ये ब्रज है, यहां अलबेली सरकार (राधारानी) का राज चलता है। प्रेम में रीझ जिसके आदेशों को कान्हा न टाल पाए, तो जनसामान्य की क्या मजाल। सो सेवानिवृत्ति के बाद कई अफसर यहां उनकी चाकरी को खिंचे चले आए।

ताजा उदाहरण बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का है। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त के बाद पांडे कथावाचक बन गए हैं। वृंदावन में पहली कथा कहने आए पांडे ने साफ कहा कि वह अब कान्हा के हाथों की वंशी हैं, जैसे बजाएंगे वैसे बजूंगा। उनसे पहले 2009-10 में बिहार में ही डीजीपी रहे आनंद शंकर की तो आत्मा ही ब्रज में बसती है। 2010 में सेवानिवृत्त के बाद वह 2013 में बरसाना घूमने आए। फिर वापस होने की इच्छा नहीं हुई। बरसाना की श्रीमाता जी गोशाला में वह गोसेवा और राधारानी का सुमिरन कर जीवन गुजार रहे हैं, जिस शख्स के तन पर खाकी वर्दी देख बड़े-बड़े अपराधी डरते थे, वह शख्स भक्ति में ऐसा रमा कि पहनावे के नाम पर साधारण कुर्ता-पायजामा है और गले में तुलसी की माला। माथे पर चंदन का टीका।

गोशाला में ही एक कमरे में जमीन पर चटाई बिछाकर सोना आनंद शंकर की दिनचर्या में है। सुबह-शाम गायों को हाथों से चारा खिलाते हैं। कहते हैं कि अब पूरा जीवन हमने श्रीजी और बरसाना को सौंप दिया है। यहां आनंद मिलता है।

रिटायर्ड जज भी करते रहे ब्रजवास : दिल्ली में जज रह चुके अलीगढ़ निवासी विपिन चंद्र को भी अध्यात्म और ब्रज ऐसा रास आया कि रिटायर होने के बाद वह वृंदावन के अखंडानंद आश्रम में 17 साल रहे। करीब पांच साल पहले उनका निधन हुआ। यहां आकर उन्होंने अपना नाम दंडी स्वामी विपिन चंद्र महाराज रखा और वृंदावन में ही भगवत भजन करते रहे।


बरसाना स्थित श्रीमाता जी गोशाला में गायों को दुलारते पूर्व डीजीपी आनंद शंकर। जागरण

पुलिस महानिरीक्षक पंडा भी रहे कान्हा के दीवाने

कान्हा के दीवानों की सूची लंबी है। 2005 में उप्र के पुलिस महानिरीक्षक रहते डीके पंडा भी कृष्ण के प्रेम में ऐसा सम्मोहित हुए कि सखी रूप धारण कर लिया। भले ही उस दौरान वह ब्रज नहीं आए, लेकिन खुलेआम खुद को कृष्ण की दूसरी राधा बताया। पंडा का ये सखी रूप काफी चर्चा में रहा।

पुरी में 24 घंटे टैप से मिलेगा शुद्ध पेयजल

जागरण टीम, भुवनेश्वर : ओडिशा स्थित श्रीजगन्नाथ धाम पुरी को विश्वस्तरीय शहर बनाने की दिशा में 'ड्रिंक फ्राम टैप' मिशन की शुरुआत हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को इस व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस योजना से न सिर्फ पुरी शहर के ढाई लाख लोगों को 24 घंटे टैप के जरिये शुद्ध पेयजल मिलेगा, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों को भी अब शुद्ध पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्हें पानी की बोतल भी नहीं खरीदनी होगी क्योंकि जहां भी ठहरेंगे, उन्हें उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध पेयजल टैप के जरिये उपलब्ध होगा।

इससे पुरी आने वाले सालाना दो करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेयजल मिलेगा। ऐसे में, प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने वाले दुनिया के प्रमुख शहरों में पुरी शहर भी शामिल हो गया है। इस व्यवस्था के शुरू हो जाने से पुरी न सिर्फ ओडिशा, बल्कि देश का पहला शहर बन गया है। इस योजना के शुरू हो जाने से पुरी शहर में सालाना चार लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक वर्ज्य वस्तु में भी कमी आएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल पुरी ही नहीं, बल्कि पूरा ओडिशा विकास की नई गाथा लिख रहा है। पुरीवासियों को अब फिल्टर रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उन्हें 24 घंटे शुद्ध पेयजल टैप के जरिये मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था शुरू करने के लिए लंदन, लांस एंजिल्स तथा सिंगापुर जैसे शहरी क्षेत्र में अब पुरी भी शामिल हो गया है। जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ संबोधन शुरू करते हुए कहा कि मिशन शक्ति की महिलाएं जल साथी बनी हैं। महाप्रभु के आशीर्वाद से जगन्नाथ धाम में एक के बाद एक योजना शुरू की जा रही है।

पुराना है दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद


असम के कछार जिले में सोमवार को मिजोरम से लगी सीमा पर असम पुलिस और उपद्रवियों के बीच हिंसक झड़प हुई। प्रेट्र

असम और मिजोरम का सीमा विवाद पुराना मसला है। अब तक इसे हल करने के लिए कई कोशिशें हुईं, लेकिन खास नतीजा नहीं निकल पाया। 2018 में हुई हिंसा के बाद पिछले साल अगस्त में फिर मामला उभरा था। इस साल फरवरी में हालात गड़बड़ाए थे, लेकिन केंद्र के हस्तक्षेप से स्थिति संभल गई थी।

डेढ़ सौ बरस पुरानी है जड़

इस विवाद की जड़ सीमांकन को लेकर 1875 और 1933 में आए दो अलग-अलग नोटिफिकेशन में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, मिजोरम का मानना है कि सीमांकन 1875 के नोटिफिकेशन के आधार पर होना चाहिए। मिजो नेता इस तर्क के आधार पर 1933 के सीमांकन नोटिफिकेशन को खारिज करते हैं कि इसमें मिजो समाज से बात नहीं की गई। वहीं, असम सरकार 1933 के सीमांकन को मानती है और इसी में विवाद है। मिजोरम के तीन जिले आइजल, कोलासिब और मामित की 164.6 किलोमीटर की सीमा असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों से लगती हैं। मिजोरम का आरोप है कि असम ने इसके कोलासिब जिले के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वहीं, असम के अधिकारी कहते हैं कि मिजोरम ने उसके हैलाकांडी जिले में 10 किलोमीटर अंदर तक निर्माण किया हुआ है और केले आदि की खेती।

कुछ अन्य राज्यों के सीमा विवाद

- महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमा विवाद है। महाराष्ट्र वहां के कुछ मराठी भाषी सीमाई इलाकों को अपनी सीमा में चाहता है।
- कर्नाटक और केरल के बीच केरल के कासरगोड़ जिले को लेकर विवाद है।
- नदियों की धारा में बदलाव के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ सीमाई इलाकों में विवाद रहता है।
- ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच 63 गांवों को लेकर विवाद है, जो अभी ओडिशा की सीमा में आते हैं।

जागरण विशेष

नीरज • शिवहर

बिहार का एक गांव जो 43 बार बाढ़ में बहा और फिर बसा

शिवहर का नरकटिया गांव 87 साल से झेल रहा बाढ़ की विभीषिका, तबाही के बाद भी ग्रामीणों का हौसला नहीं कम

यह कहानी नरकटिया के ग्रामीणों की जिजीविषा और सबकुछ खोकर फिर से खड़ा होने की जीवटता की है। बागमती की बाढ़ से उजड़ना उनकी नियति है तो पुरुषार्थ से फिर गांव को आबाद करना कर्म है। बीते 87 साल में 43 बार यह गांव उजड़ चुका है। इसके बावजूद ग्रामीणों ने हार नहीं मानी है। इस बार भी यही स्थिति है। बेघर हो चुके ग्रामीण बरसात बीत जाने का इंतजार कर रहे हैं। उजड़ गया गांव ग्रामीण एक बार फिर आबाद करेंगे।

गांव में तीन सौ घर, आबादी डेढ़ हजार: बिहार के शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड की बेलवा पंचायत स्थित नरकटिया गांव में तीन सौ घर हैं। आबादी तकरीबन डेढ़ हजार है। यह गांव कभी बाढ़ की तबाही से दूर था, लेकिन वर्ष 1934 में आए भूकंप के चलते दो किलोमीटर दूर बहने वाली बागमती की धारा मुड़कर गांव के पास पहुंच गई। उस साल बरसात में पहली बार बागमती ने तबाही मचाई। उसके बाद से हर साल दो साल में तबाही नियति बन गई।

नहीं बनाता कोई पक्का घर: गांव के सबसे बुजुर्ग 85 वर्षीय ब्रह्मदेव सहनी कहते हैं कि वह अब तक 50 बार बाढ़ का कहर देख चुके हैं। 20 बार तो अपना घर बना चुके हैं। ग्रामीण सत्यनारायण सहनी कहते हैं कि बागमती की तबाही के चलते गांव में कोई पक्का घर नहीं बनाता। महज 10 पक्के मकान बने हैं। बरसात शुरू होने से पहले अधिकतर घरों की महिलाएं बच्चों को लेकर रिश्तेदारों के घर चली जाती हैं। बरसात में बीमार को अस्पताल पहुंचाना काफी मुश्किल होता है। रामचंद्र मांझी बताते हैं कि पिछले साल बागमती के कटाव में 47 घर बह गए थे। सभी कच्चे घर गिर गए थे। इस बार पहली जुलाई को बाढ़ में 50 घर बह गए। बहुत से घर गिर गए हैं। लोग प्लास्टिक टांगकर और मचान बनाकर रह रहे हैं। बरसात के बाद सितंबर में ग्रामीण फिर से घर बनाने में जुट जाएंगे।


बाढ़ की पीड़ा बयान करते सत्यनारायण सहनी (दाएं) • जागरण

> नरकटिया को बाढ़ से बचाने के लिए बेलवाघाट पर डैम बन रहा है। इसके जरिए बागमती के पानी को रोककर उसकी पुरानी धारा में डिस्चार्ज किया जाएगा। निर्माण वर्ष 2020 में ही पूरा करना था, लेकिन बाढ़ की वजह से कार्य प्रभावित हुआ है। इसे जल्द पूरा किया जाएगा।
>
> -सज्जन राजशेखर, जिलाधिकारी

बदलता रहता है गांव का नक्शा

दवा व्यवसायी मनोज कुमार की आधी से अधिक जमीन समेत घर बागमती की धारा में विलीन हो चुका है। वह कहते हैं कि बागमती कब धारा बदल ले और किसके घर को बहाकर ले जाए, बता पाना मुश्किल है। इसके बाद भी हम हार मानने वालों में नहीं हैं। नदी से कोई शिकवा नहीं है। शिकायत व्यवस्था से है। इस गांव में एक दशक से कोई अधिकारी नहीं आया। बाढ़ के दौरान दूर से अधिकारी जायजा लेकर चले जाते हैं। मुखिया कमलेश पासवान का कहना है कि बाढ़ से उजड़ने के बाद ग्रामीण दूसरी जगह घर बनाते हैं। इस कारण गांव का नक्शा बदलता रहता है। इसी के चलते हर घर नल का जल, सड़क और शौचालय जैसी सुविधाओं का लाभ इस गांव को नहीं मिल सका है। बिजली की सुविधा है।

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें


बागमती नदी में आई बाढ़ के पानी में घिरा शिवहर का नरकटिया गांव • जागरण

महाराजा अग्रसेन के नाम पर होगा हिसार एयरपोर्ट का नाम

जासं, हिसार : हरियाणा के हिसार में बन रहे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने सोमवार को इसकी घोषणा की।

सरकार इस एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित कर रही है। तीन चरणों में इसको विकसित किया जाएगा। पहला चरण पूरा हो चुका है और हिसार से चंडीगढ़, देहरादून और धर्मशाला के लिए विमान उड़ाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार हो रहा है जो 2022 में पूरा होगा। रनवे विस्तार के बाद यहां बड़े विमान उतर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने करीब सात हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। यहां नौ हजार फीट रनवे, एयरलाइंस, जनरल एविएशन, विमानों के रख-रखाव, मरम्मत, ओवर हालिंग की सुविधाएं, एयरो स्पेस विश्वविद्यालय, पायलट, इंजीनियरों और ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ के लिए ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर बनाया जाएगा।

12 वीं बार ताइवान में घुसपैठ की है चीन के लड़ाकू विमानों ने महीने भर के अंदर। पीएलएएएफ ने दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र में पनडुब्बी रोधक शांग्जी वाई-आठ युद्धक विमानों को तैनात किया है।

तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले करता रहेगा अमेरिका

संघर्ष ▶ अफगान सेना के समर्थन में कंधार में आतंकियों पर बरसाए गए बम, गजनी में आतंकियों ने की 43 लोगों की गोली मारकर हत्या

जनरल मैकेंजी ने कहा, हिंसा की वारदातों में तेजी के चलते बढ़ाने पड़े हवाई हमले

काबुल, रायटर : अफगानिस्तान पर तालिबान के लगातार बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका फिर से सक्रिय हो गया है। उसने अफगान सरकार को सैन्य कार्रवाई में मदद का भरोसा दिलाया है। काबुल में तैनात अमेरिकी सेना के जनरल केनेथ एफ मैकेंजी ने कहा है कि तालिबान के ठिकानों पर उनके हवाई हमले जारी रहेंगे। इसका असर कंधार में दिखने लगा, जहां अमेरिकी विमानों ने कमजोर पड़ती अफगान सेना के पक्ष में आतंकियों पर बम बरसाए।


केनेथ एफ मैकेंजी

काबुल में सोमवार को एक पत्रकार वार्ता में सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा, तालिबान हिंसा की वारदातों में तेजी ला रहा है। इसी कारण अमेरिकी सेना ने कुछ दिनों से हवाई हमले बढ़ा दिए हैं। अफगान सैनिकों की मदद के लिए ये हवाई हमले अगले हफ्तों में भी जारी रहेंगे। जब मैकेंजी से पूछा गया कि क्या अमेरिकी सेना की 31 अगस्त को पूरी तरह वापसी के बाद भी हवाई हमले किए जाएंगे, उन्होंने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। उन्होंने संभावना जताई कि मुस्लिम त्योहार निकलने के बाद तालिबान हिंसा में वृद्धि कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि शहरों पर कब्जा करने में तालिबान सक्षम हो पाएगा।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री लायड आस्टिन ने भी कहा था कि अफगान सेना अपनी युद्ध रणनीति को प्रभावी बना रही है। प्रांतीय राजधानी और बड़े शहरों में उसकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है। जिलों को फिर नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रही है।

समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार, आतंकियों का खूनी खेल थम नहीं रहा है। इस बार आतंकियों ने गजनी प्रांत के मलिस्तान जिले को अपना निशाना बनाया। यहां 43 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इनमें सुरक्षा बल के कुछ सदस्य भी थे। टोलो न्यूज के अनुसार ऐसी ही घटनाएं तालिबान आतंकियों ने अन्य क्षेत्रों में की हैं। यहां के रहने वालों ने बताया कि आतंकियों ने ऐसे लोगों की हत्या की, जिनका युद्ध से कोई संबंध नहीं था। मलिस्तान में तोड़फोड़ और लूटपाट भी की गई। तालिबान के आंतरिक मंत्री ने इस नरसंहार की पुष्टि की है। आइएएनएस के अनुसार, हेलमंद व बदख्शान प्रांत में सेना ने तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस कार्रवाई में 35 आतंकी मारे गए। उल्लेखनीय है कि विभिन्न प्रांतों में हमले तेज करने और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने वाला तालिबान यह भी कह रहा है कि उसका देश की सत्ता पर कब्जे का इरादा नहीं है।

अफगान शांति वार्ता का अगला दौर अगस्त में

एएनआइ के अनुसार अफगान सरकार और तालिबान के बीच अगले दौर की शांति वार्ता अगस्त में हो सकती है। जुलाई माह के पहले सप्ताह में कतर की राजधानी दोहा में दोनों ही पक्षों की वार्ता दोबारा शुरू हुई थी। वार्ता में युद्ध विराम पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी।

46 अफगान सैनिक भागकर पहुंचे पाकिस्तान

रायटर के अनुसार, पाकिस्तान सेना ने दावा किया है कि उसकी सीमा से लगी सुरक्षा चौकियों पर तैनात 46 अफगान सैनिक तालिबान के हमले के बाद भागकर उनके यहां आ गए हैं। यह घटना चित्राल क्षेत्र की बताई गई है।

अफगान सेना प्रमुख का भारत दौरा रद

काबुल, एएनआइ : अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों की तेजी से बढ़ रही हिंसा और नागरिकों की लगातार हो रही हत्या के बाद अफगान सेना प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमदजई का तीन दिवसीय भारत दौरा रद हो गया है। अहमदजई को 27 जुलाई को भारत जाना था, जहां उन्हें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख एम एम नरवणे व अन्य अधिकारियों से मिलना था। प्रेट्र के अनुसार भारत स्थित अफगान दूतावास ने कहा है कि तालिबान के युद्ध में तेजी लाने के बाद हमारे सेना प्रमुख का दौरा रद कर दिया गया है। ज्ञात हो, अफगान सेना तालिबान से निबटने की तैयारी में लगी हुई है। इसीलिए वहां के मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला के भी विदेश दौरे तेज हो गए हैं, जो अपने सहयोगी देशों से ताजा हालात पर वार्ता कर रहे हैं।


अफगान सेना प्रमुख जनरल वली मुहम्मद अहमदजई का फाइल फोटो। सौ. ट्विटर

2021 में हो सकती है सबसे ज्यादा नागरिकों की मौत

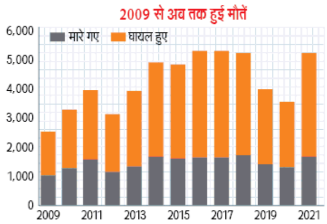
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के छह माह में अफगानिस्तान में 5183 नागरिक हताहत हुए हैं। इनमें से 1659 नागरिकों की हत्या कर दी गई और 3254 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिछले साल की इसी समयावधि के तुलना में यह 47 फीसद ज्यादा है। जब से अमेरिकी सैनिकों ने यहां से कूच किया, आतंकी हमलों में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि अभी साल के पूरे होने में कई महीने बाकी हैं। इस लिहाज से ये साल सबसे ज्यादा नागरिकों की जान लेने वाला बन सकता है।

64% मौतों के लिए आतंकी संगठन जिम्मेदार

25% मौतों के लिए सरकार समर्थित संगठन जिम्मेदार

11% दोनों धड़ों के बीच हुई गोलीबारी में हुई मौतें

2009 से अब तक हुई मौतें



अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन आज आएंगे भारत

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दो दिनी दौरे पर मंगलवार को भारत पहुंच रहे हैं। अफगानिस्तान में तेजी से बदलती सुरक्षा स्थिति, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना और कोरोना के खिलाफ प्रयास को मजबूत करने के तरीकों समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा उनके विस्तृत एजेंडे में शामिल है।

अमेरिकी विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद ब्लिंकन की यह पहली भारत यात्रा होगी। जनवरी 2021 में सत्ता में आने के बाद बाइडन प्रशासन के किसी उच्च पदस्थ अधिकारी की यह तीसरी भारत यात्रा होगी। रक्षा मंत्री लायड आस्टिन ने मार्च में भारत का दौरा किया था। जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका के विशेष दूत जान केरी अप्रैल में दिल्ली आए थे। ब्लिंकन का अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलने का कार्यक्रम है। वह बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे कुवैत के लिए रवाना हो जाएंगे।

विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि ब्लिंकन का दौरा द्विपक्षीय वार्ता को जारी रखने और भारत-अमेरिकी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देने का अवसर है। दोनों पक्ष मजबूत और बहुआयामी संबंधों की समीक्षा करेंगे और उन्हें और मजबूती देने की संभावनाओं को टटोलेंगे। इस दौरे के एजेंडे के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि दोनों पक्ष अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से बातचीत करेंगे, जिसमें देश के नए इलाकों पर कब्जा जमाने की तालिबान की बढ़ती कोशिशों पर चर्चा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी संभावनाएं तलाशेंगे, जिनमें इस साल अमेरिका में होने वाली टू प्लस टू बैठक से पहले सैन्य अभ्यास, रक्षा हस्तांतरण और प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं।

गुलाम कश्मीर के चुनाव में जमकर धांधली, विपक्ष ने कहा-लेंगे भारत की मदद

- पीएमएल-एन नेता मरयम नवाज ने कहा, इमरान की पार्टी की जीत स्वीकार नहीं
- हिंसा के बीच सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, चुनाव आयोग ने भी चुप्पी साधी


मरयम नवाज। फाइल/इंटरनेट मीडिया

मुजफ्फराबाद, एएनआइ : गुलाम कश्मीर (गिलगिट-बाल्टिस्तान) में इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने हिंसा, धांधली और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर भले ही चुनाव जीत लिया है, लेकिन विपक्षी इस जीत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन के कद्दावर नेता चौधरी मुहम्मद इस्माइल गुज्जर ने तो यहां तक कहा है कि धांधली की जांच नहीं हुई तो वह भारत की मदद लेने से भी गुरेज नहीं करेंगे। विपक्षी नेता मरयम नवाज का साफ कहना है कि यह जीत हमें स्वीकार नहीं, इमरान की पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और हिंसा के बल पर जीत हासिल की है। ज्ञात हो, रविवार को हुए मतदान के दौरान कई क्षेत्रों में हिंसा हुई, जिसमें इमरान खान की पार्टी के दो कार्यकर्ताओं की मौत हो गई।

मरयम नवाज ने ट्वीट कर कहा है कि न तो मैंने इस जीत को स्वीकार किया है और न ही करूंगी। उन्होंने अपनी पार्टी के नेता अताउल्लाह तरार समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की भी निंदा की।

पीएमएल-एन के नेता और प्रत्याशी चौधरी मुहम्मद इस्माइल गुज्जर ने कहा, चुनाव में पूरी तरह से अराजकता रही है। प्रशासन सत्ता दल का साथ दे रहा था। चुनाव आयोग इमरान का एजेंट बनकर काम करता रहा। उनके चुनाव शिविर को नष्ट कर दिया गया। यह सब पुलिस की मौजूदगी में किया गया। प्रशासन और आयोग ने यदि कोई कार्रवाई नहीं की, तो वह और उन जैसे कई प्रत्याशी भारत की मदद लेंगे। 32 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में हुए चुनाव में कुल सात सौ प्रत्याशी मैदान में थे। 53 सदस्यीय विधान सभा में 45 सीटों पर चुनाव हुए। प्रेट्र के अनुसार चुनाव में इमरान की तहरीक ए-इंसाफ-पार्टी (पीटीआइ) ने 25 सीटों पर जीत हासिल की है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने 11 सीटें जीती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) को छह सीटें मिली हैं।

पाक नेता ने कहा, यहां की जनता गुलाम मानसिकता की

एएनआइ के अनुसार, गुलाम कश्मीर के तथाकथित प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर ने चुनाव हारने के बाद कश्मीरी जनता के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने जनता को गुलाम मानसिकता का बताया। हैदर ने कहा कि यहां की जनता ढाई सौ साल गुलामी में रहने के बाद पूरी तरह गुलाम बन गई है। हैदर नवाज शरीफ की पार्टी के नेता हैं, वह अभी तक सत्ता में थे।


गुलाम कश्मीर (गिलगिट-बाल्टिस्तान) में हुए चुनाव के दौरान कई स्थानों पर हिंसा हुई। इस दौरान मतदान केंद्र पर नारे लगाता राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता (फाइल फोटो)। रायटर

अमेरिका से द्विपक्षीय वार्ता में चीन हुआ आक्रामक

बीजिंग, रायटर : चीन ने तियानजिन में सोमवार से शुरू राजनयिक स्तरीय वार्ता में अमेरिका पर द्विपक्षीय संबंध में गतिरोध का आरोप लगाया है। आक्रामक रुख अपनाते हुए चीन ने पहली बार अमेरिका को अपनी मांगों की फेहरिस्त थमा दी। उसने अमेरिका से कहा कि वह चीनी छात्रों और उनकी सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के खिलाफ वीजा पर लगे प्रतिबंधों को हटा दे। साथ ही चीनी कंपनियों और कंफ्यूशस संस्थानों का उत्पीड़न बंद करने का भी आग्रह किया है। उसने अमेरिका में चीनी दूतावास और राजदूत के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि चीनी और एशियाई लोगों पर नस्ली हमले किए जाते हैं।

चीन के उप विदेश मंत्री शी फेंग ने अमेरिका की नीतियों को खतरनाक और मानसिकता को गलत बताते हुए इसमें बदलाव लाने को कहा है। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, शी ने अमेरिकी समकक्ष वेंडी शरमन से बातचीत में कहा, चीन-अमेरिका के संबंधों में अभी गतिरोध है क्योंकि कुछ अमेरिकी चीन को दुश्मन के तौर पर आंकने लगे हैं। बाइडेन प्रशासन में नंबर दो राजनयिक मानी जाने वाली शरमन चीन जाने वाली पहली उच्चाधिकारी हैं।

- चीनी छात्रों और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को वीजा देने का आग्रह
- चीनी सरकार का अमेरिका पर संबंधों में गतिरोध का आरोप


चीन के उप विदेश मंत्री शी फेंग अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत करने से पहले अपने सहयोगियों के साथ। एपी

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी उप विदेश मंत्री शरमन और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी सोमवार को ही यहां पहुंचे हैं। अमेरिका व चीन संबंधों के प्रभारी शेई फेंग और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ शरमन तियानजिन के रिसार्ट में बैठक करेंगी। इसी साल अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने जो बाइडन द्वारा देश की कमान संभाले जाने के बाद शरमन चीन का दौरा करने वाली पहली शीर्ष अमेरिकी अधिकारी हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में चीन व अमेरिका के आपसी संबंध काफी खराब हो गए और प्रौद्योगिकी, साइबर सिक्योरिटी, मानवाधिकार समेत कई मामलों पर दोनों के बीच तनावपूर्ण हालात हैं।

गत दिवस एक साक्षात्कार में वांग ने अमेरिका के बर्ताव पर सवाल उठाया और कहा कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल अन्य देशों को दबाने में कर रहा है। उन्होंने चीन के फिनिक्स टेलीविजन को बताया, 'चीन दूसरे को कुचलने वाले किसी भी देश को स्वीकार नहीं करेगा। यदि अमेरिका दूसरे देशों के साथ एक समान व्यवहार करना नहीं सीख सकता तो चीन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इसे सीखने में अमेरिका की मदद करनी होगी।' बाइडन प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि इन वार्ताओं का मकसद किसी विशेष मामले पर चर्चा नहीं बल्कि उच्च स्तरीय संवाद के माध्यम खुले रखना है। बाइडन और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच भी अक्टूबर अंत में रोम में जी-20 शिखर सम्मेलन से अलग बैठक होने की संभावना है।

अब दुनिया भर में विजय माल्या की संपत्तियां होंगी जब्त

लंदन, प्रेट्र: ब्रिटिश हाई कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। साथ ही भारतीय बैंकों के लिए दुनिया भर में फैली उसकी संपत्तियों की जब्ती का रास्ता आसान हो गया है। माल्या ने अब बंद हो चुकी अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए भारतीय बैंकों से नौ हजार करोड़ रुपये से ज्यादे का कर्ज लिया था और जब कंपनी डूबी तो कर्ज चुकाए बिना ही वह लंदन भाग गया। माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ ने ब्रिटिश कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

भारत में माल्या की बैंकों के साथ धोखाधड़ी व मनी लांड्रिंग मामले में तलाश है। ब्रिटेन में अभी वह जमानत पर है और उसने वहां शरण लेने के लिए अपील भी कर रखी है। हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन की वर्चुअल सुनवाई के दौरान चीफ इंसाल्वेंसी एंड कंपनी कोर्ट (आइसीसी) के जज माइकल ब्रिग्स ने माल्या को दिवालिया घोषित किया है। जज ने कहा कि उन्हें यह तय करना है कि क्या निश्चित अवधि में याचिका को ऋण के पूर्ण भुगतान की वास्तविक संभावना है। जज ने यह भी कहा कि इसकी संभावना बहुत कम है कि माल्या द्वारा उचित समय में पूर्ण कर्ज का भुगतान किया जाएगा। माल्या के वकील ने फैसले को ऊंची अदालत में चुनौती देने का संकेत दिया है। सुनवाई के दौरान जज ने माल्या के वकील से पूछा,क्या उनके मुवक्किल के आपराधिक मामलों का सामना करने के लिए भारत जाने की संभावना है। वकील ने कहा, कतई नहीं है।

- ब्रिटिश हाई कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी को दिवालिया घोषित किया
- भारतीय बैंक अब उसकी संपत्तियों को बेचकर कर सकेंगे कर्ज वसूली


विजय माल्या। फाइल/इंटरनेट मीडिया

संबंधों में सुधार के लिए आज से सऊदी विदेश मंत्री का पाक दौरा

इस्लामाबाद, प्रेट्र : हाल के वर्षों में पाकिस्तान के साथ संबंधों में आई खटास को दूर करने के उद्देश्य से सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद मंगलवार को इस्लामाबाद आ रहे हैं। वह पाकिस्तानी नेताओं से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर चर्चा करेंगे।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रिंस फैसल के साथ सऊदी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी इस्लामाबाद आएगा। सऊदी विदेश मंत्री का यह दौरा पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के आमंत्रण पर हो रहा है। प्रिंस फैसल अपने दौरे में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मिल सकते हैं। इससे पहले मई में संबंधों में सुधार की कोशिश के तहत प्रधानमंत्री इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी विदेश मंत्री का यह दौरा दोनों देशों के संबंधों को और विकसित करने के उद्देश्य से हो रहा है। संबंधों का यह विकास दोनों देशों के नेतृत्व की सोच के मद्देनजर होगा।


प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद। फाइल/इंटरनेट मीडिया

वर्षों की खटास के बाद संबंधों में सुधार की गंभीर कोशिश

सऊदी अरब और पाकिस्तान के दशकों के प्रगाढ़ संबंध रहे हैं लेकिन इसमें खटास की शुरुआत तब हुई जब 2015 में पाकिस्तान ने यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व में छिड़े युद्ध में अपने सैनिक भेजने से इन्कार किया। सऊदी अरब और भारत के बढ़ते संबंधों से भी पाकिस्तान विचलित हुआ। इसके बाद जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सऊदी अरब ने जिस तरह पाकिस्तान के विरोध का साथ नहीं दिया, उससे भी पाकिस्तानी नेता बौखलाए। इसी दौरान पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर मुस्लिम देशों का अलग मंच तैयार करने की कोशिश की जिससे सऊदी अरब नाराज हो गया। उसने न केवल उधार के तीन अरब डॉलर लौटाने के लिए पाकिस्तान से कहा बल्कि उसकी तेल आपूर्ति भी रोक दी थी।



फिलीपींस में प्रदर्शन

फिलीपींस में खराब अर्थव्यवस्था का असर अब लोगों के जीवन पर भी पड़ रहा है। सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सोमवार को सड़कों पर उतर कर भारी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। एपी

इंडोनेशिया में बच्चों के लिए जानलेवा बन रहा कोरोना

न्यूयार्क टाइम्स से

जकार्ता : इंडोनेशिया में कोरोना महामारी बच्चों के लिए जानलेवा होती जा रही है। यहां हालिया हफ्तों में इस खतरनाक वायरस की चपेट में आकर सैकड़ों बच्चों की जान जा चुकी है। मरने वालों में कई पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी बताए जाते हैं। बच्चों की मौत के मामले ऐसे समय सामने आ रहे हैं, जब इस दक्षिण-पूर्व एशियाई देश में कोरोना के डेल्टा वैरिएंट का कहर बढ़ गया है।

दुनिया में चौथी सबसे बड़ी आबादी वाला देश इंडोनेशिया इस महीने कोरोना संक्रमण कके दैनिक मामले में भारत और ब्राजील से आगे निकल गया है। सरकारी डाटा के अनुसार, देश में शुक्रवार को करीब 50 हजार नए केस पाए गए और 1,566 पीड़ितों की मौत हुई। इस माह संक्रमित पाए गए लोगों में 12.5 फीसद बच्चे बताए गए हैं। बीते एक हफ्ते में कोरोना से 150 से ज्यादा बच्चों की जान गई। महामारी शुरू होने के बाद से कुल 800 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। इनमें से ज्यादातर मौत गत माह हुई। ज्ञात हो कोरोना महामारी से पूरी दुनिया हलकान है। वायरस के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।


इंडोनेशिया में कोरोना संक्रमण बढ़ गया है। हाल के दिनों में बच्चे इससे काफी प्रभावित हुए है। इस पर काबू पाने को बड़े स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। सोमवार को जकार्ता में वैक्सीन लेती एक छात्रा। रायटर

पाक में बढ़े मामले, ग्वादर में लाकडाउन

समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार, पाकिस्तान में डेल्टा वैरिएंट के चलते दैनिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में देशभर में 3,752 नए मामले पाए गए। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने महामारी की चौथी लहर के प्रति लोगों को आगाह करते हुए कहा कि गंभीर होने की जरूरत है। इस बीच, ग्वादर में 15 दिन के लिए लाकडाउन लगा दिया गया है। इस तटीय शहर में चीन बंदरगाह विकसित कर रहा है।

चीन में फिर बढ़ रहा कोरोना का खतरा

समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, चीन में कोरोना महामारी का खतरा फिर बढ़ना शुरू हो गया है। पूर्वी चीन के नानजिंग शहर में संक्रमण बढ़ने से यह खतरा बताया जा रहा है। इस शहर में 24 घंटे में 38 मामले पाए गए। यहां अब तक 60 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। नानजिंग में लाकडाउन लगाया गया है और बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है।

भारत, रूस, ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका के विज्ञानी कोविड पर करेंगे साझा शोध

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत, रूस, ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका के विज्ञानी कोविड-19 के खिलाफ दवा विकसित करने या उपलब्ध दवा के उपयोग के लिए एक साथ शोध करेंगे।

एक आधिकारिक बयान में सोमवार को बताया गया कि कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी दवा की तलाश के इस संयुक्त प्रयास में जैवसूचना, कार्बनिक रसायन, चिकित्सा रसायन, औषधि परीक्षण व परजीवी विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों का जुड़ना बेहद अहम होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एक बयान में कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के विज्ञानियों व विशेषज्ञों के प्रयासों, ज्ञान व अनुभव के मेल से ब्रिक्स देशों में स्वास्थ्य प्रणाली व स्वास्थ्य देखभाल दोनों सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंच सकेंगे। इसमें कहा गया, 'भारत, रूस, ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका के विज्ञानी सार्स-सीओवी-2 के आरएनए की प्रतिकृतियों को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम, मुख्य प्रोटीएज (प्रोटीन के विखंडन को प्रेरित करने वाला एंजाइम) व आरएनए प्रतिकृतियों के खिलाफ सीसा धातु के यौगिकों के पुनर्निर्माण, उनके सत्यापन व संश्लेषण के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसा करने से मेजबान कोशिकाओं में संक्रमण के दौरान वायरस की परिपक्वता व प्रसार दोनों को बाधित किया जा सकता है। इससे बेहतर उत्पादन विधियों के साथ नई कोविड-19 दवाओं के उत्पादन में मदद मिल सकती है।' विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कोविड-19 को महामारी घोषित किए जाने के बाद सार्स-सीओवी-2 के बहुस्तरीय प्रसार का पता चला है। इससे निपटने के लिए दुनियाभर में विभिन्न स्तरों पर पहल की जा रही है।

- महामारी से निपटने की दिशा में अहम साबित हो सकती है यह पहल
- कोविड-19 को महामारी घोषित कर चुका है विश्व स्वास्थ्य संगठन

वेटिकन के पूर्व प्रशासक समेत दस लोगों के खिलाफ सुनवाई आज से

वेटिकन सिटी, रायटर : वेटिकन में एक बड़ी वित्तीय धांधली की जांच में वेटिकन के दो नंबर के अधिकारी समेत दस लोगों के खिलाफ मंगलवार को ऐतिहासिक सुनवाई शुरू होगी। वेटिकन की खुफिया जांच में पता चला है कि प्राडा और लुई वुटान की वस्तुएं खरीदने और रियल स्टेट का घाटे वाला सौदा किया गया। यह रकम विद्रोहियों के कब्जे से एक कैथोलिक नन को छुड़वाने के लिए दी जानी थी।

वेटिकन प्रशासन के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी 73 वर्षीय कार्डिनल एंजिलो बेकु के खिलाफ भी वित्तीय अपराध के लिए मुकदमा चलेगा। पोप फ्रांसिस ने बेकू को पिछले साल ही उनके पिछले पद से हटाया था और फिर उनकी इम्यूनिटी भी हटा ली थी। हालांकि बेकू का कहना है कि वह निर्दोष हैं। इसके अलावा, स्विस वकील रेने ब्रूहार्ट के खिलाफ भी सुनवाई होगी जोकि वेटिकन के वित्तीय खुफिया यूनिट की प्रमुख रह चुकी हैं।



13 साल 330 दिन की सबसे कम उम्र में ओलिंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी मोमिजी निशिया। 1936 में बर्लिन ओलिंपिक में 13 साल 268 दिन की उम्र में मार्जोरी गेस्ट्रिंग ने महिलाओं की तीन मीटर स्प्रिंगबोर्ड डाइव स्पर्धा का स्वर्ण जीता था

« निशानेबाज अब्दुल्ला अल रशीदी • रायटर

13 साल की स्कूल गर्ल ने स्केट बोर्डिंग में जीता स्वर्ण पदक तो 58 साल के निशानेबाज ने जीता कांस्य पदक

ना उम्र की सीमा हो, ना पदक का हो बंधन...

टोक्यो, एपी : उम्र को लेकर हमेशा बहस होती रहती है लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहस को दरकिनार करने के लिए ही पैदा होते हैं। उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर हैं। टोक्यो ओलिंपिक में सोमवार को कुछ ऐसा ही हुआ। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों या वीडियो गेम से खेलते हैं, उस उम्र में ओलिंपिक में पहली बार खेली जा रही स्केट बोर्डिंग स्पर्धा में महज 13 साल की बेटियों ने हैरतंगेज करतब दिखाकर स्वर्ण और रजत पदक पर अपना कब्जा जमाया। इसके ठीक विपरीत जिस उम्र (58 साल) में लोग संन्यास लेकर अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद लेने की सोच रहे होते हैं, उस पड़ाव पर कुवैत के अब्दुल्ला अल रशीदी ने सटीक निशाना लगाते हुए कांस्य पदक जीतकर सभी को चौंका दिया।

स्केट बोर्डिंग की बात करें तो 13 साल 330 दिन कि उम्र में जापान की मोमिजी निशिया ने 15.26 के स्कोर के साथ पहला ओलिंपिक खेलते हुए पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनके अंतिम तीन प्रयास (4.15, 4.66, और 3.43) पोडियम पर शीर्ष स्थान को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त थे, क्योंकि उन्होंने ब्राजील की रेसा लील (13 साल 203 दिन) और 16 वर्षीय फुना नाकायामा को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। रेसा लील, जो



स्केट बोर्डिंग में रजत पदक जीतने वाली रेसा लील, स्वर्ण पदक विजेता मोमिजी और कांस्य पदक विजेता नकायामा • एएफपी

न केवल ब्राजील की सबसे कम उम्र की पदक विजेता हैं, बल्कि एक ओलिंपियन भी हैं, उन्होंने 14.64 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता और नाकायामा ने 14.49 के स्कोर साथ कांस्य पदक जीता। हालांकि यह दिन मोमीजी निशिया का था, जिनका नाम ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला स्केट बोर्डर के रूप में दर्ज किया गया है। वहीं, जापान के लिए इस खेल में पुरुषों की प्रतियोगिता में विजेता यूटो होरिगोम रहे। दूसरी तरफ 58 वर्षीय कुवैत के अब्दुल्ला अल रशीदी ने ओलिंपिक स्कीट निशानेबाजी के 60 में से 46 शाट लक्ष्य में मारकर कांस्य पदक जीता और दुनिया को दिखा दिया कि उनके लिए उम्र महज एक आंकड़ा है। पदक जीतने के बाद उन्होंने 2024 में स्वर्ण पर निशाना लगाने का भी वादा किया जब वह 60 पार हो चुके होंगे। रशीदी ने कहा, 'मैं 58 वर्ष का सबसे बुजुर्ग निशानेबाज हूं। यह कांस्य मेरे लिए सोने से कम नहीं। मैं इस पदक से बहुत खुश हूं लेकिन उम्मीद है कि अगले ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतूंगा।' अल रशीदी ने पहली बार 1996 अटलांटा ओलिंपिक में भाग लिया था। उन्होंने रियो ओलिंपिक में भी कांस्य जीता था लेकिन उस समय स्वतंत्र खिलाड़ी के तौर पर उतरे थे क्योंकि कुवैत पर अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति ने प्रतिबंध लगा रखा था। अल रशीदी ने कहा, 'रियो में पदक से खुश था लेकिन कुवैत का ध्वज नहीं होने से दुखी था। यहां मैं खुश हूं क्योंकि मेरे मुल्क का झंडा यहां है।'

एक जीता, बाकी हारे

स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने जब शनिवार को टोक्यो ओलिंपिक में रजत पदक जीता था तो लगने लगा था कि खेलों के महाकुंभ में सबसे बड़ा 127 भारतीय खिलाड़ियों का दल पदकों की झड़ी लगा देगा। लेकिन चानू के जीतने के बाद पदक तो दूर भारतीय खिलाड़ी लगातार हार के साथ टोक्यो ओलिंपिक से बाहर होते जा रहे हैं। सोमवार को अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल ही जीतकर इस टूर्नामेंट से खुद को बाहर होने से बचा पाए हैं। जबकि पदक की दावेदार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, तलवारबाज भवानी देवी, मुक्केबाज आशीष कुमार, निशानेबाज अंगद व मैराज, तीरंदाजी पुरुष टीम और टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल देशवासियों को निराश करके ओलिंपिक से बाहर हो गए।

शरत तीसरे दौर में, मनिका सुतिर्था का सफर समाप्त



शरत कमल • ट्विटर

टोक्यो, प्रेट्र : अपना चौथा ओलिंपिक खेल रहे अचंता शरत कमल ने शुरू में पिछड़ने के बाद अच्छी वापसी करते हुए टोक्यो ओलिंपिक खेलों की टेबल टेनिस प्रतियोगिता में सोमवार को यहां पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में प्रवेश किया लेकिन, महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा और सुतिर्था मुखर्जी सीधे गेम में हारकर बाहर हो गईं।

शरत कमल ने 49 मिनट तक चले मैच में पुर्तगाल के 20वीं वरीयता प्राप्त टियागो अपोलोनिया पर 4-2 (2-11, 11-8, 11-5, 9-11, 11-6, 11-9) से जीत दर्ज की। टेबल टेनिस में भारत की उम्मीदें अब शरत कमल पर टिकी हैं लेकिन, उन्हें मंगलवार को तीसरे दौर में चीन के मौजूदा चैंपियन मा लांग की कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। तीसरे दौर में आस्ट्रिया की सोफिया पोलकानोवा के नियंत्रित और दमदार खेल का मनिका के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने केवल 22 मिनट में 0-4 (8-11, 2-11, 5-11, 7-11) से यह मैच गंवाया। महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में सुतिर्था पुर्तगाल की फू यू से 0-4 (3-11, 3-11, 5-11, 5-11) से हार गईं।

शरत कमल की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टियागो ने पहले गेम में लगातार नौ अंक बनाकर उसे आसानी से अपने नाम किया। शरत ने हालांकि दूसरे गेम में 5-0 की बढ़त बनाकर अपना आत्मविश्वास जगाया। तीसरे गेम में भी शरत ने 5-0 की बढ़त से शुरुआत की और आसानी से यह गेम अपने नाम करके मैच में 2-1 से आगे हो गए। शरत चौथे गेम में भी एक समय आगे थे लेकिन, टियागो ने पहले स्कोर 7-7 से बराबर किया और फिर यह गेम जीतकर मैच को बराबरी पर ला दिया। भारतीय खिलाड़ी की शुरुआती बढ़त के बाद पांचवें गेम में स्कोर एक समय 4-4 से बराबर था। शरत इसके बाद टेबल के अधिक करीब आकर खेलने लगे। इसका उन्हें फायदा मिला। छठे गेम में काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिला और स्कोर 9-9 से बराबर हो गया। शरत ने हालांकि आक्रामकता दिखाई और लगातार दो अंक लेकर मैच अपने नाम किया।

दुनिया के नंबर-दो खिलाड़ी मेदवेदेव से हारे नागल

टोक्यो : भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में रूस ओलिंपिक समिति (आरओसी) के दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव के खिलाफ सीधे सेटों में हारकर बाहर हो गए। दुनिया के 160वें नंबर के खिलाड़ी नागल एक घंटा छह मिनट चले मुकाबले में 2-6, 1-6 से हारे। सुमित नागल पूरे मैच में सिर्फ तीन गेम ही जीत पाए। विश्वस्तरीय खिलाड़ी मेदवेदेव और एटीपी टूर की प्रतियोगिताओं में नियमित रूप से खेलने के लिए जूझ रहे नागल के बीच का अंतर स्पष्ट नजर आ रहा था। नागल ने कड़ा प्रयास किया लेकिन, आस्ट्रेलियन ओपन के उप विजेता को जीत दर्ज करने में कोई परेशानी नहीं हुई।

भारतीय खिलाड़ी नागल ने 2019 यूएस ओपन के दौरान ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में पदार्पण करते हुए स्विट्जरलैंड के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर के खिलाफ एक सेट जीतकर सुर्खियां बटोरी थी। नागल की शुरुआत भी खराब रही और अंत उससे ज्यादा खराब रहा।

22 मिनट में ही मनिका बत्रा को आस्ट्रिया की सोफिया से हार का सामना करना पड़ा

आशीष को भी मिली शिकस्त

टोक्यो, प्रेट्र : ओलिंपिक में पदार्पण करने वाले मुक्केबाज आशीष चौधरी (75 किग्रा) को चीन के एरबीके तुओहेता के खिलाफ पहले दौर के मुकाबले में लचर शुरुआत का खामियाजा भुगतना पड़ा और हार के साथ ही उनका सफर खत्म हो गया। एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले 27 साल के इस खिलाड़ी ने शुरुआती दौर के बाद लय पकड़ी लेकिन, यह उन्हें 0-5 की हार से बचने के लिए काफी नहीं था। हिमाचल प्रदेश के इस मुक्केबाज को चीन के खिलाड़ी ने पहले दौर में ही पछाड़ दिया। आशीष ने दूसरे दौर में वापसी की कोशिश में अधिक हमले किए। बायीं आंख के नीचे चोट के बावजूद वह तीसरे दौर में ताओहेता को परेशान करने में सफल रहे। आशीष ओलिंपिक से बाहर होने वाले तीसरे भारतीय मुक्केबाज हैं।

भवानी देवी दमदार शुरुआत के बाद दूसरा मुकाबला हारीं

टोक्यो, प्रेट्र : भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने अपने ओलिंपिक पदार्पण पर आत्मविश्वास भरी शुरुआत करके आसानी से पहला मैच जीता लेकिन, सोमवार को यहां दूसरे मैच में चौथी वरीयता प्राप्त मैनन ब्रूनेट से हारकर वह टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। भवानी देवी को महिलाओं की व्यक्तिगत साबरे के दूसरे मैच में रियो ओलिंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली ब्रूनेट से 7-15 से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने इससे पहले ट्यूनीशिया की नादिया बेन अजीजी को 15-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था।

सात्विक और चिराग की जोड़ी दूसरे मैच में हारी: सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय बैडमिंटन जोड़ी को पुरुष डबल्स के ग्रुप-ए के अपने दूसरे मैच में मार्कस फर्नाल्डी गिडियोन और केविन संजय सुकामुल्जो की इंडोनेशिया की दुनिया की नंबर एक जोड़ी के खिलाफ सीधे गेम में शिकस्त का सामना करना पड़ा। दुनिया की 10वें नंबर की सात्विक और चिराग की भारतीय जोड़ी को इंडोनेशिया की शीर्ष वरीय जोड़ी ने 32 मिनट में 21-13, 21-12 से शिकस्त दी। गिडियोन और सुकामुल्जो के खिलाफ नौ मैचों में सात्विक और चिराग की यह नौवीं हार है। गिडियोन और सुकामुल्जो दो जीत के साथ ग्रुप में शीर्ष पर चल रहे हैं जबकि सात्विक और चिराग दूसरे स्थान पर हैं। इन्हें ग्रुप-ए के अंतिम मैच में बेन और सीन वेंडी की जोड़ी से भिड़ना है।



भवानी देवी » • ट्विटर



मनिका बत्रा » • प्रेट्र

सुमित नागल » • एएफपी

साजन प्रकाश • रायटर



आशीष चौधरी » • एपी



पुरुष तीरंदाजी टीम • प्रेट्र

पदक तालिका

देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
जापान	8	2	3	13
अमेरिका	7	3	4	14
चीन	6	5	7	18
आरओसी	4	5	3	12
ग्रेट ब्रिटेन	3	3	1	7
द. कोरिया	3	0	4	7
आस्ट्रेलिया	2	1	3	6
कोसोवो	2	0	0	2
इटली	1	4	4	9
फ्रांस	1	2	2	5
भारत	0	1	0	1

नोट : भारत तालिका में 33वें स्थान पर है।

निशानेबाजी में निराशा अंगद और मैराज बाहर

टोक्यो : भारतीय निशानेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन स्कीट स्पर्धा में भी जारी रहा। अंगद वीर सिंह बाजवा और मैराज अहमद खान क्रमशः 18वें और 25वें स्थान पर रहकर फाइनल में जगह नहीं बना पाए। अंगद ने संभावित 125 में से 120 जबकि मैराज ने 117 अंक बनाए। स्कीट में चोटी के छह स्थान पर रहने वाले निशानेबाज ही फाइनल में जगह बनाते हैं। भारत के 10 मीटर एयर पिस्टल और राइफल निशानेबाजों को भी प्रतिस्पर्धा के पहले दो दिन नाकामी हाथ लगी थी।

कोरियाई टीम से हारी भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम

टोक्यो : अतानु दास, प्रवीण जाधव और तरुणदीप राय की भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम यहां टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में खिताब के प्रबल दावेदार दक्षिण कोरिया से हारकर इस ओलिंपिक से बाहर हो गई। भारतीय तिकड़ी ने कजाखस्तान को 6-2 से हराकर अच्छी शुरुआत की थी लेकिन, क्वार्टर फाइनल में उनका सामना नंबर एक कोरिया से था जिससे उसे 0-6 से हराया। इससे पहले मिक्स्ड डबल्स में दीपिका और जाधव की जोड़ी भी हारकर क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई थी।

साजन प्रकाश 24वें स्थान पर रहे

टोक्यो : साजन प्रकाश यहां हीट दो में चौथे स्थान पर रहते हुए पुरुष 200 मीटर बटरफ्लाई के सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे। पिछले महीने इटली में एक मिनट 56.38 सेकेंड के समय के साथ निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ओलिंपिक का ए क्वालीफाइंग स्तर हासिल करने वाले साजन एक मिनट 57.22 सेकेंड के समय के साथ 38 तैराकों के बीच 24वें स्थान पर रहे। शीर्ष 16 तैराकों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। साजन गुरुवार को 100 मीटर बटरफ्लाई में चुनौती पेश करेंगे। माना पटेल और श्रीहरि नटराज पहले ही प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं।

भारत के आज के मैच

पदक के मुकाबले

निशानेबाजी : 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम, क्वालीफिकेशन, सुबह 5:30 बजे, फाइनल : सुबह 8:07 बजे

- खिलाड़ी : मनु भाकर और सौरभ चौधरी, यशस्विनी सिंह देसवाल और अभिषेक वर्मा
- 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम क्वालीफिकेशन स्टेज-1, सुबह 9:45 बजे, फाइनल : दोपहर 12:22 बजे
- खिलाड़ी : इलावनिल वलारिवान और दिव्यांश सिंह पंवार, अंजुम मौदगिल और दीपक कुमार

अन्य

टेबल टेनिस : पुरुष सिंगल्स, तीसरा दौर, सुबह 8:30 बजे

- खिलाड़ी : अचंता शरत कमल

नौकायन : पुरुष, फुजीसावा, सुबह 8:45 बजे

- खिलाड़ी : विष्णु सरवनन
- इनोशिमा, दोपहर 14:50 बजे
- खिलाड़ी : गणपति केलापंडा चेंगप्पा, वरुण ठक्कर
- महिला, लेजर रेडिल, सुबह 8:35 बजे, खिलाड़ी : नेत्रा कुमानन

बैडमिंटन : पुरुष डबल्स-सुबह 8:30 बजे

- खिलाड़ी : सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी/चिराग शेट्टी

मुक्केबाजी : महिला, अंतिम-16, सुबह 10:57 बजे

- खिलाड़ी : लवलीना बोरगेहन

हाकी : पुरुष टीम, पूल-ए, सुबह 6:30 बजे

प्रसारण : सोनी नेटवर्क पर

खल रही सुनील और आकाशदीप की कमी



धनराज पिल्लै

टॉर्नेडो

टोक्यो ओलिंपिक में खेलों की दुनिया का ये बेहद उतार-चढ़ाव वाला हफ्ता रहा। सबसे पहले तो भारोत्तोलन में देश को पदक दिलाने के लिए मीराबाई चानू को बहुत बधाई। भारतीय खेलों में उनका ये रजत पदक मील का पत्थर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ऐतिहासिक पदक जीतने का उनका सफर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का काम करेगा।

अब हाकी की बात करते हैं। रविवार का दिन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि देशभर के हाकी प्रेमियों के लिए बेहद निराशाजनक रहा। आस्ट्रेलिया के हाथों मिली 7-1 की करारी शिकस्त को पचाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमें एक ऐसी टीम के हाथों खेल के हर विभाग में मात मिली, जो कौशल, रणनीति और मानसिक तौर पर हमसे काफी मजबूत साबित हुई। मुझे लगता है कि टीम को फ्रंटलाइन पर एसवी सुनील और आकाशदीप जैसे सीनियर खिलाड़ियों की सेवाओं की कमी खली। टीम का ऐलान करते वक्त हाकी इंडिया को इनके नाम पर विचार करना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि अपनी प्रतिभा के अलावा वो टीम में अनुभव भी लेकर आते हैं। इससे दबाव के पलों में भारतीय टीम को काफी फायदा मिलता। उदाहरण के लिए आस्ट्रेलियाई कप्तान एडी ओकेनडेन को देखिए, जो अपने अनुभव का इस्तेमाल सिर्फ मिडफील्ड में ही नहीं करते बल्कि फारवर्ड लाइन में अपनी क्षमता दिखाते हैं। आस्ट्रेलियन थिंकटैंक ने उनके अनुभव, कौशल और परिपक्वता का अच्छा इस्तेमाल किया। आस्ट्रेलिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में वो कभी भी अपनी रणनीति से पीछे नहीं हटते हैं। वो अपने तुरुप के इक्कों का सावधानी से इस्तेमाल करते हैं और अहम मौकों पर उन्हें मैच में झोंकते हैं। ये वो रणनीति है जो भारतीय टीम में नजर नहीं आई।

भारतीय टीम अपने तीसरे मुकाबले में स्पेन का सामना करेगी। उम्मीद है कि मनप्रीत सिंह और उनकी टीम पिछली हार को भुलाते हुए एकजुट प्रदर्शन करेगी। मेरा संदेश यही है, गलतियों से सबक सीखो और नतीजे की परवाह मत करो। (टीसीएम)

फिर हारी भारतीय महिला हाकी टीम

टोक्यो, प्रेट्र: भारतीय महिला हाकी टीम को टोक्यो ओलिंपिक में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा और सोमवार को पूल-ए के मैच में रियो ओलिंपिक की कांस्य पदक विजेता जर्मनी ने उसे 2-0 से मात दी। पहले मैच में दुनिया की नंबर एक टीम नीदरलैंड्स के हाथों 1-5 से हारने के बाद भारतीयों ने कुछ बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन, दुनिया की तीसरे नंबर की टीम को हराने के लिए यह काफी नहीं था। भारत की गुरजीत कौर ने तीसरे क्वार्टर में पेनाल्टी स्ट्रोक पर गोल करने का मौका भी गंवाया। जर्मनी के लिए कप्तान निकी लौरेंज ने 12वें और अन्ना श्रोडेर ने 35वें मिनट में गोल किए। भारत का सामना बुधवार को ब्रिटेन से होगा।

अब सिर्फ मां के पास रहना चाहती हूं : मीराबाई चानू

साक्षात्कार देश को ओलिंपिक की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू का मानना है कि अब वह पदक लेकर सीधे अपने घर मां के पास जाना चाहती हैं। टोक्यो से भारत वापसी पर **मीराबाई** से **शुभम पांडेय** ने खास बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश :

- **भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने के साथ कैसा महसूस हो रहा है?**

-मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। ओलंपिक में पदक जीतना ही बाकी रह गया था। मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है।

- **2016 रियो ओलंपिक में आप भार तक नहीं उठा सकी थी और आज आपके हाथ में रजत पदक है। इसे कैसे देखती हैं?**

-मैंने रियो में काफी कोशिश की थी लेकिन तब मेरा दिन नहीं था। मैंने उस समय तय किया था कि मुझे टोक्यो में खुद को साबित करना होगा। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग और तकनीक सब बदल दी।

- **आपका स्नैच कमजोर माना जाता रहा है लेकिन उसमें भी शानदार प्रदर्शन किया। क्लीन एंड जर्क के साथ स्वर्ण जीत सकती थी। क्या लगता है, एक मौका चूक गईं?**

-स्नैच में मैंने पूरी कोशिश करते हुए तकनीक के साथ वजन उठाने का प्रयास किया था। लेकिन 87 किग्रा ही स्नैच में उठा सकी। क्लीन एंड जर्क में 117 किग्रा का भार स्वर्ण पदक के लिए उठाना था मगर शारीरिक कमजोरी के चलते इस ओलिंपिक रिकार्ड वजन को नहीं उठा सकी। फिर भी मुझे 115 किग्रा के साथ रजत पदक जीत कर बहुत खुशी है व यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

- **अब आगे का क्या प्लान है?**

-पिछले पांच सालों से मैं केवल पांच दिन के लिए ही घर जा पाई थी। अब मैं पदक के साथ घर जाऊंगी। अपनी मां और परिवार के साथ समय बिताना चाहूंगी। बाकी कुछ नहीं सोचा है।

दैनिक जागरण
सप्तरंग
अंतस और अध्यात्म का
मंगलवार, 27 जुलाई, 2021

शांति और संतुलन के उत्सव

कजली तृतीया, स्वर्ण गौरी पूजा, कामिका एकादशी, दूर्वा गणपति, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, श्रावणी, ऋषि तर्पण आदि पर्वों को अपने में समेटे श्रावण मास उत्सव का मास बन जाता है। यह ध्यान देने की बात है कि ये सभी उत्सव उन्माद या उल्लास के कोलाहल से परे शांति और संतुलन के पर्व हैं। इन उत्सवों का जप, तप, योग, ध्यान और शांति स्थापना में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। भगवान शिव प्रेम और शांति के अथाह सागर भी हैं। उनके इस पावन मास में सभी प्राणी अपने स्वाभाविक वैर भाव को भुलाकर संसार के अन्य सभी जीवों के साथ पूर्ण शांतिमय जीवन जी सकते हैं। शिव आनंदस्वरूप हैं और जो भी उनसे जुड़ता है, वह भी आनंद रूप हो जाता है।



आदि छंद का पावन मास

समुद्र मंथन से निकले कालकूट विष से प्राणियों को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में उतार लिया था। आज कोरोना के समय में शिव जैसी कल्याण की भावना हम सबमें होनी चाहिए। शिव के प्रिय महीने सावन में उनकी उपासना, अभिषेक के साथ उनके गुणों को भी अपने भीतर आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए...



श्रावण विशेष

नीरजा माधव
सांस्कृतिक विषयों की अध्येता

श्रावण मास शुरू होने के साथ भारत का उत्सवधर्मी रूप थोड़ा और संवर गया। बेशक कोरोना की वजह से पिछले वर्ष की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं है, लेकिन इन दिनों भोले शिव के भक्तों के रोम-रोम से 'बोल-बम' की ध्वनि निकलती प्रतीत हो रही है। वातावरण शिवमय हो गया है। सावन की रसवंती फुहार में भीगते तन और तन से अधिक मन को देखकर सहज ही अनुमान हो जाता है कि भस्मी श्रृंगार वाले भूत भावन आदि योगी शिव का प्रिय मास सावन आ गया। वातावरण में रुद्राभिषेक के मंत्रों की गूंज तो कहीं जगज्जननी के विराट ऐश्वर्य के साथ सजी फक्कड़ भोले बाबा की झांकी। हर-हर बम-बम की फक्कड़ता ऐसी कि बड़ी से बड़ी सिद्धियां और विभूतियां उसके सम्मुख नतमस्तक हो जाएं। शिवलिंग पर चढ़े बिल्वपत्र और मंदार पुष्प पर तमाम ऐश्वर्य न्योछावर। यह सब होता है शिव के प्रिय मास श्रावण में।

भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय है। क्यों? शिव तो साक्षात विश्व-विग्रह हैं। काल शिव के अधीन है। शिव काल से मुक्त चिदानंद हैं- शिवस्य तु वशे कालो, न कार्य वंशे शिवः। भूः, भुवः और स्वः अर्थात भूमि, अंतरिक्ष और द्युलोक में सर्वत्र शिव ही व्याप्त हैं। 'शेते तिष्ठति सर्वं जगत् यस्मिन् सः शिवः शंभुः विकाररहितः' यानी जिसमें सारा जगत शयन करता हो, जो विकार रहित है, वह शिव है। जो अमंगल का नाश करते हैं, वही सुखमय मंगलमय भगवान शिव हैं। आशुतोष शिव त्रिविध तापों का शमन करने वाले हैं और इन्हीं से समस्त विद्याएं और कलाएं उद्भूत हैं। सारा विश्व शिव से उत्पन्न है, शिव में स्थित है और शिव में ही विलीन होता है।

शिव के इस गूढ़ और सूक्ष्म दार्शनिक, आध्यात्मिक पक्ष से हटकर हम यदि उनके सगुण रूप पर विचार करते हैं तो कुछ तथ्य सामने आते हैं कि क्यों सावन का महीना शिव के साथ अभिन्न हो गया। एक प्रचलित आख्यान मिलता है कि देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन में विषैला कालकूट विष भी निकला था, जिसकी ज्वाला से सृष्टि को खतरा उत्पन्न हो गया था। सभी प्राणियों के अस्तित्व पर संकट आ गया था। शस्य श्यामला धरती की उर्वरता नष्ट होने के कगार पर थी। कालकूट की ज्वाला से विश्व के प्राणी झुलसने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए देव, दानव सभी चिंतित हो उठे। उन्होंने भगवान शिव से सृष्टि रक्षा के लिए गुहार की। शिव ने एक ही आचमन में लोकसंहारी विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीले रंग का हो गया और वह नीलकंठ बन देवों के देव महादेव बन गए। पुराण कहते हैं कि वह समय सावन का था। उस समय शिव के ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने उनका जलाभिषेक किया था और तब से सावन मास में शिवालयों में जलाभिषेक के द्वारा शिव के उस लोकमंगलकारी रूप का स्मरण आज भी उनके भक्त करते हैं। वे शिव की कृपा की वर्षा में भीगना चाहते हैं।

इसका दूसरा पक्ष यह भी लिया जा सकता है कि सृष्टि में प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से सृष्टि के सुरक्षित रह पाने में संशय होना स्वाभाविक ही है। समुद्र जीवों के लिए एक बड़ा प्राकृतिक संसाधन है और उस संसाधन का देव, दानव दोनों प्रवृत्तियों के लोगों द्वारा दोहन धरती की उर्वरा शक्ति को नष्ट करने के साथ-साथ प्राणी मात्र के अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। शिव उस विष को अपने कंठ में धारण कर सभी को सावधान रहने का संदेश देते हैं।

सावन शिव के मंगलकारी स्वरूप के साथ जुड़ता है। सावन में मेघ इच्छाचारी होते हैं। वे बिना कोई भेदभाव किए कहीं भी बरस सकते हैं। धरती को शस्य श्यामला कर सकते हैं। लोगों की प्यास बुझा सकते हैं। शिव की कृपा भी सावन के मेघ की तरह ही सृष्टि के प्राणियों पर बरसती है।

सावन की एक और कथा इसे शिव के साथ जोड़ती है। सनतकुमारों के प्रसंग से ज्ञात होता है कि भगवती पार्वती ने अपनी सुदीर्घ तपस्या के पश्चात इसी वर्षा ऋतु में शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। सनातन धर्म में तप का सौंदर्य सर्वोच्च सौंदर्य माना जाता है। भगवती पार्वती का भी नैसर्गिक सौंदर्य जब तप की आंच में निखरता है, तब वह अपने प्रिय आशुतोष शिव को पति रूप में प्राप्त करती हैं। इसलिए भी जप-तप और योग की ऋतु है वर्षा। एक कथा यह भी मिलती है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के लिए जगत के पालनकर्ता श्रीहरि विष्णु योग निद्रा में होते हैं, इसलिए संहार के साथ-साथ जगत के पालन का भी संपूर्ण दायित्व शिव को संभालना पड़ता है।

ऋतुओं से समृद्ध भारत में सावन से शिव का नाता वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझा जा सकता है। प्रकृति में मुख्य रूप से जलवायु के दो स्वभाव हैं- एक ठंडा, दूसरा गरम। इन दोनों स्वभावों के अंतर्गत ही विभिन्न ऋतुएं या मास आते हैं। शिव आदियोगी हैं। योग का अर्थ होता है दो पदार्थों को जोड़ना या संयोग। भारत में सावन एक ऐसा महीना है, जिसके पहले प्रकृति का स्वभाव गरम रहता है और बाद में ठंडा मौसम आने वाला होता है यानी धरती पर ठंडे और गरम जैसे प्राकृतिक स्वरूपों को जोड़ने वाला महीना सावन और उस योग के समय की प्रियता को धारण करने वाले आदियोगी शिव। सावन योग का महीना बन जाता है और इस प्रकार आदियोगी शिव से भी रूप से जुड़ने का एक पवित्र महीना हो जाता है।

निर्झरिणी



अपने भगवान के निकट वही पहुंच पाता है, जो मांगने नहीं, बल्कि दिए हुए का धन्यवाद देने जाता है।

– आदि गुरु शंकराचार्य

धर्म और मानव कल्याण के प्रहरी



प्रकाश पर्व पर

डा. सत्येन्द्र पाल सिंह
सिख पंथ के अध्येता



धर्म के मार्ग पर चलना तीखी धार पर चलने जैसा है। इसके लिए समर्पण और दृढ़ता चाहिये, साथ ही भावनाओं का औदार्य भी। गुरु श्री हरिकिशन जी का जीवन और उनके कार्य इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।

वर्ष 1661 में गुरुगद्दी पर आसीन होने वाले गुरु हरिकिशन जी सिखों के आठवें गुरु थे। उस समय उनकी आयु मात्र पांच वर्ष की थी। दिल्ली के तख्त पर बैठा मुगल बादशाह औरंगजेब उस समय निरंतर कट्टर व धर्मांध नीतियों के कार्यान्वयन की ओर अग्रसर था, जबकि हरिकिशन जी के पहले सातवें गुरु हरिराय जी पूर्व में ही औरंगजेब से किसी भी तरह का संपर्क न रखने की नीति बना चुके थे और गुरु हरिकिशन जी इस नीति के पालन के लिए पूर्णतया कटिबद्ध थे।

गुरु हरिकिशन जी सिखों को गुरुवाणी के माध्यम से सिख धर्म के आदर्शों से जोड़ने में लग गये। उन्होंने मानवता को धर्म में सबसे आगे रखा। उन्होंने श्रीगुरु ग्रंथ साहिब की अनेक हस्तलिखित प्रतियां तैयार करा कर दूरस्थ सिख संगतों को भिजवाईं।

गुरु हरिकिशन जी की सेवाभावना भी अप्रतिम थी। एक बार गुरु साहिब कीरतपुर के निकट एक गांव में धर्म और मानवता के प्रसार के लिए गए तो वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दूर खड़ा है। लोगों ने बताया कि उस व्यक्ति को कोढ़ है, जिसके कारण वह पास नहीं आ रहा है। यह बात सुनकर गुरु साहिब स्वयं ही उसके पास गये और उसे गले से लगा लिया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा - तुम्हारे शरीर में भले ही बीमारी हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा बहुत सुंदर है, क्योंकि उसमें ईश्वर के लिए भावना है।

औरंगजेब ने गुरु साहिब को दिल्ली बुलवाने के लिए अपने प्रमुख दरबारी राजा जय सिंह को आगे किया। गुरु हरिकिशन साहिब ने राजा जय सिंह का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। बाद में दिल्ली की सिख संगत के आमंत्रण पर वर्ष 1664 में दिल्ली आए। यहां राजा जय सिंह के आग्रह पर उनका आतिथ्य स्वीकार कर उनके महल में रुके। वहां औरंगजेब ने उनसे मिलने के अनेक प्रयास किए, किंतु गुरु साहिब इन्कार करते रहे। यह औरंगजेब की क्रूरता को करारा उत्तर था।

उसी दौरान दिल्ली में महामारी फैल गई। मुगल शासन मूकदर्शक बना हुआ था। गुरु हरिकिशन जी से लोगों का दुख देखा न गया। वह रोगियों की सेवा व उपचार में लग गये। उनके सद्प्रयासों से लोग स्वस्थ होने लगे और गुरु साहिब का यश चतुर्दिक फैलने लगा, लेकिन वे स्वयं अस्वस्थ होकर परमात्मा में लीन हो गये। उनका गुरु काल ढाई साल से भी कम था, किंतु वह धर्म की प्रतिष्ठा और मानव कल्याण का स्वर्ण काल था।

प्रेरक प्रसंग

भलाई में नहीं होता प्रतिदान

एक युवती की आंखें एक दुर्घटना में चली गई थीं। उसे अपनी जिंदगी नीरस लगने लगी। अपने जीवन से गिले-शिकवों के बीच ही उसे एक युवक मिला। वह युवती का बड़ा खयाल रखता। उस युवक के जिंदगी में आने से युवती के अंदर जीने की इच्छा पैदा हुई। उसे युवक की बातें बहुत अच्छी लगतीं। उसने युवक से शादी करने की इच्छा जताई। युवक ने लड़की से कहा- मैं तुम्हारी आंखों की रौशनी वापस लाने की कोशिश करूंगा। तुम फिर से दुनिया को देख सकोगी। उसने युवती की आंखों का आपरेशन बड़े अस्पताल में करवाया। जिस दिन उसकी आंखों की पट्टी खुली, उसने सबसे पहले युवक को देखा। युवती यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि जिस युवक को बिना देखे वह प्रेम कर रही थी, उसकी आंखें नहीं थीं। उसके शादी के सारे सपने धरे रह गए। उसने कहा- मैं स्वयं नेत्रहीन होने का दर्द सह चुकी हूं, इसलिए एक नेत्रहीन से शादी नहीं कर सकती। युवक इस बात पर मुस्कुराया और कहा- अब तुम दुनिया को देख सकती हो, उसे भरपूर जी सकती हो। मेरा उद्देश्य पूरा हुआ, मैं चलता हूं। मेरी आंखों का खयाल रखना।

कथा-मर्म : निःस्वार्थ भाव से भलाई करने वाला कभी यह नहीं सोचता कि उसे बदले में क्या मिलेगा।

योग है जीवन-रक्षक

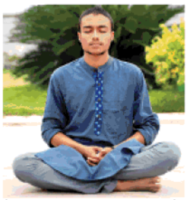


योग-ध्यान

सद्गुरु
ईशा फाउंडेशन के प्रणेता

मैं अनेक विज्ञानियों और दुनिया के कई प्रमुख चिकित्सकों से बात करता रहा हूं। जितना मुझे समझ में आया, जो सामान्य समझ भी है कि इस महामारी के इस साल या अगले साल खत्म होने की अधिक उम्मीद नहीं है। यह चार-छह साल तक चल सकती है, जिसके बाद यह महामारी मात्र एक संक्रामक रोग बनकर रह जाएगी। वह भी तब संभव है, जब हम बहुत प्रभावी उपचार ला पाएं। तब तक यह महामारी बार-बार लहरों के रूप में लौट कर आती रहेगी।

पहली लहर से लेकर दूसरी लहर तक आते हुए वायरस ज्यादा नुकसानदायक हो गया। अब संभावित तीसरी लहर को और भी नुकसानदायक बताया जा रहा है। यह वायरस इंसानों को नुकसान पहुंचाने में कई गुना ज्यादा असरदार हो गया है। यह वायरस खुद को और बेहतर कर सकता है, इसलिए हमें भी खुद को और बेहतर बनाना होगा। पहली चिंता रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की है। इसके लिए योग काफी कारगर है। लोग कहते हैं कि इसे हमारे शरीर से गुजरना ही है। इसलिए यह बीमारी हमारे शरीर से बिना लक्षणों के गुजरे, इसके लिए हमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि हर कोई योग क्रियाओं की अहमियत को समझे। लोग सोच सकते हैं कि योग क्रियाएं उनका आध्यात्मिक विकास करेंगी, उनके पीठ दर्द या सिर दर्द में आराम पहुंचाएंगी, रोजमर्रा के जीवन में उनकी क्षमता को बेहतर करेंगी और कई और दूसरी चीजें करेंगी। लेकिन आपने कभी उन्हें जीवन-रक्षक साधन के तौर पर नहीं देखा होगा, पर वे बिलकुल ऐसी हो सकती हैं। अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, तो आपका शरीर वायरस के असर को निश्चित रूप से दूसरे लोगों के मुकाबले बेहतर तरीके से झेल सकता है।



हर किसी को रोजाना कम से कम डेढ़-दो घंटे का समय कुछ अभ्यासों में बिताना चाहिए, जैसे सूर्य क्रिया, शक्ति चलन क्रिया और शांभवी या अगर कुछ और नहीं तो कम से कम सिंह क्रिया, साष्टांग और मकरासन।

ध्यान से दूर करें चिंता



दृष्टिकोण

संत राजिन्दर सिंह
आध्यात्मिक गुरु

चिंता तनाव के कारणों में से प्रमुख है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। चिंता करने से हम अपने जीवन की आयु को कम कर रहे हैं। लगातार चिंता रहने से शरीर में कई लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तनाव हमारे शरीर में उन हार्मोंस को उत्पन्न करता है, जो खतरे से बचने के लिए बनाए गए थे। खतरे की स्थिति में या तो हम भागते हैं अथवा सामना करते हैं। ये हार्मोंस हमारी बाहों और टांगों की ताकत को लड़ने या दौड़ने के लिए मजबूत करते हैं, किंतु जब हम भागने अथवा लड़ने की आवश्यकता न होने के बावजूद भी तनाव महसूस करते हैं, तो ये हार्मोंस हमारे शरीर में उल्टा असर करते हैं। हमें कमजोरी महसूस होती है।



चिंता करने वाले एक तिहाई से ज्यादा लोग उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं, जो कभी होती ही नहीं। दूसरे एक तिहाई लोग उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं, जो भूतकाल में हुई होती हैं और जिन्हें बदला नहीं जा सकता। बचे हुए एक तिहाई लोग उन चीजों की चिंता करते हैं जो कि अन्य व्यक्तियों से जुड़ी होती हैं और जिनसे उनका कोई सीधा संबंध नहीं होता। इस प्रकार की चिंताओं से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है?

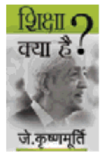
चिंता से मुक्त कैसे हों : चिंता होने पर हम यह विचार कर सकते हैं कि क्या यह सही है कि हम जीवन के बहुमूल्य समय को उन चीजों के विचारों में लगा रहे हैं, जो शायद होगी या नहीं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। अगर वास्तव में कोई समस्या है, तब भी चिंता करने की जगह हमें उस समस्या के समाधान के लिए निश्चित योजनाएं बनानी चाहिए। कर्म करना उपयोगी है, किंतु चिंता करना व्यर्थ है। समस्या के समाधान के लिए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिये।

अतीत से सीखें : हम अतीत में हुई अपनी गलतियों के प्रति सावधान रहें और भविष्य में उन्हें न दोहराने का संकल्प लें। जब हम उन्हें भुला देते हैं तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा को अन्य कार्यों में लगाकर बेहतर परिणाम पा सकते हैं। इससे हमारे समय की बचत होती है और वह समय हम ध्यान-अभ्यास में लगाकर शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं।

ज्ञान से मन हो आलोकित

ज्ञान-आलोक

पुस्तक : शिक्षा क्या है?
लेखक : जे कृष्णमूर्ति
अनुवादक : विनय कुमार वैद्य
प्रकाशन : राजपाल एंड संस



कुछ विषयों का अध्ययन कर अपनी जानकारी बढ़ा लेना या परीक्षा पास कर लेना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षित होने से तात्पर्य मन और मनुष्य जीवन में सामने आने वाले प्रश्नों का सही उत्तर जान लेने या ढूंढ लेने से है। प्रसिद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु जे. कृष्णमूर्ति ने अपनी किताब 'शिक्षा क्या है' में इसी की व्याख्या की है। यह अंग्रेजी किताब 'टॉक्स विद स्टूडेंट' का हिंदी अनुवाद है। इस किताब में रोजमर्रा के जीवन और दैनिक घटनाक्रमों से रूबरू होने पर जो मन में सवाल उठते हैं, उन्हें छात्रों द्वारा किया गया है। उनके जवाब ही जे. कृष्णमूर्ति ने अपने दृष्टिकोण से दिए हैं। भले ही प्रश्न शिक्षा के बहाने किए गए हों, लेकिन इसमें मनुष्य-मन और जीवन के प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे। इसमें भय, तुलना, पहल, सुरक्षा, आदत, महत्वाकांक्षा, परंपरा, ईर्ष्या, ताकत, अनुशासन, अपने मन को समझना, आनंद आदि को विस्तार से बताया गया है। इनके अलावा, धर्म क्या है और उनका पालन किस तरह करना चाहिए, इस बारे में भी पुस्तक में बताया गया है। यहां पर ज्ञान की क्या विशेषता होनी चाहिए, इसे भी लेखक ने समझाने की कोशिश की है। लेखक ने बताया है कि सतह पर जो हमें पानी दिखता है, मात्र उसे ही गंगा नदी समझ लेना हमारी भूल है। वास्तव में गंगा तो एक विशाल नदी है, जिसकी लंबाई उद्गम स्थल से लेकर वहां तक है, जहां वह सागर में मिलती है। इसी तरह शिक्षा और ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है। शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि मन का आलोकित होना भी है। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा सिर्फ बुद्धि या कौशल नहीं। प्रज्ञा वह है, जिसकी खोज आपने स्वयं की है। मानव मन की हर जिज्ञासा का समाधान जे. कृष्णमूर्ति ने दर्शन की अवधारणाओं, आध्यात्मिक संकल्पनाओं, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक रूप में शिक्षा पद्धति के मौजूदा सिद्धांतों से अलग हटकर किया है।

स्मिता सिंह

सप्ताह के पर्व-त्योहार



28 जुलाई : स्नान-दान-व्रतादि की पुष्य नक्षत्रयुता पौषी पूर्णिमा। शाकंभरी जयंती।
31 जुलाई : सौभाग्य सुंदरी व्रत।
2 अगस्त : श्रावण सोमवार व्रत। श्रीगुरु हरिकिशन जयंती।

आज का भविष्यफल

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थितिः 27 जुलाई, 2021 मंगलवार श्रावण मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी का राशिफल।
आज का राहुकालः दोपहर 03:00 बजे से 04:30 बजे तक।
आज का दिशाशूलः उत्तर।
विशेषः पंचक।
आज का पर्व एवं त्योहारः श्री गणेश चतुर्थी व्रत, मंगला गौरी व्रत।

मेषः भावुकता में नियंत्रण रखें। कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मानसिक कलेश मिले। अतः किसी मामले में हस्तक्षेप न करें और वाणी पर संयम रखें।

वृषः संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। आर्थिक और व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा।

मिथुनः किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। व्यावसायिक योजना को बल मिलेगा।

कर्कः चली आ रही समस्या का निदान होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा।

सिंहः व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव एवं वर्चस्व में वृद्धि होगी।

कन्याः दांपत्य जीवन सुखमय होगा। नई योजना फलीभूत होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। बुद्धि कौशल से किए गए कार्यों में आशातीत सफलता मिलेगी।

तुलाः शाही खर्च पर नियंत्रण करना होगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। भागदौड़ की स्थिति से बचें। रचनात्मक प्रयासों में सफलता मिलेगी।

वृश्चिकः आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। सम्मान में वृद्धि होगी। पारिवारिक संबंध मधुर होंगे।

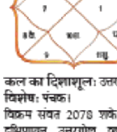
धनुः रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। दांपत्य जीवन सुखमय होगा।

मकरः निजी सुख में व्यवधान रहेगा। संतान और जीवनसाथी का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

कुंभः धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि का योग है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

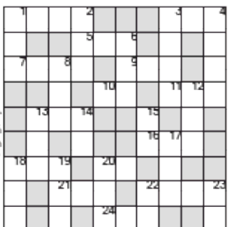
मीनः चली आ रही समस्या का समाधान होगा। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। व्यक्ति विशेष का सहयोग रहेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

कल 28 जुलाई का पंचांग



कल का दिशाशूलः उत्तर।
विशेषः पंचक।
विक्रम संवत 2078 शके 1943 दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु श्रावण मास कृष्ण पक्ष की पंचमी 26 घंटे 49 मिनट तक, तत्पश्चात् षष्ठी पूर्वभाद्रपद नक्षत्र 10 घंटे 45 मिनट तक, तत्पश्चात् उत्तरभाद्रपद नक्षत्र अतिगण्ड योग 20 घंटे 18 मिनट तक, तत्पश्चात् सुकर्मा योग मीन में चंद्रमा।

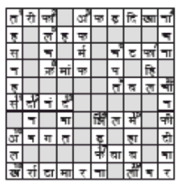
वर्ग पहेली-1649



बाएं से दाएं
1 [illegible] (4)।
3 खाने-पीने का सामान (3)।
5 [illegible] (3)।
7 [illegible] (4)।
9 अंग्रेज (3)।
10 [illegible] (2)।
11 [illegible] (3)।
13 [illegible] (3)।
16 [illegible] (3)।
18 [illegible] (3)।
20 [illegible] (2)।
21 [illegible] (3)।
22 [illegible] (4)।
24 [illegible] (3)।
25 [illegible] (3)।
26 [illegible] (4)।

ऊपर से नीचे
1 [illegible] (3)।
2 [illegible] (3)।
3 [illegible] (4)।
4 [illegible] (4)।
6 अनुकूल (3)।
8 [illegible] (3)।
12 [illegible] (3)।
13 [illegible] (3)।
14 [illegible] (2)।
15 [illegible] (2)।
17 [illegible] (3)।
18 [illegible] (4)।
19 [illegible] (4)।
20 [illegible] (3)।
22 [illegible] (3)।
23 [illegible] (3)।

कल का हल



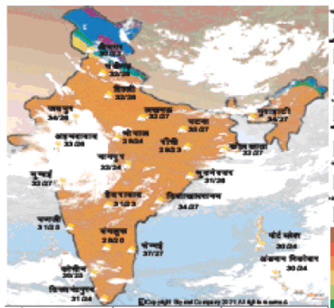
जागरण सुडोकू-1649

	3		4		6			1
1		2		5		4	9	
		5		1				3
	1			9		7		
2					7		3	
		3	5			1		9
	8		6		5		1	2
	5			3		9		
3		1		7			5	4

कल का हल

7	8	9	5	2	1	4	6	3
6	1	2	8	4	3	5	7	9
5	4	3	6	7	9	8	1	2
3	5	8	9	6	2	7	4	1
9	2	7	4	1	8	6	3	5
1	6	4	7	3	5	9	2	8
2	9	6	1	5	7	3	8	4
8	7	1	3	9	4	2	5	6
4	3	5	2	8	6	1	9	7

मौसम



पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व जम्मू में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा संभव है। कश्मीर व लद्दाख में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा होगी। राजस्थान में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा संभव है।

कल पढ़ें



जिंदगियां बचाने के लिए प्रयास आवश्यक

युद्ध बंदियों की सुरक्षा के लिए तीसरा जेनेवा कन्वेंशन

वर्ष 1929 में आज ही युद्ध बंदियों को लेकर जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। इसमें 97 आर्टिकल शामिल थे। 19 जून 1931 से यह नियम लागू हुए थे। इसमें बंदियों को युद्ध के बाद तुरंत रिहा करने का प्रविधान था। वर्तमान में 194 देश जेनेवा कन्वेंशन मानते हैं।





डायबिटीज के लिए इंसुलिन इंजेक्शन की मिली राह

वर्ष 1921 में आज ही चार्ल्स बेस्ट और डा फ्रेडरिक बैंटिंग ने पहली बार कुत्ते के पैंक्रियाज से इंसुलिन को अलग किया था। इसके बाद उसी पर इसे प्रयोग किया गया। 23 जनवरी, 1922 को इंसानों में पहली बार 14 साल के बच्चे को इसका इंजेक्शन दिया गया।

जसपाल ने जीता था विश्व निशानेबाजी में स्वर्ण पदक

वर्ष 1994 को आज ही जसपाल राणा ने इटली के मिलान शहर में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने 569/600 का रिकार्ड स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया था। इससे पहले 1978 में पहली बार निशानेबाजी में भारत को एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक मिला था। जसपाल को 1994 में अर्जुन पुरस्कार और यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह जसपाल राणा इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशनल एंड टेक्नोलाजी देहरादून में खिलाड़ियों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग देते हैं। वर्ष 2020 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।



सक्रिय जीवनशैली से कम करें खर्राटे का जोखिम

शोध ▸ अमेरिका में 1.3 लाख पुरुषों और महिलाओं पर किया गया 10 से 18 साल तक अध्ययन

यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल में प्रकाशित हुआ निष्कर्ष

वाशिंगटन, एएनआइ : सोते समय जोर-जोर से खर्राटा लेना एक सामान्य विकृति है। इसे मेडिकल साइंस की साइंस की भाषा में आब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्नीया (ओएसए) भी कहते हैं। ऐसा तब होता है जब नींद की स्थिति में गले की मांसपेशियों की शिथिलता के चलते श्वसन मार्ग आंशिक या पूर्ण रूप से अवरुद्ध होने लगता है। इससे हार्ट अटैक समेत कई प्रकार के हृदय रोग का भी खतरा होता है। इतना ही नहीं, खर्राटे लेने वाले लोगों के आसपास सोने वाले लोगों की भी नींद खराब होती है, जिससे वे परेशान होते हैं। लेकिन एक नए अध्ययन में बताया गया है कि सक्रिय जीवनशैली अपना कर इस विकृति के जोखिम को कम किया जा सकता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष से प्रभावित होकर अब डाक्टर भी इस विकृति के जोखिम वाले लोगों को बचाव के लिए व्यायाम (एक्सरसाइज) की सलाह देने लगे हैं।



रोगों से बचाता है शारीरिक श्रम। फाइल फोटो

अध्ययन का निष्कर्ष यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। बिग्रम और वुमेन्स हास्पिटल के शोधकर्ताओं ने सक्रिय जीवनशैली और ओएसए के बीच संबंधों का अध्ययन किया है। इसके तहत शोधकर्ताओं ने अमेरिका में करीब 1.3 लाख पुरुषों और महिलाओं का 10 से 18 साल तक फालोअप अध्ययन किया और पाया कि अधिक शारीरिक सक्रियता और स्थूल व्यवहार ओएसए के जोखिम से जुड़ा हुआ है।

बिग्रम में एसोसिएट एपिडेमियोलाजिस्ट तियानी हुआंग ने बताया- हमारे अध्ययन से पता चला कि अधिक शारीरिक सक्रियता और घर या आफिस में कम समय तक लगातार बैठने से ओएसए का जोखिम कम होता है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है लोग टीवी देखने या कंप्यूटर पर काम करने के लिए ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं। हुआंग के मुताबिक, इस अध्ययन से इस बात का संकेत मिलता है कि सक्रिय जीवनशैली से ओएसए के जोखिम की रोकथाम और इलाज दोनों में ही फायदा मिलता है। शोधकर्ताओं ने शारीरिक सक्रियता और स्थूल स्थिति की समयावधि को स्टैटिकल माडलिंग से तुलनात्मक अध्ययन कर ओएसए के डायग्नोसिस की कोशिश की।

इस दौरान सामान्य और अत्यधिक शारीरिक श्रम का अलग-अलग अध्ययन किया गया और ओएसए के संदर्भ में उसका विश्लेषण करने पर पाया गया कि इन दोनों ही स्थितियों में ओएसए का जोखिम कम तो होता है, लेकिन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। यद्यपि 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं, जिनका बाडी मास इंडेक्स (बीएमआइ) 25 केजी प्रति एम2 था, उनके मामले में इन कारकों का ज्यादा गहरा संबंध देखा गया।

बड़े सैंपल साइज से विश्वसनीय निष्कर्ष

हुआंग ने बताया कि यह पहला अध्ययन है, जिसमें शारीरिक सक्रियता और स्थूल व्यवहार का ओएसए के जोखिम का एकसाथ आकलन किया गया है। खास बात यह भी है कि इसका सैंपल साइज काफी बड़ा रखा गया। इस कारण कई अन्य कारकों को भी अध्ययन में शामिल किया जा सका और निष्कर्ष ज्यादा विश्वसनीय निकल सका। इसके लिए जुटाए गए आंकड़े अध्ययन में शामिल लोगों द्वारा खुद से दी गई रिपोर्ट से जुटाए गए थे। इसका फायदा यह हुआ कि सामान्य चिकित्सीय परीक्षण में जो हल्के ओएसए मामले पकड़ में नहीं आते, वे भी अध्ययन में शामिल किए जा सके।

हुआंग के मुताबिक, शोध के अगले चरण में एक्टिग्राफी, होम स्लीप एप्नीया टेस्ट और पालीसोमनोग्राफी से भी डाटा जुटाए जाएंगे। लेकिन अभी तक के निष्कर्षों के आधार पर शोधकर्ताओं ने डाक्टरों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि वे ओएसए का जोखिम कम करने के लिए लोगों को शारीरिक सक्रियता के फायदे से अवगत कराएं।

उन्होंने बताया कि हमने पाया कि शारीरिक सक्रियता और स्थूल व्यवहार स्वतंत्र रूप से ओएसए जोखिम से जुड़े हैं। इसलिए जो लोग रोजाना ज्यादा देर तक बैठते हैं, वे भी खाली समय में शारीरिक श्रम या सक्रियता बढ़ाकर ओएसए का जोखिम कम कर सकते हैं।

इसी प्रकार जो लोग शारीरिक कमजोरी की वजह से ज्यादा श्रम नहीं कर सकते, वे ज्यादा देर तक बैठने में कमी लाकर या खड़े होकर या हल्के श्रम से भी ओएसए का जोखिम कम कर सकते हैं। हालांकि स्थूल स्थिति में कमी लाने के साथ ही शारीरिक श्रम बढ़ाने से ज्यादा फायदा होगा।



अल्फार्न फेस्टिवल...

स्विट्जरलैंड के नेंदाज में 20वां अंतरराष्ट्रीय 'अल्फार्न फेस्टिवल' मनाया गया। इसमें कई समूहों के रूप में लगभग 120 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पाइप के आकार जैसा दिखने वाले इस वाद्य यंत्र को आकर्षक पहनावे के साथ ऊंची ध्वनि में बजाने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। इस पारंपरिक उत्सव में इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फार्न वाद्य यंत्र का प्रयोग प्राचीन काल में चरवाहों द्वारा अपने पशुओं को बुलाने के लिए किया जाता था, जो अब एक पारंपरिक उत्सव में बदल गया है। एपी

कोरोना की गंभीरता के खतरे को भांपने का तरीका ईजाद

अनुसंधान



समय रहते पता चलेगा जोखिम। फाइल फोटो

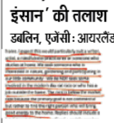
कोरोना वायरस (कोविड-19) की चपेट में आने वाले लोगों में संक्रमण के गंभीर होने के खतरे को भांपने के लिए एक नया तरीका ईजाद किया गया है। एक नए अध्ययन के अनुसार, संक्रमण के प्रारंभिक दौर में शरीर के एंटीवायरल रिस्पांस से कोरोना के गंभीर होने के खतरे का अनुमान लग सकता है। इससे कोरोना संक्रमण को गंभीर होने से रोका जा सकता है।

अमेरिका के मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी (एमआइटी) और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह विश्लेषण किया कि क्या अनुमान से बहुत पहले ही संक्रमण गंभीर होना शुरू हो जाता है या नहीं। शोधकर्ताओं के अनुसार, संभवतः यह दौर उसी समय शुरू हो जाता है, जब कोरोना वायरस नाक में प्रवेश करता है। यहीं पर इस वायरस से मुकाबले के लिए प्रारंभिक रिस्पांस होता है। उन्होंने यह निष्कर्ष कोरोना पीड़ितों के नेजल स्वैब के नमूनों में सेल्स (कोशिकाओं) के अध्ययन के आधार पर निकाला है। ये नमूने कोरोना संक्रमण के प्रारंभिक दौर में लिए गए थे। इनमें से कई पीड़ितों में बाद में संक्रमण गंभीर हो गया था। सेल पत्रिका में प्रकाशित किए गए अध्ययन के मुताबिक, जिन पीड़ितों में कोरोना संक्रमण गंभीर हुआ था, उनकी कोशिकाओं में एंटीवायरल रिस्पांस बहुत अधिक पाया गया। शोधकर्ता ने कहा, 'नतीजों से जाहिर होता है कि शरीर के प्रारंभिक एंटीवायरल रिस्पांस से कोरोना के गंभीर होने के खतरे का अनुमान पहले ही लग सकता है। इससे संक्रमण को गंभीर होने से रोकने का नया रास्ता निकल सकता है।' -प्रेट

इधर-उधर की

किराएदार के तौर पर 'सही इंसान' की तलाश

डबलिन, एजेंसी : आयरलैंड की राजधानी डबलिन में एक मकान मालिक का अनोखा विज्ञापन वायरल हो रहा है। उसने यहां की हाउसिंग वेबसाइट पर दिए विज्ञापन में किराएदार रखने के लिए कुछ अनोखी शर्तें दी हैं। उसकी शर्त है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो व्यवहार व आदतों में उसके बाकी के तीन किराएदारों जैसा ही हो। लेखक, कलाकार या घर से पढ़ाई कर रहे व्यक्ति को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है।



खूब वायरल हो रहा है विज्ञापन। इंटरनेट मीडिया

अल्जाइमर : टुकड़ों में गुम होती हैं यादें

अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है, जो व्यक्ति की याददाश्त को प्रभावित करती है। अल्जाइमर के नाम से लोगों में एक डर बैठ जाता है। दुकान में खरीदारी करते समय कोई सामान भूल जाना भी इसका लक्षण हो सकता है। कनाडा की मांट्रियल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं स्वेन जोबर्ट, एमिली डेलेग और इसाबेल ने इस संबंध में कुछ बातों को स्पष्ट किया है।



दो तरह की होती है याददाश्त

याददाश्त की बात करते समय हमें समझना होगा कि हमारी हर याददाश्त एक-दूसरे से जुड़ी नहीं होती है। इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं और दिमाग उन्हें अलग-अलग तरह से नियंत्रित करता है।

- **एपिसोडिक मेमोरी :** इसमें ऐसी यादें होती हैं, जो किसी समय से जुड़ी हैं। बचपन की यादें, पहली बार चलने की यादें, हमारी सर्वश्रेष्ठ छुट्टियां, किसी वीकेंड में बिताया कोई पल या सुबह के नाश्ते से जुड़ी यादें इसमें शामिल होती हैं। इन यादों के लिए हमें किसी समय, जगह या व्यक्ति के बारे में सोचना होता है।
- **सिमेंटिक मेमोरी :** इसमें किसी जगह या समय को याद रखने की जरूरत नहीं होती। यह हमारी रोजाना की जिंदगी में सीखी गई बातें होती हैं, जैसे किसी अभिनेता की पत्नी का नाम, उसकी सुपरहिट फिल्म का नाम आदि।

अल्जाइमर ऐसे लगाता है सेंध

अल्जाइमर के लक्षणों की शुरुआत 10-12 साल पहले से होने लगती है। शुरुआत में व्यक्ति की सिमेंटिक मेमोरी कम होने लगती है। व्यक्ति छोटी-छोटी बातें भूलने लगता है। गंभीर होने पर पुराने यादें धुंधली होने लगती हैं। हालांकि शोधकर्ताओं ने उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त को लेकर लोगों में बेवजह चिंता को अनावश्यक बताया है। उनका कहना है कि कई बार कुछ बातें भूल जाना सामान्य होता है। किताबें पढ़ना और पहेलियां सुलझाना आदि ऐसे कदम हैं, जिनसे दिमागी सेहत को सही रखने में मदद मिलती है। इस बीमारी के लिए अव्यवस्थित जीवनशैली, तनाव, समेत पोषण संबंधी फैक्टर विटामिन बी की कमी को भी जिम्मेदार माना जाता है।



ऐसे काम करता है दिमाग

एपिसोडिक मेमोरी को संभालने का काम दिमाग का हिप्पोकैंपी हिस्सा करता है। यह हिस्सा दिमाग के बीच में होता है। फ्रंटल लोब इन यादों को संगठित करता है। दूसरी ओर, सिमेंटिक मेमोरी को संभालने का काम पैराहिप्पोकैंपल हिस्सा करता है। (इनपुट : प्रेट्र)

स्क्रीन शॉट

पठान फिल्म में जबरदस्त एक्शन करेंगी दीपिका पादुकोण

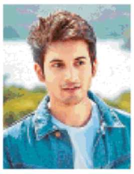


हालीवुड फिल्म में भी दीपिका दिखा चुकी हैं एक्शन का जलवा।

हिंदी फिल्मों में अभिनेत्रियों को एक्शन करने का मौका कम ही मिलता है। कई फिल्में कर चुकीं दीपिका पादुकोण भारतीय दर्शकों के सामने पहली बार फिल्म पठान में एक्शन करेंगी। हालांकि इससे पहले दीपिका हालीवुड फिल्म ट्रिपल एक्स : रिटर्न आफ जेंडर केज में एक्शन का जलवा दिखा चुकी हैं। फुल स्पलिट्स से लेकर हथियारों से खेलना और गुंडों के साथ लड़ाई तक उन्होंने हर तरह का एक्शन फिल्म में दिखाया था। दीपिका का वह अनुभव पठान फिल्म में काम आएगा। दीपिका के करीबी सूत्रों की माने तो वह फिलहाल पठान के लिए खतरनाक एक्शन दृश्यों की शूटिंग कर रही हैं। इन एक्शन सीन्स की शूटिंग मुंबई में ही हो रही है। दीपिका पूरी तैयारी के साथ सेट पर स्टंट करने के लिए उतरी हैं। लाकडाउन में मिली ढील के बाद दीपिका दो फिल्मों पर एक साथ काम करने में व्यस्त हैं। दीपिका ने पहले ही पठान और शकुन बत्रा की फिल्म का एक शेड्यूल पूरा कर लिया था। उनकी आगामी फिल्मों में इन दो फिल्मों के अलावा अभिनेता प्रभास के साथ नाग अश्विन की फिल्म, हालीवुड की हिंदी रीमेक फिल्म द इंटर्न, महाभारत, 83 और फाइटर शामिल हैं।

मम्मी-पापा के हाथ-पैर जोड़ने के बाद मिला था पहला लैपटाप : रोहित सराफ

सितारों को देखकर यही लगता है कि उनके लिए जीवन में सब कुछ आसान रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लूडो, द स्काइ इज पिंक जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके रोहित सराफ आज भले ही प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन उनका बचपन आम बच्चों की तरह ही रहा है। अब भी रोहित सोच समझकर ही पैसे खर्च करना पसंद करते हैं। एक लाइव चैट के दौरान रोहित ने कहा कि पहला लैपटाप मुझे पांच साल पहले ही मिला है, जिसके लिए मुझे अपने मम्मी-पापा के हाथ-पैर जोड़ने पड़े थे। मेरा पूरा बचपन स्कूल और ट्यूशन्स के बीच बीता है। उस वक्त भी मैं मम्मी-पापा से लैपटाप मांगता था, ताकि उस पर गेम खेल सकूं, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। पांच साल पहले जब उन्हें लगा कि मुझे वाकई में अब काम के लिए लैपटाप की जरुरत है, तब जाकर उन्होंने खरीदा। बचपन में भी चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म वेक अप सिड देखने के बाद मुझे लगा था कि अब मुझे फोटोग्राफर बनना है। मैंने मम्मी-पापा से कैमरा मांगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कैमरा मिला था। अब खुद कमा रहा हूं, तो समझ सकता हूं कि पैसों की क्या अहमियत होती है। मैं सोच समझकर पैसे खर्च करता हूं। वही चीजें खरीदता हूं, जो बहुत जरूरी हैं। अपनी पहली कमाई से मैंने फोन खरीदा था, जो अब भी इस्तेमाल कर रहा हूं।



सोच समझकर पैसे खर्च करते हैं रोहित।

कोरोना की दूसरी लहर थमने पर सितंबर से मुंबई में शुरू होगी पिप्पा की शूटिंग

ईशान खट्टर, मृणाल ठाकुर और वेब सीरीज मिर्जापुर 2 फेम अभिनेता प्रियांशु पेन्युली अभिनीत फिल्म पिप्पा की शूटिंग की तैयारियां एक बार फिर से जोरों पर हैं। राजा कृष्ण मेनन के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग पहले मार्च में शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से बिगड़ी परिस्थितियों के कारण निर्माताओं ने मार्च में शूटिंग शुरू करने की योजना रद कर दी। अब करीब चार महीने बाद इस फिल्म की शूटिंग की तैयारियां एक बार फिर से जोरों पर है। फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, फिल्म से जुड़ी टीम को यह सूचित कर दिया गया है कि फिल्म की शूटिंग सितंबर महीने से शुरू हो जाएगी। साल 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान की युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित होने के कारण इस फिल्म के लिए अलग-अलग स्तर की तैयारियों की जरूरत है। सभी कलाकार अगस्त के शुरुआत से ही अपने-अपने किरदारों की शारीरिक तैयारियों में जुट जाएंगे। शूटिंग शुरू करने से पहले फिल्म की टीम युद्ध के दृश्यों का रिहर्सल भी करेगी। पिप्पा ब्रिगेडियर बलराम द्वारा लिखी किताब द बर्निंग चाफीस पर आधारित है। ब्रिगेडियर बलराम साल 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 45वें कैवलरी टैंक स्क्वाड्रन का हिस्सा रहे और उन्होंने इस युद्ध में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म में ईशान, ब्रिगेडियर बलराम तथा प्रियांशु उनके भाई का किरदार निभा रहे हैं।



पिप्पा में ब्रिगेडियर बलराम मेहता का किरदार निभाएंगे ईशान खट्टर।

अगस्त से शुरू होगा एमटीवी सुपरमाडल आफ द ईयर सीजन 2

साल 2019 में शुरू हुए धारावाहिक एमटीवी सुपरमाडल आफ द ईयर के दूसरे सीजन का प्रसारण अगस्त से एमटीवी पर किया जाएगा। माडलिंग की दुनिया में अपना भविष्य तलाश रही युवा लड़कियों को एक मंच मुहैया कराने वाले इस शो के दूसरे सीजन की थीम अनएपोलाजिकली यू होगा। जिसके तहत यह दिखाया जाएगा कि कैसे किसी दूसरे की टिप्पणियों या आलोचनाओं से प्रभावित हुए बिना कोई अपनी जिंदगी अपने पसंद के फैशन के साथ जी सकता है। इस सीजन में अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा और अभिनेता मिलिंद सोमन एक बार फिर से जज की कुर्सी संभालेंगे। पहले सीजन में तीसरी जज रही मसाबा गुप्ता इस बार शो का हिस्सा नहीं होंगी, उनकी जगह शो के पहले सीजन में बतौर मेंटर जुड़ी अनुषा दांडेकर तीसरी जज होंगी। इस सीजन के बारे में मलाइका ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि इस शो का पहला सीजन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। दूसरे सीजन में उससे कहीं ज्यादा रोमांच होगा। यह सीजन फैशन की दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले सभी दर्शकों के लिए खास उपहार की तरह होगा। वहीं तीन अगस्त से जी टीवी पर शुरू होने जा रहे धारावाहिक भाग्य लक्ष्मी में अभिनेत्री स्मिता बंसल एक उच्च वर्गीय महिला नीलम ओबेराय के किरदार में नजर आएंगी। ऐश्वर्या खरे और रोहित सुचंती की मुख्य भूमिका वाले इस धारावाहिक में स्मिता का किरदार नायक ऋषि की मां और एक जिम्मेदार पत्नी का होगा। यह धारावाहिक सीमित संसाधनों में रहकर भी दूसरों के काम आने वाले लड़की लक्ष्मी की कहानी है।



सुपरमाडल आफ द ईयर के दूसरे सीजन में जज की कुर्सी पर होंगी मलाइका अरोड़ा

(सभी फोटो इंस्टाग्राम से)



शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार में होंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा • इंस्टाग्राम

शेरशाह फिल्म सेना के जवानों के त्याग को दिखाती है। इसमें विक्रम बत्रा की लव स्टोरी, पर्सनल लाइफ भी देखने को मिलेगी।

पापा खुश हैं कि कहीं तो फौजी बना : सिद्धार्थ

इन दिनों कारगिल में अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी फिल्म शेरशाह का प्रमोशन कर रहे हैं। फिल्म में सिद्धार्थ कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाएंगे। यह फिल्म कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक होगी। दैनिक जागरण से बातचीत में सिद्धार्थ ने बताया कि सेना के नायकों पर फिल्में बननी चाहिए। वह कहते हैं कि हमने इस उद्देश्य से फिल्म बनाई है कि आम जनता इस बात को समझे कि सेना का जवान बनना कितना मुश्किल काम है, कितना बड़ा त्याग करना पड़ता है। हम बड़े शहरों में रहकर जो आजादी का मजा ले रहे हैं, वह हमारे जवानों की बदौलत है। भारतीय सेना दुनिया की बेहतरीन सेना है। हमारे पास जो तकनीक है, जवानों का जज्बा है, वह दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर आता है। मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से हूं। मेरे दादा भारतीय सेना में थे। मेरे पापा भी सेना में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मर्चेंट नेवी में काम मिला। पापा खुश हैं कि फिल्मों में सही, लेकिन मैं फौजी तो बना। बार्डर, लक्ष्य जैसी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूं, लेकिन शेरशाह इन फिल्मों से अलग है, क्योंकि यह एक बायोपिक है। कैप्टन विक्रम बत्रा की लव स्टोरी, उनकी पर्सनल लाइफ, कारगिल में जिस साहस से वह लड़े हैं, सब इस फिल्म का हिस्सा होगा। नए तरह की वार फिल्म है, जो रील और रियल के बीच संतुलन रखेगी। फिल्म शेरशाह 12 अगस्त को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।

सुस्वागतम में दिखेगा लव ट्रायंगल

गत मार्च में रिलीज हुई फिल्म टाइम टू डांस से हिंदी सिनेमा में पदार्पण करने वाली अभिनेत्री और कट्रीना कैफ की बहन इसाबेल कैफ की दूसरी फिल्म सुस्वागतम खुशामदीद है। इस फिल्म में वह अभिनेता पुलकित सम्राट और साहिल वैद्य के साथ काम कर रही हैं। इस फिल्म के बारे में दैनिक जागरण से बातचीत में साहिल बताते हैं, 'सुस्वागतम खुशामदीद में मैं, पुलकित और इसाबेल तीनों ही लीड किरदार में हैं। इस फिल्म की कहानी बहुत दिलचस्प है, लेकिन अभी इसकी शूटिंग पूरी नहीं हुई है। इस फिल्म के आधे हिस्से की शूटिंग बाकी है। इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हमने मुंबई में की थी। उसके बाद हमने दिल्ली और आगरा में इसकी शूटिंग की। बाकी बचे हुए हिस्सों को हमें मुंबई में शूट करना था, जो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से नहीं हो पाया। इस फिल्म में इसाबेल के साथ मेरा एक गाना भी है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक कंफ्यूजन की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि इसाबेल का किरदार नूर, पुलकित के किरदार अमन के साथ है या मेरे किरदार चांद के साथ। मुझे यकीन है इस कंफ्यूजन और रोमांस को देखने में दर्शकों को बहुत मजा आएगा।' धीरज कुमार के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की रिलीज के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। साहिल आगामी दिनों में फिल्म सत्यमेव जयते 2 में भी नजर आएंगे।



सुस्वागतम खुशामदीद फिल्म से साहिल को हैं बड़ी उम्मीदें • इंस्टाग्राम

साथ दिखेंगे शाह रुख-काजोल

हिंदी सिनेमा में अभिनेता शाह रुख खान और अभिनेत्री काजोल ने एक साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाजीगर और कुछ कुछ होता है जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। सिनेप्रेमी जल्द ही इस जोड़ी को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। खबर है कि फिल्मकार राजकुमार हिरानी की अगली सोशल कामेडी फिल्म में शाह रुख और काजोल की जोड़ी एक बार फिर बन सकती है। इस फिल्म की कहानी पंजाब और कनाडा के बीच एक परिवार के अप्रवासन के इर्द-गिर्द होगी। इस फिल्म को लेकर पिछले काफी दिनों से शाह रुख की राजकुमार के साथ बातचीत चल रही है। फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, शाह रुख से इस फिल्म के लिए स्वीकृति मिलने के बाद राजकुमार ने इस फिल्म में शाह रुख के किरदार की पत्नी के लिए अभिनेत्री काजोल से बातचीत की है। काजोल की तरफ से भी सकारात्मक जवाब मिला है। इसके अलावा राजकुमार ने अन्य किरदारों के लिए अभिनेत्री तापसी पन्नू और विद्या बालन से भी संपर्क किया है। हालांकि दोनों अभिनेत्रियों की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। मनोज बाजपेयी और बमन ईरानी के भी अहम भूमिकाओं में होने की खबरें हैं। सब कुछ सही रहा तो शाह रुख के साथ यह काजोल की आठवीं फिल्म होगी, अगले साल अप्रैल में शूटिंग शुरू करने की योजना बना रहे हैं हिरानी।



राजकुमार हिरानी की फिल्म को स्वीकृति दे चुके हैं शाह रुख • इंटरनेट मीडिया

अब गुरु रंधावा ने बढ़ाया अभिनय की दुनिया की ओर कदम

सोनू निगम, दिलजीत दोसांझ जैसे कई गायक हैं, जो अभिनय की दुनिया में अपने हाथ आजमा चुके हैं। अब इसमें गायक गुरु रंधावा का नाम भी जुड़ गया है। गुरु एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म से बालीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। फिल्मों में अपने डेब्यू को लेकर गुरु ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि पहले भी मुझे पंजाबी फिल्मों के लिए कई आफर्स मिल चुके हैं। मेरा मानना है कि सही समय पर ही हर काम होता है। मुझे लगता है कि यह सही समय है कि पंजाबी और बालीवुड की फिल्मों में एक्टिंग की जाए। मैंने अपने करियर की शुरुआत एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर की थी। अपने सभी गानों के वीडियो में मैंने एक्टिंग की है। एक्टिंग करने के सपने को म्यूजिक वीडियो के जरिए पूरा करता आया हूं। तीन मिनट के वीडियो में अलग-अलग तरह के किरदार निभाने पड़ते हैं। फिल्मों में अभिनय करने को लेकर जो सबसे बड़ा अंतर होगा, वह उसकी अवधि को लेकर होगा। हालांकि मेहनत तो हर जगह करनी होती है। मैंने वीडियो में कई बड़े पर्दे की अभिनेत्रियों के साथ काम किया है, ऐसे में उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। फिल्म भले ही म्यूजिकल ड्रामा है, लेकिन मैं इसे कंफर्ट जोन नहीं मनाता हूं। मैं खुद को किसी एक जानर तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं। जिस तरह से अपने गानों के जरिये फैंस का मनोरंजन करता आया हूं, उसी तरह अपनी फिल्मों से भी करना चाहता हूं। इस फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं किया गया है। फिल्म की शूटिंग इस साल शुरू होगी।



म्यूजिकल ड्रामा फिल्म से गुरु कर रहे हैं डेब्यू • पीआर टीम

Vikas Divyakriti Sir Hindi literature Full Course

Year - 2020-21
Total - 157 Video lectures + 20 Booklet Pdf

👉(Real Price - 40000/-)
👉We Provide only ₹1499 ✅

दृष्टि The Vision

Contact on Telegram 👉 @prakashstudy24

